Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 5

शुक्रवार,
दिनांक 19 मार्च, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

[राजस्व, कृषि, आयुर्वेद, उद्योग विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हंसराज आर्य।

गंगानगर जिले की तहसीलों में पैमाइश का कार्य

38. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की तहसीलों की पैमाइश हुए काफी समय गुजर चुका है लेकिन अभी तक पैमाइश के कागजात राजस्व तहसीलों को नहीं सौंपे गये हैं ?

(2) क्या भविष्य में पैमाइश के कागजात राजस्व विभागों में शीघ्र चले जायेंगे ?

(3) यदि हां, तो कब तक ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि सभी तहसीलों के रजिस्टर इन्तकाल पैमाइश विभाग के पास चले गये हैं ?

(6) क्या यह सही है कि रजिस्टर इन्तकाल के चले जाने से हर एक किसान के सामने एक कठिनाई आ गई है ?

(7) क्या यह भी सही है कि रजिस्टर इन्तकालात राजस्व तहसीलों में नहीं होने के कारण विरासतन इन्तकाल भी रुक गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(1) जी हां।
(2) जी हां।
(3) जल्दी से जल्दी भेजे जायेंगे।
(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
(5) जिन तहसीलों में बन्दोबस्त कार्यवाहियां चल रही हैं उनके इन्तकाल रजिस्टर बन्दोबस्त विभाग में आये हुये हैं।
(6) इससे कोई कठिनाई नहीं आती है।
(7) यह सही नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन तहसीलों में पैमाइश हुये

Page No 2

(श्री हंसराज आर्य)
8-10 साल हो चुके हैं उनके कागजात राजस्व विभाग में क्यों नहीं आये ?

श्री रामकिशोर व्यास : फाइनेलाइज नहीं हुये हैं। बाद में मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई और संशोधन करना पड़ा।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय घोषणा को एक साल हो चुका है। एक महीने में एक तहसील हो सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : सेटिलमेंट का सारा प्रोसेस वापिस शुरू किया गया था।

श्री हंसराज आर्य : अब यह कब तक पूरा हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे ही पास बुक्स बट जायेंगी।

श्री हंसराज आर्य : जैसे से आपका मतलब ? समय बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : बुक्स बट जाने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री हंसराज आर्य : जैसे से आपका मतलब क्या है ? 2 साल, 4 साल, 5 साल

श्री रामकिशोर व्यास : पर्चे नहीं बटेंगे तब तक कैसे हो सकता है सेटलमेंट रूल्स के अन्दर डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद रेकार्ड भेजा जाता है।

श्री हंसराज आर्य : लाखों की संख्या में जमा हो चुके हैं। इसका मतलब तो यह है जिस आदमी के पास पैसे होते है वहां तो हो जायेगा और जिसके पास पैसे नहीं है, वहां नहीं होगा ····

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो कायदा है।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी। श्रीमती मदन कौर।

नल कूप खोदने का आधार

39. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किसी भी स्थान पर नल कूप का बोरिंग किन आधार पर किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि काफी संख्या में नल कूप गहराई तक खोदे जाने के बाद, जल के अभाव में अथवा हानिकारक जल के कारण बन्द कर देने पड़ते हैं ?

(3) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि केन्द्रीय मरु प्रदेश अनुसन्धान शाला, जोधपुर के पास सेसमिक सर्वे एवं अर्थक्वेट मैथड से सर्वे करने के ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं जिनके द्वारा भू-तल में जल की गहराई, जल की मात्रा एवं जल में घुले कैमिकल कान्टेन्टस का सही सही पता लगाया जा सकता है ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसा संयन्त्र पश्चिमी क्षेत्र के लिये उपलब्ध करा कर समस्त क्षेत्र का भूतल जल की दृष्टि से सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ?

उप मंत्री (श्री खेतसिंह) : नलकूप कृषकों अथवा अन्य संस्थाओं की मांग के आधार पर अग्रिम राशि जमा होने पर बनाया जाता है। अगर संस्था चाहती है तो उस स्थान का प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी कर दिया जाता है।

(श्री खेतसिंह)

(2) हां, यह सही है कि कुछ नलकूप काफी गहराई तक खोदे जाने के बाद जल-युक्त स्ट्रेटा न मिलने के कारण अथवा हानिकारक जल के कारण बन्द कर देने पड़ते हैं।

(3) इस विभाग को यह जानकारी है कि केन्द्रीय मरु अनुसंधान शाला, जोधपुर के पास सेसमिक सर्वे यन्त्र उपलब्ध हैं। इस यंत्र द्वारा विभिन्न चट्टानों के कान्टेन्ट्स मालूम किये जा सकते हैं। जल की मात्रा व केमिकल्स का पता नहीं लगाया जा सकता।

(4) उपरोक्त यंत्र भू-जल मण्डल के पास हाल ही में प्राप्त हुआ है, तथा इसका उपयोग राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भू-भौतिक सर्वेक्षण के लिये किया जायेगा।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान सरकार की जानकारी में है जोधपुर शहर के 10 मील के घेरे में केन्द्रीय मरु प्रदेश अनुसंधान शाला, जोधपुर नलकूपों के लिये सर्वे किया गया था और जल की मात्रा और जल की गहराई का भी पता लगाया गया था और वह सही उतरा था।

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। यह मेरी नालेज में नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : क्या आप पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसा यंत्र जोधपुर के पास है।

श्री खेतसिंह : वह तो मैंने प्रश्न में बताया है। अब भू-तल जल मण्डल के पास भी यह यंत्र उपलब्ध हो चुका है।

श्रीमती मदन कौर : प्रश्न 4 के जवाब में बताया गया है कि प्राथमिक सर्वे का यंत्र उपलब्ध हो गया है और उससे सर्वे कराने का काम लिया जायगा। सारे राजस्थान का सर्वे कब तक करा लिया जायगा ?

श्री खेतसिंह : यह हाल ही में प्राप्त हुआ है और दो साल की अवधि में पश्चिमी क्षेत्र का सर्वे करा लिया जायगा।

श्रीमती मदन कौर : लोग पानी के बिना मर रहे हैं, खारा पानी पी रहे हैं और इससे कई तरह की बिमारियां फैल रही हैं आप कह रहे हैं दो साल में सर्वे का काम पूरा हो जायगा।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : यू. जी. डब्ल्यू. बी. का सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री खेतसिंह : आप बताते हैं वह भी सही है। कुछ स्थानों का सर्वेक्षण किया है। जैसा प्रश्नकर्ता ने कहा है काफी ऐसे गांव हैं जहां खारा पानी है और वहां का सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। प्राथमिकता हम उन गांवों को पहले देंगे और अच्छा यह हो माननीय सदस्य गण भी उन इलाकों के नाम हमारे पास भेज दें तो सर्वेक्षण पहले करा लिया जायगा।

श्री बालसिंह सोढा : यू. जी. डब्ल्यू. बी. ने विभाग को सर्वेक्षण की रिपोर्ट दे दी है।

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है और इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : प्रश्न संख्या दो में बताया गया है, यह कौनसा आधार है किस आधार पर यह बताया गया है। ट्यूब

(श्री बालसिंह सोढा)
वेल्स तय करने के पाइन्ट कौन कौन से हैं जो विभाग द्वारा खोदे गये हैं ?

श्री खेतसिंह : यह दूसरा प्रश्न है। जब यह प्रश्न पूछे तो सप्लीमेंटरी पूछ लेना।

श्री बालसिंह सोढा : इसी में है। आप पढ़ लीजिए।

श्री खेतसिंह : वह तो मैंने जवाब दिया है उससे ही मालूम हो जाना चाहिये था। नल कूप अन्य संस्थाओं के आधार पर बनाये जाते है।

श्री बालसिंह सोढा : जो नल कूप विभाग ने बनाये हैं वे किस पाइन्ट के आधार पर बनाये हैं ?

श्री खेतसिंह : कोई भी संस्था या इन्डीवीज्युअल पैसा जमा कराता है कि हमारे फलां जगह बोरिंग कर दीजिये तो वहां हम कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बिना किसी संस्था और बिना किसी इन्डीज्युअल के पूछे ट्यूब वेल्स खुदवाये हैं ?

श्री खेतसिंह : यह सवाल नहीं है। हमने फेमिन में खोदे हैं और वह भी पैसे दिये गये हैं तब खोदे हैं। हमारा कामर्सियल डिपार्टमेंट है।

श्री भैरोंसिंह : कोई सामाजिक संस्था या व्यक्ति आपके विभाग में रुपया जमा नहीं कराते हैं। वह तो किसी दूसरे विभाग को ही पैसे जमा कराता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री खेतसिंह : पी. एच. डी, डिपार्टमेंट अपने निर्णय के अनुसार कोई योजना चालू करना चाहता है तो वह हमको पाइन्ट्स बता देते हैं वहां पर हम कुये खुदवाते हैं। वे फन्ड्स डाइवर्ट कर देते हैं तभी जाकर . . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी गैर सरकारी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने एक ट्यूब वेल नहीं खुदवाया है।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

ग्राम कोटडी में भूमि का अलाटमेन्ट

40. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटडी में जब से भूमि का अलाटमेंट शुरू हुआ है सैकड़ों व्यक्तियों को गलत रूप से जमीन अलाट की गई है ?

(2) यदि सही है तो क्या जिलाधीश, भीलवाड़ा ने इसकी जांच भी करवाई है ? यदि करवाई है तो कब और किस वर्ष से किस वर्ष तक के अलाटमेंट की ? जितने वर्षों की जांच कराई हो और उनमें जितने भी पंचायतवार गलत अलाटमेंट पाये गये हों उनकी पूरी फहरिश्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या जितने भी गलत अलाटमेन्ट हुए उन्हें जिलाधीश ने खारिज किये हैं ? यदि नहीं किये गये हैं तो क्यों ? क्या जल्दी

Page No 5

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
ही गलत अलाटमेंट खारिज होंगे ? यदि होंगे तो कब तक ?

(4) क्या इस प्रकार प्राप्त की गई जमीन भूमिहीनों को तुरन्त अलाट हो सकेगी ?

राजस्व मंत्री, (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) पंचायत समिति कोटडी के क्षेत्र में कुछ मामलों में गलत अलाटमेन्ट हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

(2) सन् 1965 से 1969 तक हुए आवंटन की प्रारम्भिक जांच करवाई गई है। प्रारम्भिक जांच के अनुसार 577 मामले गलत अलाटमैन्ट के पाये गये हैं। पंचायतवार सूची तैयार की जा रही है।

(3) संबंधित अलाटीज को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही यह निर्णय लिया जायेगा कि अलाटमेन्ट गलत है या नहीं तथा गलत निर्णय होने पर ही अलाटमेन्ट खारिज किया जायेगा। अलाटीज को नोटिसेज देने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) अलाटमेन्ट जो गलत पाये जायेंगे, को खारिज कर भूमि को पुन: ग्रहण की जाकर शीघ्र ही भूमिहीनों को आवंटन करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कितना समय लग जायेगा ? क्योंकि भूमिहीन तो बेचारे तरस रहे हैं और 65 से किया है इसलिए 500 पाये गये हैं और भी कई हजार पाये जाते। तो इस पर कार्यवाही कम्पलीट करके कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री राम किशोर व्यास : कार्यवाही की गयी है आखिर जिनको अलाटमेन्ट हुआ है उनको सुनना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उसमें समय कितना लगेगा ?

श्री राम किशोर व्यास : वह तो कह नहीं सकता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसका मतलब यह है कि जो भूमिहीन हैं उनको भूमि नहीं मिलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जमीन कहीं चली थोड़े ही जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

मरु विकास बोर्ड

41. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मरू विकास बोर्ड की केन्द्रीय सरकार की ओर से कब स्थापना की गई ?

(2) उक्त बोर्ड ने रेगिस्तान के विकास के लिये विभिन्न जिलों में क्या योजना बनाई ? संक्षेप में विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजनाओं का कहां कहां किस प्रकार क्रियान्वयन किया गया ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से

(श्री हरिसिंह)
संबंधित है और इस कारण इस क्वेश्चन को ड्राप कर दिया जाये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह प्रश्न कृषि विभाग से संबंधित है केन्द्रीय सरकार से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन्फर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि यह राजस्थान के डेजर्ट के डवलपमेन्ट का सवाल है।

श्री हरि सिंह : बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पहले बना था लेकिन अब जोधपुर में एरिड जोन रिचर्स इन्सटीट्यूट कार्य कर रहा है।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय वह विभाग जो केन्द्र से ताल्लुक रखते हैं जैसे रेल्वे टेलीफोन वगैरह तो उनके बारे में भी यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं पूछे जाते हैं।

नेक्स्ट.

प्रश्न संख्या 42

श्री लादूराम सुलानिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदन कौर.

बाड़मेर जिले के नलकूप

13. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन वर्षों में बाडमेर जिले में कितने नलकूप विभिन्न विभागों के माध्यम से खोदे गये ?

(2) ये नलकूप किन किन स्थानों पर खोदे गये और प्रत्येक की कितने गैलन पानी प्रति घन्टा देने की क्षमता है ?

(3) क्या इन नलकूपों के पानी का पूरा उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं तो किन किन स्थानों पर और क्यों ?

उपमन्त्री (श्री खेतसिंह) :

(1) गत 3 वर्षों में बाडमेर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा 16 नलकूप खोदे गये।

(2) जिन जिन स्थानों पर उपरोक्त नलकूप खोदे गये हैं उनकी सूची मय क्षमता के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत खोदे गये नलकूपों का उपयोग अकाल के दिनों में पीने के पानी के लिये किया गया और अब अधिक क्षमता वाले नलकूपों का उपयोग कृषि हेतु किया जायेगा। शेष नलकूप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए सौंपे जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय जो नलकूप खोदे गये हैं, बिट्टूचा में एक नलकूप खोदने की बात की जा रही है और जबकि दो खोदे गये हैं और दोनों में बहुत ही मीठा पानी है और दोनों ही बन्द पड़े हैं और डोली में जिस कुए का उपयोग हो रहा है वहां ट्यूब वैल तो आज भी बन्द पडा है।

श्री खेतसिंह : बिट्टूचा के अन्दर फैमिन रीलीफ के तहत 1970-71 में खोदा गया

(श्री खेतसिंह)
था और यह कुआ पी. एच. डी. के सुपुर्द कर दिया गया है वाटर सप्लाई बालोतरा के लिए।

श्रीमती मदन कौर : बालोतरा के लिए तो एक नया नलकूप लूणी नदी के ऊपर की तरफ खोदा गया है उससे पानी मिलता है।

श्री खेतसिंह : हमने तो कुआ पी. एच. डी. के सुपुर्द कर दिया है। यदि और जानकारी लेनी है तो कृपया आप क्वेश्चन उनको पूछिये।

श्रीमती मदन कौर : दूसरा नलकूप जो बिटूचा में है उसका क्या हुआ और डोली के नलकूप का क्या हुआ ?

श्री खेत सिंह : डोली के नलकूप की क्षमता 1500 गैलन प्रति घन्टा है इसलिए अभी तक उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। यदि गांव वाले लेने के लिये तैयार हैं तो हम पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिये उनको यह सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं वर्ना फिर विचार किया जायगा कि कम क्षमता वाले कुए का क्या किया जाये।

श्रीमती मदन कौर : गांव में तो मीठा पानी है तो फिर गांव वाले क्यों लेने गये और दूसरी योजना नहीं बनी है और बिटूचा का एक कुआ बिलकुल बन्द पड़ा है और उसके आस पास पानी खारा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर) कौन कौन से नलकूप काम में लाए जायें इसकी नामावली आप देने की कृपा करें ?

श्री खेत सिंह : आपको यूं तो क्वेश्चन के जवाब में निवेदन किया था कि उसकी सूची रख दी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप कह रहे हैं कि उपयोग में लाये जा रहे हैं तो वह बतायें कि कौन कौन से काम में लाये जा रहे हैं ?

श्री खेत सिंह : यह तो अभी नहीं बता सकता कि कौन से चल रहे है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फिर आपको क्या जानकारी है, कुछ भी नहीं है। यह तो सूची सबको पता है लेकिन आप यह बतायें कि उपयोग में क्यों नहीं लाये जा रहे हैं ?

श्री रामकिशन : (वैर) लेकिन वह कह रहे हैं कि क्यों चल रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री खेत सिंह : मैंने यह नहीं कहा है मैंने यह कहा है कि यह कुए खोदे हैं और इनकी यह क्षमता है। इसमें कितने उपयोग में लाये जा रहे हैं यह अभी नहीं बता सकता क्योंकि कई तो दूसरे विभागों को हैंड ओवर कर दिए हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : और जो आपके विभागों के पास है उनकी क्या हालत है ?

श्री खेत सिंह : कटडा, झाडम, गडरा रोड, पादरा, आरूमन्ना हैं। इसके लिए लिखा है कि कोई भी काश्तकार इन कुओं से पानी लेकर काश्त करना चाहें तो हम इन कुओं से पानी लेकर काश्त करना चाहें तो हम इन कुओं से पानी देने के लिए तैयार है लेकिन कुछ साल जमीन अच्छी होने से लोग अपनी फसल में लगे रहे

(श्री खेतसिंह)
और उन्होंने पानी नहीं लिया लेकिन अब वह कह रहे हैं कि हम काश्त करना पसन्द करेंगे इन कुओं के पानी से।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : आप पानी की क्षमता किस आधार पर तय करते हैं ?

श्री खेतसिंह : उसका जितना डिस्चार्ज होता है पर आवर गैलन के हिसाब से।

श्री आईदानसिंह : आप मीटर लगाते हैं या क्या करते हैं जिससे कि आप डिस्चार्ज का पता लगाते हैं।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री): मैं समझता हूं की टंकी होती है···

श्री आईदानसिंह : आज तक किसी भी ट्यूबवैल में 'वी' नोज नहीं लगा है और आप की क्षमता पांच साल पहले की है। सन् 64 में जब कुए खोदे थे उस समय की क्षमता है और उसके बाद में वहां से क्षमता को मिटाया गया है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन रखा था क्षमता के बारे में फिर टेस्ट की गई क्षमता तो वह आधी से भी कम पाई गयी। आप 52 हजार गैलन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप सब जगह पर 'वी' नोज लगायें।

श्री खेतसिंह : वह तो लगा देंगे। इतने एक्सपर्ट तो आप भी नहीं है कि जितने जोर से आप कह रहे हैं।

श्री आईदानसिंह : एक्सपर्टस तो गैलेरी में बैठे होंगे। एक्सपर्ट आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन आपके जो बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर लिखा है 'राजकीय भूतल जल मण्डल, राजस्थान सरकार क्षमता' और उसकी क्षमता को मिटाया है, वह रही नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : यह तो एक्सपर्ट नहीं हैं लेकिन यह (श्री खेतसिंह जी) बात छिपाने में और झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या क्षमता को मिटा दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि कुछ कुओं के अन्दर पानी की क्षमता कम हुई है और कुछ में बढ़ी है। यह बात नहीं है कि जिस समय खोदे थे वही क्षमता सब में आज वैसी ही है, किसी में क्षमता बढ़ी है और किसी में घटी है इसलिए हो सकता है कि कहीं पर पहले क्षमता ज्यादा हो और अब कम हो गयी है और उसको कम लिखने के लिए मिटा दिया होगा। इसमें दिक्कत नहीं है। तो झूठ तो आप कह रहे हो और सच्चाई तो इनके पास भी ज्यादा नहीं है। हम 25 पर्सेन्ट झूठ बोलते हैं तो यह 75 परसेन्ट बोलते हैं।

श्री आईदानसिंह : आपने क्षमता नहीं लिखी है और पानी दे रहे हैं और पुरानी क्षमता से आप चार्ज कर रहे हैं उसके लिए क्या जवाब है ?

श्री अध्यक्ष : अब क्षमता लिखने के लिए तैयार हैं ?

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ष हर कुए की क्षमता को दुबारा रिव्यू करके लिख दिया जाये यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनोहरसिंह मेहता।

मांडलगढ़ क्षेत्र में औषधालयों की व्यवस्था

44. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):- क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहां वर्षाकाल में रास्ते पूरी तरह बन्द हो जाते हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या ऐसे स्थानों पर औषधालय हैं ?

(3) यदि नहीं, तो फिर औषधालय खोलने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि आजादी के तेईस वर्षों के बाद भी मांडलगढ़ क्षेत्र की कई पंचायतों में आज भी दवा का वैसा ही अभाव है जैसा आजादी के पहले था ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद : (श्री जयकृष्ण-शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी है।

(3) औषधालय व्यवस्था है।

(4) जी नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या कह रहे हैं अधिकतर स्थानों पर औषधालय की व्यवस्था है ? कल मैंने अर्ज किया था और कहीं यह भ्रम न हो कि मैं वारबार वही प्रश्न कर रहा हूं तो मेरे दो पंचायत क्षेत्र हैं और हमारा दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद मंत्री के पास पैसा नहीं है और मेरा दुर्भाग्य यह है कि लड्डू तो हैं लेकिन पत्ते दोने नहीं है। वहां लोग मर रहे हैं और मैं उनकी तनख्वाह उठा रहा हूं और बिना दवा के लोग मर रहे हैं और वहां लोग मेरे प्राण खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या इनके प्राण खाने से बचाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कल तो माननीय सदस्य 9 औषधालय बता रहे थे और आज दस बता रहे हैं। 232 पंचायत समितियां हैं और 7500 पंचायतें हैं और हर पंचायतों में चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे यह निवेदन करना है कि इन्होंने दस कहा लेकिन मेरे यहां ऐसे गांव हैं जहां बसें आज तक नहीं गयी हैं और बरसात में हजारों आदमियों का आवागमन रुक जाता है इसलिए इन परिस्थितियों में वहां दवाखाने खोलने चाहिए, क्योंकि वहां बीमारियों से बचने के लिए कोई साधन नहीं हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह कौन कौन से स्थान हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : झझोला, मपेला में दवाखाना नहीं है। इसी तरह के 40-50 स्थान हैं जिन्हें मैं बता सकता हूं जहां पर कोई दवाखाना नहीं है। जहां पर ट्रकों के अलावा लोगों ने बसें तक नहीं देखी हैं, सड़कें नहीं है वहां पर तो कम से कम दवाखाने खोले जायें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में जहां जहां बसें नहीं जाती हैं और पानी से कटते हैं तो उनकी समस्या है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह ले लें बहुत अच्छा है।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाते हैं पंचायत समिति या जिला परिषद् लेवल पर तो उसका आधार तो बता दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कई आधार हैं। औषधालयों का एक आधार नहीं है बहुत से आधार हैं। पंचायत समितियां भी कहती हैं, जिला परिषद् भी कहती है, गांवों के लोग भी अपनी मांगे रखते हैं, भवन तैयार वहां पर होता है, आने जाने की सुविधाएं भी देखी जाती हैं। सभी बातों पर गौर किया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 10 जो बताये हैं उनमें आधा आधा मील पर दवाखाने हैं और कई जगहों पर 10 10 मील पर भी दवाखाने नहीं हैं और मैं चार साल से चिल्ला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वे कौन से गांव हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिजोलिया के अन्दर, छोटी बिजोलिया, थाथरी इनमें 3–4 मील के फासले पर हैं वहां पर एलोपैथिक का दवाखाना भी है। झझोला में कहीं आवागमन के साधन नहीं है वहां पर चार साल तक रोने पर भी नहीं खोले हैं तो मैं आपका आधार समझ नहीं सका हूं। आप कह रहे कि हैं समाजवाद आ रहा है तो समाजवाद क्या हैलिकोप्टर से आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछा गया है क्या हैलिकोप्टर से आयेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हैलिकोप्टर से आयेगा या दवाइयां वहां पर हैलिकोप्टर से बरसायेंगे क्योंकि समाजवाद तो तेजी से आयेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इनकी कान्स्टीटुएन्सी में 1-1, 2-2 मील पर जहां जहां पर औषधालय हैं उनकी सूची दे दें तो मैं उनको उन गांवों में तब्दील कर दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह आपका काम नहीं है क्या कि मैं सूची दूं। मैंने बताया है हाथलिया, लोढीबिजोलिया आदि हैं। बिजोलिया के लोग नाराज होंगे तो होंगे और मुझे वोट नहीं देंगे, लेकिन लोगों को दवाइयां मिलना चाहिए। मैं सूची दूं तो आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सहयोग देना है अगर सूची दें तो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : साल भर बाद में यदि मुझे वोट न मिलें तो कोई बात नहीं लेकिन मैं सहयोग दे रहा हूं। जहां पर अस्पताल भी हैं और दवाखाने भी हैं ऐसी जितनी भी जगह है, ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरीज भी हैं और आयुर्वेदिक दवाखाने भी हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर न आयुर्वेदिक दवाइयें मिलती हैं और न एलोपैथिक, न सड़कें हैं और न कुछ अजने की फाकी मिलती है।

श्री अध्यक्ष : इस पर ध्यान दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अब की बार।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं बोला फिर आ गया हुकम।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह हुकुम क्या होता है ?

जंगलात की बीड़

45. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया उप तहसील के जंगलात के कुछ बीड़ राजस्व में आ गये हैं ?

(2) यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं ?

(3) ऐसी हालत में जब कि बीड़ राजस्व में ले लिये गये हैं भूमिहीनों को बांटने से क्यों रोका जा रहा है ?

(4) क्या वितरण कमेटी जल्दी ही इन बीड़ों की भूमि को ऊपर माल क्षेत्र के हाथ से खेती करने वाले भूमिहीनों को बांट सकेगी ?

(5) क्या इसी वर्षा की मौसम के पहले भूमिहीनों को भूमि बांट दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(1) जी हां।

(2) (1) सलोई बीड़। (2) मनोल बीड़ (3) तिखी ब्लाक में रामपुरा के स्थान पर, (4) केशव विलास बीड़।

(3) भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन करने की कार्यवाही जारी है।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या हुकुम भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है तो कब तक कर देंगे ? चार साल हो गये हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जल्दी ही एलॉटमेंट कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : 70 में बीड़ ट्रांसफर हुए हैं और मई जून में एलॉटमेंट का नोटिफिकेशन भी निकला है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 70 में हुए '

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

उद्योगों के लिए कर्ज के रूप में दी गई राशि

46. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किस किस बड़े बड़े उद्योगपति में कुल कितना कर्ज बाकी है जो उद्योगों के विकास के लिए दिया गया था ?

(2) वह कर्ज किस किस में कितने सालों से बकाया है ?

(3) किस किस कर्ज को वापिस जमा कराने की अवधि समाप्त हो चुकी है और उसका सूद कितना है ?

(4) उपरोक्त जानकारी सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जिन उद्योगपतियों में कर्ज का कुल रुपया जो बकाया है वह संलग्न सूची के के कालम 3 में अंकित है।

(2) यह सूचना संलग्न सूची के कालम 4 में अंकित है।

(3) यह सूचना संलग्न सूची के कालम 3 व 4 में अंकित है।

(4) सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री भैरोंसिंह : सूची पढ़कर सुना दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री हंसराज आर्य : पैसा कितने समय से ड्यू है।

श्री उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : नं. 1 में एक किश्त बकाया है और नं. 2 में दो किश्त बकाया है।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सूची पढ़ दें ताकि माननीय सदस्यों को पता लगे हम सदन में सूचना चाहते हैं कि किस किस में कितना कितना बकाया है। पूरी पढ़कर सूची सुना दें।

श्री हरिदेव जोशी : जयपुर उद्योग लि. 10,00,000,01 मूलधन और 12,000 ब्याज। जयपुर उद्योग लि. दूसरा 6,50,000 मूलधन और 87,750 ब्याज।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : जिन लोगों में एक किश्त ओवरड्यू हो गई उनसे पेनल इन्ट्रेस्ट क्यों नहीं वसूल किया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : ओवरड्यू है तो डिस्प्यूट के कारण है। गवर्नमेंट को देय था वह चुकाया नहीं इसलिए इन्होंने भी नहीं चुकाया है। अब आदेश दे दिए गये हैं चुकाने के लिए तो सेटिलमेंट हो गया है।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, सूची में नं. 5, नं. 6 और नं. 3 पर जितना पैसा दिया गया था उतने का उतना पैसा बकाया है और उनसे एक किश्त भी वसूल नहीं की गई है।

श्री हरिदेव जोशी : जो विवरण विशेष का कालम है उसमें आप देखिए। विजयनगर शुगर मिल्स लिक्विडेशन में चला गया इसलिए वहां का सवाल पैदा नहीं होता। कमानी इन्डस्ट्रीज को गवर्नमेन्ट ने जमीन नहीं दी इसलिए सवाल पैदा नहीं होता।

श्री हंसराज आर्य : क्या विजयनगर में काम शुरू हो गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : काम शुरू होकर फिर लिक्विडेशन में दिया गया है।

श्री हंसराज आर्य : यह पैसा कब तक वसूल हो जाएगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : मुझे अफसोस है कि एक तरफ तो उद्योगपतियों में 2 करोड़ 25 लाख बकाया है उसकी वसूली की कोई कार्य-

(श्री हंसराज आर्य)

वाही नहीं कर रही है यह सरकार और दूसरी तरफ मुझे अफसोस है कि नौहर तहसील में रामसर में अभी पिछले महीने एक चमार से वसूली के लिए किस तरह की कार्यवाही की गई। उसे भूमि तीन साल पहले तो एलॉट हुई थी और दो साल अकाल पड़ा। उससे वसूली के लिए यहां तक कार्यवाही की कि उसकी एक चारपाई और एक झोंपड़ी भी कुर्क करके ले गये। वह हरिजन रात भर बेचारा रोता फिरा और दाने मांग मांग कर उन दानों को बेचकर उसने अपनी चारपाई और झोंपड़ी को छुड़ाया। उधर वह हाल है और इधर पूंजीपतियों में सवा दो करोड़ रुपया बकाया पड़ा है और सरकार वसूल नहीं कर रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह समाजवाद है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने जो इन्फर्मेशन अभी यहां पढ़कर सुनाई है वह ठीक नहीं है। ड्यू होना एक बात है और नहीं चुकाना एक बात है। तो ड्यू होगा तब लेंगे। ढाई करोड़ का लोन दिया गया है वह ड्यू नहीं हुआ है आज तक। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक विजयनगर शुगर मिल्स का सवाल है तो उसको लोन दिया गया है और उसने फंक्सन करना बन्द कर दिया है तो उसके ऊपर जो जाप्ते की कार्यवाही होती लिक्विडेशन में लाने की और वसूलात करने की वह की जा रही है। जहां तक कमानी इण्डस्ट्रीज का सवाल है तो उनका पिग आयरन प्लान का प्रोजेक्ट था वह युगोस्लाविया से लाने में सफल नहीं हो सके इसलिए केवल भूमि का पैसा दिया गया है और भूमि राज्य के कब्जे में है और उसको वापस ले लिया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : सूची नं. 1 और दो में से किस को ड्यू मानते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि गवर्नमेन्ट में उनका ड्यू था। उनको वाटर वर्क्स बनाने के लिए लोन दिया गया था। उसीकी किश्त है। उन्होंने वाटर वर्क्स बनाया और राज्य सरकार ने 60 हजार गैलन सवाई माधोपुर को पानी सप्लाई करने के लिए कहा। उन्होंने पानी सप्लाई किया लेकिन वाटर वर्क्स ने पेमेन्ट नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हमसे जो किश्त मांगते हो, तो हमारा जो देय है वह हमको दे दो। दोनों के बीच में सेटिलमेन्ट हो गया है और वह एडजस्ट हो गया है।

श्री हंसराज आर्य : मैंने 5 साल के बड़े बड़े उद्योगपतियों का पूछा है तो सारे उद्योगपतियों का पूछा है। उनमें 15.20 करोड़ रुपया बाकी है जो ड्यू हो गया है।

श्री हरिदेव जोशी : जिसका आपने नोटिस दिया था उसकी सूचना सामने रख दी है और जो एतराज था उसका जवाब दे दिया गया है। मैं समझता हूं कहीं कोई दूसरी इन्फर्मेशन चाहें तो बतायें।

श्री हंसराज आर्य : जिनमें ड्यू हो गया है वह कब तक वसूल हो जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक विजय नगर का सवाल है उसका वसूल नहीं हो सकता है क्योंकि कम्पनी की पोजीशन यह है। जहां तक जयपुर उद्योग का सवाल है वह एमाउन्ट एडजस्ट होने को है। गवर्नमेंट में उनका पैसा है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भूमि का आवंटन और रेकार्ड में दुरस्ती का कार्य

42. **श्री लादूराम सुलानिया (फाग)**:– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले की फागी व चाकसू तहसीलों में कृषकों को भूमि आवंटित हो जाने के बाद भी उनके रिकार्ड में दुरस्ती नहीं होती हैं?

(2) क्या यह भी सत्य हैं कि भूमि आवंटन के बाद भी कृषकों से पैनल्टी वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सत्य हैं कि यह परेशानी इसलिये होती है कि कर्मचारी और अधिकारी रिकार्ड दुरस्ती की ओर ध्यान नहीं देते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी और दुरस्तियां कराकर वसूल की गई राशि वापिस करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जागीरों का मुआवजा

30. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कुल कितनी जागीरें थीं और उनका कुल कितना मुआवजा तय किया गया था?

(2) उस मुआवजे में से आज तक कितना मुआवजा दिया जा चुका है और कितना देना बाकी है?

(3) क्या जागीरदारों में सरकारी बकाया है?

(4) यदि हां, तो किस प्रकार की बकाया है और कितनी पुरानी है? क्या वह वसूली योग्य है? यदि हां, तो वसूली कब होगी? उपरोक्त सूचना सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखा जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 6,25,395 जागीरें थीं जिनमें से 5,76,425 जागीरों के दावे निर्णीत होकर मुआवजे के रूप में 37,60,48,900 रुपये की राशि देना तय किया गया।

(2) उपरोक्त तय किये गये मुआवजे में से 36,41,76,500 रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 1,18,72,400 रुपये का भुगतान करना शेष है।

(3) जी हां।

(4) जागीरदारों पर यह बकाया जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व की ट्रिब्यूट, मातमी, कर्जा

(राजस्व मंत्री)

लैण्ड रेवेन्यू एवं कोर्ट ग्राफ वार्डस की है जो वसूली योग्य है। जिलाधीशों से प्राप्त फार्म नं. 10 के आधार पर मुआवजे की राशि में से काट कर महालेखाकार कार्यालय में जमा कराया जा रहा है।

कृषकों को पास बुकों का वितरण

31. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ता. 25-3-70 को मुख्य मंत्री जी ने जो विधान सभा में यह घोषणा की थी कि समूचे राजस्थान में भू-राजस्व समान रूप से नये सिरे से कायम किया जावेगा उसके अनुसार कितने गांवों में भू-राजस्व समान रूप से कायम कर दिया गया है?

(2) यदि नहीं, तो उपरोक्त घोषणा को कार्य रूप में परिणित करने में कितना समय और लगेगा?

(3) क्या जिन गांवों में बहुत अधिक लगान पहले से ही लिया जा रहा है, उसमें कमी की जावेगी?

(4) क्या किसानों को देने के लिये पास बुकें तैयार हो चुकी हैं?

(5) यदि हां, तो कितने जिलों के किसानों को पास बुकें बांटी जा चुकी हैं और कितने जिले बाकी हैं?

(6) जो जिले बाकी हैं वहां के किसानों को पास बुकें कब तक दे दी जावेंगी?

उत्तर

(1) ऐसी कोई घोषणा नहीं की।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो विधान सभा में 25-3-70 को घोषणा की उसके अनुसार कमी होना संभव है।

(4) जी हां।

(5) समस्त जिलों में 8 लाख 86 हजार पास बुकें वितरण के लिये भेज दी गई हैं।

(6) 1 लाख 32 हजार पास बुकें और वितरण करने के लिये कार्यवाही जारी है।

खातेदारी के अधिकार

32. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बारानी क्षेत्र के उन किसानों को खातेदारी हकूक दिये जायेंगे जो कि सन् 55 के बाद के काबिज काश्त हैं और हर साल उनको वो भूमि अलोट होती है वह भू-राजस्व बराबर देते जा रहे हैं? यदि हां, तो किस वर्ष तक की कब्जा काश्त भूमि पर काश्तकारों की खातेदारी अधिकार दिये जावेंगे?

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या सरकार किसानों को सदैव के लिये ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार से वंचित रखेगी?

(4) क्या सरकार ने ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार देने के आदेश जारी कर दिये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री ने 25-3-70 को निम्न अंकित घोषणा की और उसके अनुसरण में नियमों का प्रारूप मंत्री मंडल को अनुमोदनार्थ पेश कर दिया गया है:–

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवन्टन हेतु वर्तमान नियमों के अनुसार 1955 के बाद के आराजी काश्तकारों के पट्टे (लीज) समाप्त हो जाते हैं। इसलिये इन व्यक्तियों के लम्बे कब्जा काश्त को देखते हुए इन्हें एक मुरब्बा (25 बीघा) तक भूमि आरक्षित मूल्य पर आवन्टित करने का निर्णय लिया गया है। यह आवन्टन केवल ऐसे वास्तविक भूमिहीन काश्तकारों को किया जावेगा जो सन् 1955 के पूर्व से क्षेत्र में रहते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में एक मुरब्बा से अधिक भूमि सरकार ले लेगी और क्षेत्र के अन्य भूमिहीनों को आवंटित कर देगी।

1955 के बाद के आराजी काश्त पट्टा धारकों (ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 1955 से 1960 के बीच आराजी काश्त पट्टे पर भूमि लेली है) के अलावा समस्त वर्गों के व्यक्तियों द्वारा अस्थायी पट्टे पर धारित भूमियां 1955 से गंगानगर जिले के गंगानगर क्षेत्र में रहने वाले वास्तविक भूमिहीन काश्तकारों तथा बीकानेर जिले में, बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों को एक साल के लिये अस्थायी काश्त पट्टे पर दी जायेगी। उक्त सभी भूमियां लाटरी निकाल कर पात्र (अलिजिबिल) आवेदकों को वितरित की जायेंगी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उत्तर भाग 1 में दे दिया गया है।

(4) उत्तर भाग 1 में दे दिया गया है।

जिला पाली के ग्रामों में कृषकों के विरुद्ध मामले

33. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला पाली के बिठूडा, अनोपपुरा व भाचूंदा गांवों के काश्तकारों पर धारा 91 के अन्तर्गत अनेक मामले चल रहे हैं? यदि हां, तो कौन कौन सा मामला किस किस तारीख से चल रहा है और ऐसे कुल कितने मामले हैं? किस किस मामले का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है?

उत्तर

जिला पाली के ग्राम बिठूडा, अनोपपुरा और भाचूंदा के काश्तकारों के धारा 91 के समस्त मामलों का निर्णय हो चुका है। इस समय कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में डिग्गियों का निर्माण

34. श्री हंसराज आर्य (भादरा):– क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में कुल कितने गांव और चकों में डिग्गियां बन कर तैयार हो गई है?

Page No 17

(श्री हंसराज आर्य)

(2) औसतन प्रति डिग्गी की क्या लागत आई है ?

(3) क्या इन डिग्गियों का उपयोग होने लग गया है ?

(4) इन डिग्गियों में नहर का पानी डाला जाता है या वर्षा के पानी पर निर्भर करती हैं ?

(5) क्या राजस्थान कैनाल क्षेत्र में किसी स्थान पर कोई मंडी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है ?

(स्थगित किया गया)

ट्रैक्टरों का वितरण

35. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1970 तक किस किस प्रकार के कुल कितने ट्रैक्टर सरकार ने जिलेवार किसानों को बांटे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष जोधपुर में ट्रैक्टरों का कारखाना खोला जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि गंगानगर में भी ट्रैक्टरों का कारखाना खोला जावेगा ?

(4) यदि हां, तो कब तक ?

(5) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में साधनहीन किसानों की भूमि को किराये पर काश्त करने के लिये कुछ ट्रैक्टर भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन से ट्रैक्टर है वे कहां पर रहेंगे व किस शर्त पर भूमि काश्त करेंगे ?

(7) क्या यह भी सही है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में साधनहीन, भूमिहीनों को उधार बीज देने का एक डिपो भी खोला गया है ?

(8) यदि हां, तो वह डिपो कौन से स्थान पर खोला गया है तथा बीज उधार किस शर्त पर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इस प्रकार के प्रयास जारी हैं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) वित्तीय साधनों के अभाव के कारण सम्भव नहीं है।

(6) जी हां, गंगानगर में 65 अश्व शक्ति के 9 रोमानियन ट्रैक्टर भूमि को किराये पर काश्त करने हेतु उपलब्ध हैं; जिन्हें हनुमानगढ़ में रक्खा गया है। ये ट्रैक्टर 28) रु. प्रति घंटे के हिसाब से, जुताई के कार्य के लिये दिये जाते हैं।

(7) जी हां।

(8) डिपो अनूपगढ़ में खोला गया है। ये ऋण 9% ब्याज पर दिया गया है तथा इसकी वसूली 31-3-71 तक कर लेनी है।

(कृपया-परिशिष्ट 3 देखिये)

आबादी भूमि पर काश्त

36. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कैनाल की कितने चकों की आबादी भूमि काश्त होती है और ऐसी अबादी की कितनी भूमि है ?

(2) क्या उस भूमि का लगान तथा तावान भी वसूल होता है ?

(3) यदि हां तो सरकार को कुल कितनी आय सालाना होती है ?

(4) क्या भाखरा नहर क्षेत्र में भी आबादी के चकों की भूमि काश्त होती है ?

(5) ऐसी आबादी भूमि भाखरा के चकों में कितने एकड़ है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

ब्यावर में सीमेन्ट फैक्टरी

37. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार द्वारा ब्यावर में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की घोषणा हुई थी ?

(2) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ब्यावर प्लाट के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। दांतरा डेम से पानी लाने के लिये सर्वे हो चुका है। 15,000 किलोवाट बिजली देने का आश्वासन दे दिया है। रेलवे में साईडिंग का अलाइनमेन्ट सर्वे कर लिया है। मशीन का आर्डर पार्टी द्वारा दे दिया गया है। पार्टी द्वारा 31-12-70 तक रु. 3,83,639.36 खर्च किया जा चुका है। भारत सरकार से सी. ओ. बी. (Carrying on Business) लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये पत्र व्यवहार जारी है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने कस्बा नोहर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री देवीदत गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान बिक्रीकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों से छापा मारकर अग्रिम बिक्री कर की राशि इकट्ठी करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) 17-3-71 को बयाना जिला भरतपुर की स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा में दिन दहाड़े डाका पड़ने के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार है :—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधानसभा ने नगर परिषद्, अजमेर द्वारा पक्की दुकानों के अलॉटमैन्ट के बाद भी लकड़ी की दो केबिन की इजाजत देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री लाभचन्द वैद, सदस्य विधान सभा ने लक्ष्मणगढ़ नगर में गत कई महिनों से मन्दिरों के आभूषणों एवं अन्य उपकरणों का चोरी में चले जाने उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री गंगासहाय, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि 302 के मामले में पुलिस द्वारा पिस्तौल पेश नहीं की गई, जिसके कारण मुल्जिम वरी हो गया।

ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। इसके अतिरिक्त इन मामलों को सम्बन्धित मांगों पर वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये भी उठाया जा सकता है। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित दो पेण्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है:—

(1) 25 फरवरी, 1971 को ग्राम बड़बड़ के निकट एक 12 वर्षीय बालक को एक ट्रक से कुचल कर मार डालने की घटना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से सम्बन्धित श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा, श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री जुझारसिंह व श्री बृजवल्लभ बोहरा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) अजमेर व जयपुर नगर में मिट्टी के तेल की सप्लाई ठप्प होने के बारे में श्री भगवानदास शास्त्री व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इसी विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है।

इनके अतिरिक्त महारावल श्री लक्ष्मण-सिंह व अन्य सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय नागरिक रसद मन्त्री जी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

माननीय मन्त्री।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है, जो व्यवस्था आपने दी है, वह शिरोधार्य है।

Page No 20

श्री अध्यक्ष : हां जी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन मेरा निवेदन है कि कोई नगर ऐसा नहीं है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कौन सा स्थगन प्रस्ताव ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव......

श्री अध्यक्ष : मैंने रिजेक्ट कर दिया क्या ? मैंने रिजेक्ट नहीं किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियम का अंशमात्र तो पालन करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन (बैर) : निवेदन तो किसी भी स्थिति में हो सकता है।

शासकीय वक्तव्य

अजमेर एवं जयपुर नगर में मिट्टी के तेल की सप्लाई ठप्प होने के सम्बन्ध में...

श्री हरिदेव जोशी (उद्योगमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अजमेर शहर और जयपुर शहर में केरोसिन तेल की कमी का स्थगन प्रस्ताव रखा है। इसमें यह निवेदन करना है कि इसमें शंका नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों शहरों में ....

कुछ माननीय सदस्य : दोनों शहरों में ही नहीं अन्य शहरों में भी है।

श्री हरिदेव जोशी : अखबारों के पढ़ने से मालूम होता है कि लगभग सभी जगहों पर यह समस्या है। आंकड़ों को पढ़ने पर पता चलता है कि केरोसिन जयपुर में काफी आया है। पिछले वर्ष फरवरी महीने में 14 हजार लीटर केरोसिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस साल 22 हजार लीटर प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अजमेर में ज्योढ़ा केरोसिन लगभग दिया गया है। मूल चीज मैं सोचता हूं कि यह है कि कोयले की कमी का असर उस पर भी पड़ा। तेल पर भी पड़ा। दोनों पर असर पड़ा है। लकड़ी भी मंहगी हो गई है। यह सारी चीज की कमी वैगन नहीं मिलने से, उसमें कोई व्यवधान होने से यह हुआ है। मैंने यह सोचा कि कुछ ज्यादा तेल लेकर इस कमी को पूरा किया जाये। इसकी जो कम्पनी है, अगर दो दिन भी तेल नहीं आये तो हल्ला हो जाता है। मैंने आई. ओ. सी., इन्डियन आयल कम्पनी है उससे बातचीत की है। उन्होंने 4 गुनी क्षमता कर दी है। जो स्टाक रहता है, उससे कई गुना उनका स्टाक रहेगा। किन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जबतक रेलवे सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो तबतक यह कठिनाई आ सकती है। इसलिए मैंने गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से अपील की है। जो सप्लाई करते हैं उनके अन्दर अपना प्रतिनिधि रख दिया है। वह रोज राजस्थान गवर्नमेंट से सम्पर्क रखता है और रोज हम से बातचीत करता रहता है। और जल्दी से जल्दी सप्लाई करने की व्यवस्था करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पिछले दिनों इलेक्शन के कारण से स्टाफ जो था वह इधर उधर ड्यूटी में लगा हुआ था। हो सकता है कि यहां का कोटा इधर उधर चला गया हो। शहर में बिक्री सेन्टर

Page No 21

(श्री हरिदेव जोशी)

कायम कर दिये हैं। प्रति व्यक्ति को 5 लीटर देने की व्यवस्था कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि एक्सप्लायट करने की प्रवृत्ति को हमने सील करने का प्रयत्न किया है। कुछ कानून में भी, क्योंकि यह कण्ट्रोल कमोडिटी तो है नहीं। केवल हमें यही अधिकार था। वह किस भाव पर बेचते हैं, इसको एग्जीबिट करें। उसका भी जो अधिकार राज्य सरकार को लेना चाहिए था वह ले लिया है। स्थिति में सुधार आयेगा। मैं समझता हूं निरन्तर विजीलेंस रहने से सुधार आएगा। इसके जो आंकड़े थे, जयपुर शहर में फरवरी में 70 के अन्दर 194 किलो लीटर सप्लाई हुआ था। मार्च, 70 में 196 किलो लीटर। इस साल मार्च में अबतक 220 किलो लीटर सप्लाई किया जा चुका है। फरवरी के अन्दर ड्योढ़े से ज्यादा पहले की अपेक्षा सप्लाई किया जा चुका है। परन्तु जब कोई कमी होती है तो आदमी होर्ड करता है। वह देखते हैं कि शार्टेज होती है। हमारा प्रयत्न है कि दो, चार, पांच दिन में यह व्यवस्था सुधर जाये। लोगों को ठीक ढंग से उपलब्ध हो सके, इसका प्रयत्न किया जायेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, केरोसिन के मामले में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, अजमेर और जयपुर की व्यवस्था टूट गई है। फरवरी और मार्च 1970 के बारे में मैंने अच्छी तरह से चेक किया था कि जब भी केरोसिन की कमी हुई थी तो आईडेन्टी कार्ड और फेयर प्राइस शाप्स के जरिए, जैसे आपने कहा प्रति व्यक्ति 5 लिटर, कुछ भी दे दें, 2–5–10 लिटर दे दें। इस प्रकार वापस चालू करके वापस जनता को दे दें तो जनता को सुविधा रह सकती है। मैंने देखा है इनको आप कोटा देते हैं गावों का नाम लेकर और सारे के सारे ट्रक फिरकर नगर में आते हैं। 20-20 रुपये तक भी बेचा गया है। और विशेषकर ज्यादा अधिक मात्रा में केरोसिन घरों में रखा है, ऐसी बात नहीं है। व्यापारी कमाए, इसके अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। लकड़ी महंगी, कोयला न मिले, गैस न मिले और घासलेट न मिले आखिर हर परिवार का व्यक्ति किस प्रकार भोजन की व्यवस्था कर सकता है। या तो आप ऐसा करें कि लाइट, हीटर्स पैदा करें जिन पर भोजन बना सकें।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : जहां तक स्थिति का सवाल है आप और मेरे बीच में मतभेद नहीं है। मैंने निवेदन किया कि सप्लाई फिगर्स से मालूम होता है कि सप्लाई तो हो रही थी। जैसा मैंने कहा संभव है कि एक अंश में होर्डिंग है, दूसरा ब्लेकमेलिंग का हो। सारे फैक्टर्स ने मिलकर क्यूमूलेटिव इफेक्ट शार्टेज का हुआ। हमारी दिक्कत यह है कि हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया, यह लाइसेन्सड कमोडिटी नहीं है। सेल के लिए कंपनी अपने होलसेलर्स और रिटेलर्स नियुक्त करती है। कानून के अन्दर राज्य सरकार को केवल एक ही चीज देखने का अधिकार है कि जो रेट कम्पनी और सरकार के बीच तय हुए हैं, उन रेट्स पर बेचते हैं या नहीं, वह बोर्ड पर लगा रहे है या नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा व्यापारियों ने गड़बड़ की हो इलेक्शन और होली के दिनों में, एन्फोर्समेंट जो ड्यूटी पर लगा हुआ इसके अन्दर गड़बड़ी की गई हो। किन्तु अब

(श्री हरिदेव जोशी)
अजमेर और जयपुर म्युनिसिपैलिटीज से अब कोई टैंकर्स कलेक्टर की मन्जूरी के बिना बाहर नहीं जा सकेंगे, हर चुंगी के नाके पर उनकी चैकिंग होगी और देखेंगे कि केरोसिन बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से रिटेल शाप्स कंपनीज ने बना दी हैं, केरोसिन मिडिलमेन को न देकर खुद सेल करेंगे और 5–5 लिटर प्रति व्यक्ति को देंगे, इससे स्थिति में सुधार आएगा।

इसके सिवाय ये तो प्रिकाशनरी मेजर्स हैं किन्तु सप्लाइज ज्यादा आयें इसके लिए एफर्ट्स करना जरूरी था, वह हमने इनीशिएट कर दिए हैं, रेलवे ने सहयोग किया है। उन्होंने अपना आदमी पेट्रोलियम और केमीकल्स डिपार्टमेंट के अंदर बिठा दिया है वह निरंतर कान्टेक्ट में रहता है जितने वैगन्स और टैंकर्स जाते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि इतना रवाना करते हैं, उसके अनुसार सप्लाई करते हैं

श्री भगवानदास शास्त्री : मंत्री महोदय ने जो व्याख्या वार बार की उसको रिपीट किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि यह केरोसिन कम आया है या कम मात्रा में वितरित किया गया है। आप चाहे इलेक्शन का नाम लें, चाहे होली का नाम लें; किन्तु जहां तक मुझे सूचना मिली है, यह जो बजट आने वाला है जिसको समाजवादी बजट मानते थे आज उस बजट के लिए भी ब्लेकमेलिंग करने वाले गड़बड़ कर रहे हैं। चूंकि आप चाहे तो भारत सरकार की तरफ से चाहें राज्य सरकार की तरफ से जिन कंपनीज को सीधा लाइसेंस आपने दिया है, उन्होंने शायद सोच रखा हो कि इससे फायदा होगा, जब भी बजट के दिन आते हैं तो ब्लेकमेलिंग के लिए चाहे भारत सरकार को लिखें चाहे कंपनीज को लिखें ब्लैक लिस्ट करके आप उनको फेंक दें तो उनको पता लग जाएगा। सरकार की नीति बिलकुल कमजोर इसलिए है कि जहां तक मेरा विश्वास है जितने केरोसिन के व्यापारी हैं उन्होंने या तो आपको आश्वासन दिया होगा या 50–50 हजार रुपए चुनाव के फंड्स के लिए दिये होंगे तभी आपने चुप्पी साधी, आपने चुनाव का फायदा लिया है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं सवाल करता हूं। आपकी सरकार कौन है? न तो लकड़ी, न कोयला, न घासलेट, न गैस उपलब्ध कराए। आखिर भोजन बनाने के लिए जनता को कुछ चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां और औरतें आपने क्यू में देखी होंगी बड़े बड़े घराने की। उनके साथ इस बदतमीजी के साथ व्यवहार होता है, उनको ठोकर मारते हैं, औरतों की बेइज्जती करते हैं। इस तरह जनता की इज्जत सिर्फ केरोसिन की वजह से जा रही है ....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप कहते हैं कि वैगन्स आयेंगे। मेरा विश्वास है कि 31 मार्च तक कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी चाहे कंपनीज ने भाव बढ़ाने के लिए बंद कर रखा हो।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर) : क्या मंत्री महोदय ने इस दृष्टि-कोण से भी विचार किया है कि जितना केरोसिन बड़े बड़े शहरों में प्राता है और वितरण करने के लाइसेंस तीन चार व्यक्तियों को दिया जा चुका है, उन्होंने नगरों में वितरण की क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : दूसरी बात, प्राज मंत्री महोदय ने केरोसिन की समस्या पर वक्तव्य तो सदन के सामने दे दिया है लेकिन प्रापको प्रौर मुख्य मंत्रीजी प्रौर सदन के माननीय सदस्यों को प्रच्छी तरह से मालूम है कि यह समस्या प्राज उत्पन्न नहीं हुई है । यह समस्या पहले भी शहरों में कई बार उत्पन्न हो चुकी है प्रौर वक्तव्य देने की नौबत क्यों प्राई ? मालूम होना चाहिए कि मंत्रियों को प्रौर विरोधी पक्ष के नेताप्रों को, जनता ने चौपड़ पर उनकी कारों को घेर लिया प्रागे जाने नहीं दिया जब यह स्थिति प्रा गई ।

श्री प्रध्यक्ष : नंबर 31

श्री दुर्गालाल बाढदार : तीसरी बात यह है कि सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैं मानकर चलता हूँ प्रौर प्राज नगर के लोग कहने लगे हैं, कि समाजवाद प्रा गया क्योंकि बहुमत में प्रापकी सरकार प्रा गई, प्रापकी जीत हुई । समाजवाद क्या प्राया ? सबसे पहले समाजवाद प्राया कि बाजार में रेजगारी की समस्या । खुली चेंज नहीं मिल सकती है ।

दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि प्राखिर दैनिक प्रावश्यकता की वस्तुप्रों की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर सकती तो फिर क्या इस सरकार का फायदा होगा ? प्रापने यह भी कहा कि हम नहीं कह सकते कि होली के कारण ही ब्लैकमेकिंग (ब्लैक मार्केट) हुप्रा हो । प्राप केवल यह कहकर मौन हो जाते हैं कि प्राइस लिस्ट लगा दें उसके प्रनुसार कार्यवाही होती है या नहीं लेकिन लाइसेंस बगैर कोई केरोसिन बेच सकता है ? लाइसेंस देने का प्रधिकार किसको है ? लाइसेंस केंसिल किया जा सकता है । प्राज मंत्री इस सदन के सामने प्रपनी विवशता को प्रकट करते हैं...

श्री अध्यक्ष : (उद्योग मंत्री से) इस स्थिति को भी प्राप देख लें ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जब किसी डीलर के बारे में राज्य सरकार संतुष्ट हो जाए केरोसिन की केपेसिटी बढ़ती है तो क्यों नहीं व्यवस्था की जाती ? सिर्फ केरोसिन की ही समस्या नहीं है प्रौर दैनिक वस्तुप्रों की समस्या है जिन पर पूरा ध्यान देना चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : केरोसिन प्राइल के बारे में ग्रामीण जनता के लिए प्रापने सोचा कि शहर में प्राकर केरोसिन ले जाए, यह सही नहीं है । प्राप ग्रामीण जनता को ग्राम पंचायत केन्द्रों तक जिस प्रकार से शक्कर वितरित होती थी उस ढंग से उनको ग्राम पंचायत केन्द्र पर केरोसिन मिल जाए इस संबंध में प्रापने क्या व्यवस्था की ?

श्री अध्यक्ष : प्रार्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : प्रध्यक्ष महोदय...

Page No 24

श्री परसराम गंगाराम : सवाल यह है, अजमेर . . .

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इंडियन ग्रोइल कम्पनी ने राजस्थान के लिए जो पहले होलसेल एजेंसी थी उसमें कुछ परिवर्तन किया है ? क्या यह सही है कि इंडियन ग्रोइल कम्पनी द्वारा राजस्थान में जिस पाइन्ट से तेल की सप्लाई की जाती थी उस पाइन्ट को बदल कर दूर के पाइन्ट से तेल सप्लाई करने का काम इस होलसेल एजेंसी को दिया है ? क्या इसके कारण से ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज ज्यादा बढ़ रहे हैं ? और इस कारण यह होलसेल डीलर कम से कम ग्रोइल राजस्थान में लाता है ? दो बात।

क्या यह सही है कि फरवरी, 1970 के पहले जो आपने फरवरी के फिगर दिये हैं, 1964 लिटर प्रति दिन या प्रति माह–जो कुछ भी कहा, वह जयपुर में आता था। क्या यह सही है कि फरवरी 1970 के पहले लगातार दो वर्षों तक जो मात्रा बताई है इससे कहीं अधिक मात्रा जयपुर शहर में आती थी ?

क्या आप यह भी जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि फरवरी 1970 का ही प्रश्न नहीं है, कैरोसिन की कमी लगभग दो वर्ष से सारे राजस्थान में महसूस की जा रही है ? जयपुर और अजमेर का प्रश्न नहीं है, बाहर गांव में कैरोसिन का दर्शन नहीं होता है। आप अजमेर और जयपुर में व्यवस्था कर देंगे उससे सारे राजस्थान की व्यवस्था होने वाली नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा, क्या राजस्थान सरकार ने अपने लेवल पर कभी इस बात का असेसमेंट किया है या नहीं कि राजस्थान में कितने कैरोसिन की आवश्यकता है ? इंडियन ग्रोइल कम्पनी कितना तेल सप्लाई कर रही है ? होलसेल एजेंट कितना कैरोसिन ग्रोइल ला रहा है ? और कितने की बिक्री हो रही है ? इस सारी स्थिति के बाद भी यदि राजस्थान सरकार ने पूरा असेसमेंट नहीं किया है तो आपने स्टोप गैप अरेंजमेंट बताया, इससे इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैं राजस्थान सरकार से चाहूंगा कि राज्य सरकार पैट्रोलियम एण्ड इंडियन ग्रोयल कम्पनी के साथ, होलसेल एजेंट के साथ बैठकर विचार करे कि किस प्रकार ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज बढ़े हैं, राजस्थान में कितने तेल की आवश्यकता है, कितना तेल सप्लाई किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर और इसके साथ साथ रूरल एरिया में कितने तेल की आवश्यकता है, उस तेल की किस प्रकार से सप्लाई की जा सकती है ? मैं समझता हूं, चाहे एक प्राइवेट कम्पनी का होलसेल डीलर व्यक्ति हो, लेकिन जहां तक सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रश्न है, उसमें राजस्थान सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। वह इस समस्या का समाधान इस तरह से करे तो लाभ होगा। लेकिन आप कहें कि दो दिन में वैगन आ जायेंगे, दो दिन में आ जायेंगे तो दो दिन में कैरोसिन ग्रोइल की सप्लाई हो गई तो उससे प्रॉबलेम होने वाली है। आप चाहें कर सकते हैं लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिये सबसे पहले डिटेल में जायं और मांग का असेसमेंट करें, फिर मांग की पूर्ति

Page No 25

(श्री भैरोंसिंह)

किस प्रकार की जा सकती है–इस बारे में असेसमेंट करें और फिर कम्पनी के साथ बैठ कर होलसेल डीलर की कैपेसिटी है या नहीं–इसका अन्दाज लगाकर किस प्रकार उसकी पूर्ति की जा सकती है, इसका ब्ल्यू प्रिंट बना कर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो, मैं समझता हूं कि इससे समस्या में कमी आयेगी। लेकिन दो दिन तक लोगों ने आवाज उठाई जिससे डर कर भारत सरकार से वैगन मांग लिये और आंकड़े ले लिये–इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री परसराम गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, बात यह है ...

श्री अध्यक्ष : बात यह नहीं, प्रश्न !

श्री परसराम गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 62 पैसे लिटर पर तेल बिकता है और अजमेर में 58 पैसे लिटर पर तो क्यों नहीं राजस्थान में 58 पैसे लिटर किया जाय ? क्या वजह है कि 62 पैसे लिटर दूसरी जगह बिकता है ? मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान में एक जैसा भाव हो वह ठीक रहेगा और जनता को फायदा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना !

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि बजट के दिनों में, जब बजट आने वाला होता है तो क्या बजट के कारण से, जो टैक्स नये से नये लगने वाले होते हैं, उसकी आशा में लोग चीजें बेचने में कमी करते हैं, संग्रह करते हैं, छिपा देते हैं और बजट प्रगट होने के बाद इन चीजों को बाजार में लाते हैं ? तो क्या बजट के पहले इन चीजों को बाजार से ओझल नहीं होने दिया जाय इसका प्रबन्ध करने में सरकार सक्षम है ?

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, जयपुर में नगरपालिका क्षेत्र, अजमेर नगरपालिका क्षेत्र में इतना कैरोसिन आइल आता है, उसके बाहर जाने पर रोक लगा दी है इसके साथ साथ चुंगी चौकियों और नाकों से वह बाहर नहीं जाने दिया जायगा। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, जो रूरल एरिया है, अजमेर और जयपुर को छोड़ कर राजस्थान का अधिकतर भाग रूरल एरिया है वहां की जनता के लिए तेल की व्यवस्था करने के लिए आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : क्या कदम उठाये ?

श्री श्रवण लाल : क्या करने का विचार है और किस प्रकार तेल वहां पर पहुंचाया जायगा और उनकी सुविधा के लिए आगे क्या कार्यवाही की जायगी ? इसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा।

श्री मदनसिंह : गांव गांव में बिजली लगा दी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था; जो प्रश्न अभी किये गये हैं, मेरे खयाल में मैंने उन सब का उत्तर दे दिया है, वह यह है कि राजस्थान में मैंने अपने आपको इसलिए

(श्री हरिदेव जोशी)

महदूद रखा था क्योंकि यह प्रश्न अजमेर और जयपुर के सीमित क्षेत्र के रूप में पूछा था, इसलिए दूसरे आंकड़े मैंने देने की कोशिश नहीं की। परन्तु इन सारी चीजों का रिव्यू कर लिया गया है। जैसा मैंने निवेदन किया, कानून में हमको केवल यह देखने का अधिकार था कि जो रेट निर्धारित की गई है, उस पर बिकता है अथवा ज्यादा पर, और वह एक्जिबिट किया जाता है या नहीं। परन्तु जैसा मैंने निवेदन किया, विशेष अधिकार राज्य सरकार ने लिये हैं और पुख्ता पाबन्दी इसमें की है और जो भी नियंत्रण करना पड़ेगा, उसको करने की कोशिश की जायगी। जहां तक बाहर भेजने का सवाल है, अजमेर और जयपुर शहर का कोटा बाहर नहीं जाय–यह मतलब है। गांवों के व्यक्तियों को नहीं दिया जायगा और अजमेर, जयपुर शहर को सप्लाई किया जायगा–यह तात्पर्य नहीं है।

कैपेसिटी का जहां तक सवाल है, पहले यह कैपेसिटी टैंकर्स की 345 किलोलिटर थी, उसके बजाय अब 2400 बना दी गई है ताकि ज्यादा स्टाक रह सकेगा मैं इस रूप में देखता हूं। माननीय सदस्य जिस रूप में कि रिटेलर और होलसेलर से पैसा ले लिया है, वह गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेंट मैं मानता हूं। इसके सिवाय बाकी सारी चीजों को मैं समझ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें स्लेक्स तीन तरह के हैं। ज्यादा सप्लाई, सप्लाई रेगुलर होवे, जो निर्धारित कर दिया जाय कोटा वह बराबर आता रहे। वह नहीं आये, अगर कन्ट्री में अमुक प्रकार की शार्टेज होगी तो राजस्थान में भी हो जायगी . . .

श्री भैरोंसिंह : हमें यह पूछना है, राजस्थान सरकार को यह मालूम है कि राजस्थान का कितना कोटा निर्धारित था, उसके अगेन्स्ट में कितना मिला और होलसेलर द्वारा लिया गया ? यह मालूम होगा तब प्राबलम सोल्व होगी।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने निवेदन किया, इन सारे इश्यू को डिस्कस कर लिया है। जो पहले राजस्थान का कोटा था, जो पहले कोटे में सप्लाई थी, उसकी ड्योढ़ी सप्लाई आवे। यह व्यवस्था कर ली है।

श्री भैरोंसिंह : आज तक आया या नहीं ? क्वेश्चन यह है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात सुनें पूरी बात। फिर कह लीजिए।

श्री अध्यक्ष : अपनी बात कहें। मैं उनको रोक लूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं, कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट पिछले कन्जम्प्शन को देख कर असेसमेंट करती है कि हमारा कन्जम्प्शन इतना है, इसलिए यह जाना चाहिए। पिछले पांच वर्ष के कन्जम्प्शन को देख कर उससे ड्योढा लगभग असेसमेंट है, क्योंकि लोगों का खर्चा बढ़ा है, कन्जम्प्शन बढ़ा है। उस हिसाब से कर रहे हैं। जो कोटा निर्धारित किया है, वह सप्लाई बराबर आती रहे।

दूसरा मुख्य स्लेक मानता हूं, वह रेल्वे के वैगन का है। हमको एस्योर किया है गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने भी और रेल्वे अधिकारी, पेट्रोलियम एण्ड केमिकल्स मिनिस्टरी में

(श्री हरिदेव जोशी)
रखा है, वह बराबर आता रहे, इसको देखेगा।

तीसरी चीज है कि रेल्वे की दिक्कत के कारण एक बार नहीं आये। तो स्टाक यहां पर होना चाहिए। उसकी व्यवस्था कर ली है कि तीन-चार दिन का स्टाक रह सके ताकि व्यवस्था कर सकें।

चौथी चीज कानूनी व्यवस्था करने की है। जो कलेक्टर और दूसरे, उन्हें जो अधिकार चाहिए थे, वह व्यवस्था कर दी गई है। मैं समझता हूं कि जो कमी आज महसूस हो रही है वह कमी नहीं रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक रेट का सवाल है। माननीय सदस्य ने कहा रेट का दूरी के कारण तो कांडला से कोई चीज आती है, तो कांडला के पास में सस्ती पड़ेगी, दूर जाकर मंहगी हो सकती है। उसको इन्टरफियर करना नहीं चाहता, गवर्नमेंट यह देखना चाहती है कि सप्लाई एन्स्योर हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन बिल्कुल साफ है॰॰

श्री परसराम गंगाराम : बात यह है कि राजस्थान में 62 पैसे लिटर मिले॰॰॰॰

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिंह।

श्री परसराम गंगाराम : अजमेर में 58 पैसे लिटर। इतना फर्क है।

श्री अध्यक्ष : जनसंघ के नेता श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। या तो मंत्री महोदय जानकारी के अभाव के कारण या और किसी कारण से सदन में नहीं रखना चाहते हैं। दो वर्ष पूर्व कांडला के स्थान पर दूर से ट्रान्सपोर्ट करने के लिए डी. एस. ओ. ने इन्डियन आइल कम्पनी को कह दिया। दूर से जितना ट्रान्सपोर्ट किया जावेगा तो बेगनों की शार्टेज आवेगी। विवाद चलता रहा। कम्प्रोमाइज हुआ दोनों के बीच में एट दी कोस्ट ऑफ राजस्थान पब्लिक। राजस्थान को जितना माल मिलना चाहिए था अकार्डिंग टू दी रेट असेस्ड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया उसके अनुसार राजस्थान को केरोसिन की सप्लाई नहीं हुई। मंत्री महोदय ने यह कहा कि इन्डियन आइल कंम्पनी और एस्सो की ओर से यह इत्तला पहुंची थी कि तेल का संकट आने वाला है और राजस्थान सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। दो वर्ष पूर्व रिप्रेजेन्टेशन मिला था और उसको राजस्थान सरकार के पास भेजा था। राजस्थान में इस प्रकार का संकट आ सकता है उसके लिए पूर्व ही सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए थी।

राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कमी आयगी सो तो आ गयी लेकिन भविष्य में भी ऐसी स्थिति बने नहीं इसके लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है यदि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कितना माल लिया जा सकता है और कितना लेना चाहिए यह विचार करके

(श्री भैरोंसिंह)
यदि हस्तक्षेप हो सकता है तो हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह प्रश्न साफ कर चुका हूं। यही कह सकता हूं कि जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं उनको करने में कसर नहीं रखी जावेगी। मैंने पहले ही कहा था कि सप्लाई होनी चाहिए और इसको हम एन्स्योर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

राजस्व मन्त्री।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

(क) अध्यादेश

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ग्रामदान अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1971) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री।

(क) प्रतिवेदन लेखे व अधिसूचना

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर शुगर मिल्स लि. का 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित लेखे एवं संचालकों का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 4/एल./पी. एस./ए./आर/5/904-14 दिनांक 19 फरवरी, 1971 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (सेवा) नियम, 1959 में और संशोधन किए गये हैं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

गृह मंत्री जी।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 61 के अन्तर्गत राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन

(श्री हीरालाल देवपुरा)
अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 13 सन् 1970) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : आपने फरमाया था कि राज्य सरकार से स्टेटमेंट दिलायेंगे.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : आपने व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर यह कहा था कि जानकारी लेकर निर्णय दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वक्तव्य दिला दें। यदि आप इसमें देरी करेंगे तो वहां की जनता के साथ भारी अन्याय होगा। मेरा स्थगन प्रस्ताव था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वहां की जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस क्षेत्र की जनता का मैं प्रतिनिधि हूं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : बार बार कहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। मैं वहां का प्रतिनिधि हूं आज तक उन्होंने आश्वासन को पूरा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी भी बात सुन लीजिये। वह जानकारी के लिए भेजा है। कल सूचना दे दूंगा।

श्री हीराभाई : कल तो छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष : कल मतलब अगले दिन जब विधान सभा की कार्यवाही होगी।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलने के लिए बोल रहे हैं।

श्री हीराभाई : आपको (मंत्री महोदय को) सचेत करने के लिए चेयर से निवेदन करूंगा कि हजारों की तादाद में लोग गुजरात में भटक रहे हैं, औरतों को पकड़ कर लेजा कर बेचते हैं। वहां हालत बड़ी खराब है। इस पर वक्तव्य दिलायें और सरकार को इसके लिये बाध्य करें।

श्री अध्यक्ष : दो दिन की छुट्टी है दो दिन आप और रोक रखिये।

श्री रामकिशन।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अभिभाषण दिया है इससे अधिक तथ्यहीन भाषण तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? सदन के माननीय सदस्यों के लिए यह कह देना कि उनको तो समाजवाद के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनकी जानकारी है ही। फिर नं. 1 पर राज्यपाल महोदय यह कहते हैं कि "1970-71 देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक वर्ष रहा है। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस वर्ष जो महत्वपूर्ण कदम उठाये थे सब आपके सामने हैं।" मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से और विशेष तौर से सरकारी पक्ष के लोगों से

(श्री रामकिशन)
समाजवाद के लिए कौन कौन से सरकार ने कदम उठाये, उनकी उनको जानकारी है क्या? कम से कम मुझे तो नहीं है। मुझे नहीं है, तो मैं मान कर चलता हूँ कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी नहीं है।

सरकार यह कहती है कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं की पेन्शनें बन्द की। उनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। कौन कौन से कदम उठाये हैं उनकी जानकारी यदि राज्यपाल महोदय दे देंगे तो सदन को भी जानकारी मिलती और हम भी यह समझते कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन हुआ है।

लोक सभा के चुनाव हुए। यह कहा गया कि शान्ति से हुए। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हुए और किस प्रकार की अव्यवस्था हुई उसकी जनता को और सरकार को पूरी तरह से जानकारी है। बड़े पैमाने पर जनता को लूटा, मारा और हिंसा हुई तो मैं सहमत हूँ कि इस पैमाने पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकारी मशीनरी ने अब की बार किस प्रकार से काम किया वैसा मैंने पन्द्रह साल में भी नहीं देखा। बहुत से सरकारी कर्मचारी यह समझ बैठे थे कि सरकारी नौकर नहीं कांग्रेस पार्टी के नौकर हैं। वे यह समझ बैठे थे कि सरकार तो जा रही है लेकिन उनके लिए तो ऐसी ही सरकार हो सकती है जो करप्शन के लिए अधिक संरक्षण देती हो। जितनी सरकारें बनी हैं देश में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसने इतना बड़ा संरक्षण दिया हो।

जो बहुत ज्यादा करप्ट थे और जो बदलती हुई परिस्थितियों के परिणामों को समझकर भयभीत थे, उन लोगों ने क्या क्या किया यह अपनी आंखों से देखा। इन्जीनीयर लोग कांग्रेस के लिये सरकार के मिनिस्टरों के चुनावों के खर्च के लिये चन्दा वसूल कर रहे हैं। अब विरोधी लोग पराजित हो चुके हैं, चुनावों की बाजी कांग्रेस जीत ले गई है, इसलिए यह सब अधिक कहने का अब ज्यादा अर्थ नहीं नहीं रह गया। ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी के लोग आज भी आप चले जाइये देख सकते हैं उनको वहीं करते, लोगों से चन्दा वसूल कर रहे थे। कल जयपुर में वे सड़कों पर जाकर बैठ गये और कहने लगे कि कुछ पहले का उधार रह गया हैं, दीजिए। मुझे यह सब देखकर शर्म आती है। किस दिशा में यह समाजवाद का थोथा नारा लगाने वाली सरकार अपने कर्मचारियों को ले जा रही है।

देश में हमें कुछ परम्पराओं को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा जिससे लोकतन्त्र को मजबूत किया जा सके।

अब इन्जीनियरों ने चन्दा वसूल किया, आर. टी. ओ. ने गाड़ियां पकड़कर उनसे जबरन पैसा वसूल किया गया। फिर भी राज्यपाल महोदय कहते हैं कि चुनाव शान्तिपूर्वक हुए। व्यापक पैमाने पर कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई यह जरूर है, इसका हमें भी सन्तोष है, पर सरकार अगर यह समझती हो कि चुनावों में सही सही सारे नियमों का पालन हुआ है तो वह पूरी तरह से भ्रम में है।

आगे राज्यपाल महोदय कहते हैं, यह ऐतिहासिक वर्ष है कि समाजवाद के लिये कदम उठाये गये हैं। अब सरकार भी यह

(श्री रामकिशन)
कहती है इससे दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसलिए होती है कि समाजवाद का सम्पूर्ण अर्थ समझ नहीं पाये। इस नारे से कांग्रेस को सफलता मिली है जिसके लिए बीस साल से संघर्ष कर रहे थे लोग। हमें उनके मुकाबले में चुनाव में पराजित होने का दुःख नहीं, दुःख है तो इस बात का है कि समाजवाद की कल्पना की जो तस्वीर मिलनी चाहिये वह तस्वीर यह सरकार दे सकेगी या नहीं इसमें बहुत सन्देह है। अगर राज्यपाल महोदय का भाषण देखा जावे तो यहीं से निराशा की शुरूआत होती है। एक लाइन, एक चिन्ह ऐसा नहीं मिलता चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, जिससे ऐसा लगता हो कि वे समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं।

आगे चलकर राज्यपाल महोदय ने कुछ संकेत किये हैं अपनी उपलब्धियों के बारे में। नहरें बनाली, सड़कों का खानों का उद्योग धन्धों का परिवार नियोजन और श्रम कल्याण आदि कुछ कर लिये। पांच सात पेराग्राफ में इन उपलब्धियों का उल्लेख है। ये राजस्थान की समस्यायें नहीं हैं। फिर राजस्थान की समस्यायें क्या हैं? यह नहीं कि नहर बनेंगी, ये तो बन रही हैं। ज्यादा बनानी हैं, बनानी ही चाहिये। बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, बढना चाहिये, सड़कें बन रही हैं बननी चाहिए, स्कूल खुल रहे हैं खुलने ही चाहिए, अस्पताल खुल रहे हैं, खुलने ही चाहिए ये तो यह समस्या नहीं है।

देश की समस्या, राजस्थान की समस्या आज है गरीबी और बेरोजगारी आज हिन्दुस्तान की सरकार या इन्दिराजी की सरकार यह नहीं कर सकी कि गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए राजस्थान के राज्यपाल से कोई सन्देश और उसकी कार्य प्रणाली या रूपरेखा दिलवाती।

राज्यपाल केवल यह कहकर चुप रह गये कि गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए एक जिले में एक हजार लोगों को रोजगार दिलाया जावेगा। इसके लिए 3॥ करोड़ का प्रावधान किया है।

मैं पूछना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कितने बेरोजगार हैं? जो सूची आपने दी है रोजगार दफ्तरों के आंकड़ों के आधार पर 88 हजार के आसपास बेरोजगार हैं। अगर प्लान बनाने का यही तरीका है, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार उसमें असफल होगी। आज जो विजय आप ने प्राप्त की है सम्भव है वह भयंकर सशस्त्र क्रान्ति में परिणीत हो जाय। निराश लोग बेरोजगार लोग दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। राजस्थान सरकार का प्लानिंग विभाग अगर यही काम करता है तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है, दया आती है।

कितने लोग बेरोजगार हैं देश में इसके आंकड़े आपके इन एम्पलायमेन्ट एक्सचेंजों से नहीं आंके जा सकते। इसकी दो तीन श्रेणियां हैं। एक तो वे जो पढ़े लिखे हैं जिनके नाम रोजगार के दफ्तरों में रहते हैं। उनकी संख्या राजस्थान में सन् 68 में 88 हजार थी आज वह बढ़ी होगी, और 1 लाख 22 हजार के आसपास होगी। पर तीन श्रेणियां और हैं। एक तो हैं जो भूमिहीन किसान हैं वे जो खेतों पर मजदूरी करते हैं।

Page No 32

(श्री रामकिशन)

फसल के दिनों महिने पन्द्रह रोज उनको काम मिलता है। उनकी संख्या इकट्ठी करनी चाहिए। आंकड़े संकलन करने वाले विभागों को नई टैकनिक इसमें अपनानी चाहिए। अब ग्रामीण बेरोजगार कितने हैं?

दूसरे जो भिन्न भिन्न धन्धों में रहते हैं, जिनका मौसम में काम धन्धा चलता है, हमारे अर्थ शास्त्र के अनुसार उनको अर्द्ध बेरोजगारों की श्रेणी में रखा है। इन तीन तरह के बेरोजगारों को इकट्ठा कर लें तो कितने होंगे, इसका अन्दाज लगाया जा सकता है।

हिन्दुस्तान में इस तरह के जो आंकड़े हैं बेरोजगारों के वे 4.50 करोड़ बताये गये हैं। इसमें अर्द्ध-शिक्षित और मौसमी धन्धों के बेरोजगार की संख्या की भी गिनती की गई है। कम आय वालों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। 4।। करोड़ बेरोजगार हैं यह हिन्दुस्तान का प्लानिंग विभाग मानता है।

अब इन्दिराजी और सुखाड़ियाजी वादा करते हैं कि एक हजार आदमियों को एक जिले में रोजगार वे दे सकेंगे। अब इस हिसाब से हिन्दुस्तान के सारे जिलों का हिसाब लगाए तो आप पांच लाख आदमियों को रोजगार दे सकेंगे, एक साल में। इस हिसाब से 4।। करोड़ लोगों को रोजगार देने में आपका 90 वर्ष समय लगेगा। तब तक न इन्दिरा गांधी रह पावेंगी यहां न बेरोजगार ही रह पावेंगे।

आज जो बेरोजगार हैं, उनको आप अपने हिसाब से 90 साल में रोजगार देना चाहते हैं। 1।। लाख के करीब राजस्थान में बेरोजगार हैं, यह योजना कमीशन अन्दाज लगाता है और राजस्थान सरकार केवल यह संख्या 88 हजार मान रही है और इसके लिए 3।। करोड़ का प्रावधान किया है। इस हिसाब से 1346 रुपया प्रति व्यक्ति के लिए सालाना प्रावधान किया है। अब इतनी छोटी सी रकम में किस तरह का उद्योग आप उसको करावेंगे।

तीन प्रकार के धन्धे आपके पास हैं। खेती, व्यापार और सरकारी सेवायें। सरकारी सेवाओं का हिसाब लगावें तो हमारे देश में आज सरकारी नौकरों की संख्या इतनी हो चुकी है कि जितनी संसार में किसी सरकारी तन्त्र में नहीं है। अब इसमें और वृद्धि करना बजट को असन्तुलित करना है। अब रोजगार के लिए रोजगार देना है तो अलग बात है अन्यथा तो यहां के शासन तन्त्र में जितने व्यक्ति हैं उतने और संसार में कहीं नहीं हैं। 138 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे देश में हो चुके हैं। देश की कुल आबादी में 31 व्यक्तियों पर एक कर्मचारी है। तो इस तरफ रोजगार देने की ज्यादा सम्भावनायें नहीं हैं। केवल बजट को असन्तुलित बनाना हो या प्रोडक्टिव केपिटल को डेड केपिटल में बदलना हो तो अलग बात है।

फिर रह जाते हैं दो धन्धे। उद्योग धन्धे और खेती। अब योजना कमीशन यह कहता है कि एक आदमी के लिए रोजगार दे सकते हैं तो पूंजी का नियोजन चाहिए 2023 रुपया और खेती के क्षेत्र में 1600) का दे सकते हैं।

(श्री रामकिशन)

तो इस तरह से योजना सरकार ने जो बनाई है वह योजना अधूरी तो है ही, बल्कि बेरोजगारी भी मिटेगी नहीं। यह आपका कथन भ्रम पैदा करने वाला लगता है केवल क्योंकि आप न इतने लोगों को खेती पर लगा सकते हैं न उद्योग धन्धों में लगा सकते हैं। इस तरह से राजस्थान की सरकार की और हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से कौनसे समाजवादी कदम उठाये गये हैं यह पता नहीं लगता।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया किसानों को ऋण दिलाने के लिए राजस्थान में किसानों को बैंकों की मार्फत 4 करोड़ 3 लाख का ऋण दिया गया है। क्या राजस्थान सरकार इस कर्ज को ही काफी मानती है। यह ठीक है बैंक पहले कर्जा नहीं देते थे। पर वास्तव में देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कितना कर्जा चाहिए, इसका हिसाब लगावें तो सरकार, साहूकारी क्षेत्र और बैंक वगैरह से मिलाकर 50 परसेन्ट कर्जे का प्रावधान भी नहीं कर पायी है।

अभी हिन्दुस्तान ग्रामीण ऋण समिति का गठन किया गया। उसने अन्दाज लगाया था कि चौथी योजना में किसानों की हालत उन्नत करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 40 अरब रुपयों की जरूरत पड़ेगी। इसमें से 20 अरब का कर्जा जो देना पड़ेगा वह अल्पकालीन देना पड़ेगा। 5 अरब का कर्जा देना पड़ेगा वह मध्यकालीन कर्जा होगा और 15 अरब का कर्जा देना पड़ेगा वह दीर्घकालीन कर्जा होगा। इस प्रकार का ऋण देने वाली समिति ने अन्दाजा लगाया था कि हिन्दुस्तान में कृषि को, खेती को उन्नत करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हमें कम से कम 40 अरब के कर्जे का प्रावधान करना पड़ेगा। उसने इसके साथ ही साथ भी कहा है कि इस 40 अरब में से यह इस तरह इसके वितरण का प्रावधान होना चाहिये। इसमें यह था कि सहकारी क्षेत्र में से 8 अरब 25 करोड़ का प्रावधान होगा और दूसरी वित्तीय ऐजेन्सी 2 अरब 50 करोड़ का प्रावधान रखेगी। इस तरह से चौथी पांच साला योजना के आखिरी तक सहकारी समितियों और वित्तीय ऐजेन्सियों के द्वारा किसानों को इतना कर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। उन लोगों की जरूरत 40 करोड़ रुपयों की नहीं थी। यह कहना कि बैंकों से इतने करोड़ का कर्जा हमने दिलाया, उचित नहीं है। मैं यहां सारे हिन्दुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ उसके एक प्रान्त राजस्थान की बात कह रहा हूं। इस अनुमान के अनुसार आप हिसाब लगा सकते हैं कितना कर्जे का प्रावधान राजस्थान के लिए होना चाहिये था। उसके अनुसार राज्य सरकार को राजस्थान के किसानों के लिए कम से कम 2 अरब रुपयों का प्रबन्ध करना चाहिये था। चाहे वह वित्त निगम के द्वारा हो, सहकारी क्षेत्र की समितियों के द्वारा हो। यह चौथी पांच साला योजना के आखिरी तक राजस्थान के किसानों को दिलाना था। परन्तु राजस्थान सरकार और उसके मंत्रीगणों को इन वायदों के सहारे वोट लेने की आदत पड़ गई है। इन समस्याओं का कोई निराकरण उनके पास नहीं है। उन्हें इन समस्याओं का कोई अनुभव भी नहीं है। 4 करोड़ 38 लाख रुपयों का कर्जा व्यावसायिक बैंकों से

Page No 34

(श्री रामकिशन)

दिला दिया और यह बात आपने हमारे गवर्नर साहब से कहला दी और अब हम से कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्हें धन्यवाद दो। अध्यक्ष महोदय, हमें दो अरब रुपयों का कर्जा इन वर्षों में किसानों को दिलाना चाहिये था उसके स्थान पर यह राजस्थान की सरकार सिर्फ 4 करोड़ 8 लाख रुपया ही दिला सकी है और जो सहकारी बैंक हैं और दूसरी ऐजेन्सियां हैं उनका भी तमाम का कर्जा मिलाकर देखें तो यह 40 करोड़ के आस पास आकर ठहरा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि हमें जितना कर्जा दिलाना चाहिये था उस लक्ष्य का पचास प्रतिशत के आस पास भी हम, हमारी यह समाजवादी सरकार नहीं पहुंच पाई है। जो यह 76 लाख टन के उत्पादन की बात कहती है, अकाल मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी, प्रसन्न हैं कि यह 76 लाख टन अन्न उत्पादन का लक्ष्य हमारे राज्य ने प्राप्त कर लिया है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अन्न का यह रिकार्ड उत्पादन आप की योजनाओं की वजह से नहीं है। योजना कमीशन ने जो टारगेट निश्चित किया था उन सब में हमारा राजस्थान पीछे है। वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। उसे तो हमारे अकाल मंत्रीजी खूब जानते हैं। यही तो हर बार झटके लगते रहते हैं। हमारा स्थायी सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है। यह बात और है कि इस बार हमारे राज्य पर इन्द्रदेव की कृपा रही है और बरसात अच्छी हो गई है। एक साल इन्द्र देव की कृपा नहीं हो, बरसात न हो तो यहां पर क्या हो इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं। राजस्थान का मुकाबला आप दूसरे मुल्कों से तो क्या कर सकते हैं, परन्तु हमारे ही प्रदेशों से कर लिजिए, कहां तक आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम दूसरे राज्यों की तरफ देखेंगे तो उन्होंने स्थायी सिंचित क्षेत्र बना रखें हैं और हम 23 साल बाद यहां पर यह कहते हैं कि हमने 40 हजार हैक्टर में सिंचाई की व्यवस्था की है। इससे अधिक हम नहीं कर पाये हैं। इससे अधिक एरिया में स्थायी रूप से हमारे यहां पर सिंचाई नहीं हो पाती है। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो यह 76 लाख टन का जो लक्ष्य है, उस तक हम नहीं पहुंच सके हैं। बरसात हो जाने और मौसम अच्छा हो जाने के कारण यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि नये बीज और खाद का इसमें योगदान नहीं रहा है। इनका भी उपज बढ़ाने में काफी योगदान रहा है। परन्तु जिस तरह से दूसरे प्रदेशों ने प्रगति की है और कर रहे हैं उस दृष्टि से यहां के किसानों को हम उन्नत नहीं कर पाये हैं। इसलिये जितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वह हमारे यहां पर पूरा नहीं हो पाया है। एक तरफ राज्यपाल महोदय यह कह रहे हैं कि हम इतने क्षेत्र में सिंचाई करेंगे और दूसरी ये आपकी रिकार्ड उपलब्धियां हैं— परन्तु ये नगण्य हैं। इन आंकड़ों को देखेंगे तो समझेंगे कि प्रगति जरूर हुई है, हो रही है लेकिन इनके लिए हमारा जो लक्ष्य है, जो विकास की गति हमने निर्धारित की थी, वह हमने कहां तक पूरी की है इसके मुकाबले में तो आज यह देखेंगे कि यह बिल्कुल ही नगण्य है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ोतरी का लक्ष्य आपने चौथी पांच साला योजना में 7 प्रतिशत रखा था और वह 2॥ से 3

(श्री रामकिशन)

प्रतिशत के बीच इस अवधि में बढा है। यह लक्ष्य आपका रहा है, यह आपने क्या लक्ष्य की प्राप्ति की है ? जो लक्ष्य हमने तय किया था वह राजस्थान की सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए यह सरकार समाजवादी सरकार नहीं है। यह सिर्फ समाजवाद का नारा ही दे रही है। यह समाजवाद के नारे का ही चमत्कार ही है कि इन्दिराजी इस बार भारी बहुमत से आसन पर विराजमान हो गई हैं परन्तु अब इनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा यह कहने कि समाजवाद में यह रोड़ा है। उनको लोक सभा में दो तिहाई बहुमत मिल गया है। यह जैसा चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, जो कदम समाजवाद के लिए चाहे वे उठा सकती हैं। जो हम लोग बाहर रह गये हैं उनकी नीतियों का समर्थन करेंगे। परन्तु यह समय ही बतायेगा कि यह समाजवादी सरकार है या नहीं है। आज तो जिस समाजवाद को यह राजस्थान सरकार यहां पर प्रतिनिधित्व कर रही है, उसने यहां पर अपना जो आचरण पेश किया है जिस प्रकार का आचरण यह यहां पर कर रही है उससे तो यह सरकार समाजवादी नहीं लग रही है। यह तो भ्रष्ट नोकरशाही सरकार है, उसमें कोई नवीनता नहीं नजर आ रही है। यह तो मात्र पूंजीपतियों की सरकार है। इसका कोई कदम समाजवाद की ओर उठता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने, श्री नाईक ने कहा है कि जमीनों पर सीलिंग को कम नहीं करने वाले हैं। आप जमीन की सीलिंग को कम नहीं करेंगे तो गरीबी को कैसे मिटायेंगे। इन्दिराजी ने कहा है कि वे बेरोजगारी और गरीबी को मिटायेंगी। देश में आज स्थिति क्या है और सरकार की योजना क्या है गरीबी को मिटाने के लिये। गरीबी को मिटाने के लिये जो साधन है वह एक ही साधन है जमीन और जमीन की सीमा को आप कम नहीं कर रहे हैं और जो जमीन भी आपके पास में है उसको भी आप गरीबों को नहीं बांट रहे हैं। आज की तारीख तक अध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान की सरकार ने 60 लाख एकड़ जमीन का वितरण किया है, उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन हरिजनों और आदिवासियों को दी गई है और 47 लाख एकड़ जमीन ऐसे लोगों को बांटी गई हैं जिनका धन्धा खेती नहीं है, जो काश्तकार नहीं हैं, खेतीहर नहीं हैं। ऐसे लोगों ने जमीन को हड़प लिया है। आखिर जमीन ही ऐसी है जो गरीबी को मिटा सकती है। गरीबी को मिटाने का यही एक साधन है। पानी का आपने क्या प्रबन्ध किया है ? हमारे प्रदेश में इसकी कमी है। गरीबी मिटाने का दूसरा साधन है उद्योग-धन्धे। परन्तु आज प्रदेश में उद्योग धन्धों की हालत क्या है, उनकी हालत को आप देखें ? गवर्नर साहब ने कहा है कि एक मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में अतुल खनिज सम्पदा है और कहा है कि हमें दुःख है कि हमारा राज्य इस मामले में दरिद्र है। हमारे यहां पर पानी का अभाव रहा है। परन्तु मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पानी के बहाने से आप कब तक लोगों को बहलाते रहेंगे। एक पानी के मामले में ही हम दरिद्र हैं किन्तु कई मामलों में हम सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहला सौभाग्य आपका यह है कि जितनी जमीन

(श्री रामकिशन)

राजस्थान को मिली है प्रति व्यक्ति हिन्दुस्तान में वह कहीं पर भी नहीं है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें प्रति व्यक्ति 1011 प्रतिशत जमीन आती है और आबादी 4 प्रतिशत के करीब आती है। आपकी यह उपलब्धि काफी है फिर क्यों नहीं आप सब को बराबर जमीन दे रहे हैं? यहां की आबादी कम है। दूसरा कारण यह भी है कि राजस्थान का वातावरण शान्त है, इतना शान्त है कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं है। राजस्थान के लोगों की एक परम्परा रही है, एक मर्यादा रही है, वे मीरां और कबीर के भक्त हैं। मीरां के पद, भजन जो गिरधर के चरणों पर ही थी और कबीर के दोहे पर श्रद्धावान है, जो पारलौकिक पदों में रमे रहते है। यह विरासत में यहां के लोगों को मिला है। यहां की जनता कबीर और मीरां के पदों पर ही सन्तोष कर लिया करती हैं। बंगाल की तरह बन्दूक उठाना नहीं जानते हैं। दूसरा फायदा आपको यह भी है कि यहां की आबादी कम है और प्रदेश को शान्ति मिली है संस्कृति से––संस्कृति की परम्परा से हमारा यह प्रदेश धर्म प्रधान रहा है और इसीलिये यहां के लोग 23 सालों के अन्दर आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाये हैं। उनको इन 23 सालों में समाजवाद कितना मिला है? आप भी मानते हैं कि राजस्थान खनिजों के मामले में सौभाग्यशाली है, हिन्दुस्तान के उड़ीसा और राजस्थान ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर खनिजों का बाहुल्य है और यदि इनका विकास, डवलपमेंट ठीक ढंग से किया जाये तो हमारे राजस्व की आधी आमदनी इससे हो सकती है। इनके उद्योग धन्धों में तरक्की हो तो राजस्थान को राहत मिल सकती है। इनमें कम्पीटीशन होना चाहिये जिनसे हमारे यहां पर उत्पादन बढ़े। परन्तु सब जगह ही चीज गिनाते हैं कि हमारे यहां पर मरुस्थल है और इसी पर राजस्थान की जनता को इन 23 सालों से फुसलाते रहे हो। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनियां विज्ञान से कितनी नजदीक आ गई है। हमें विरासत में पानी नहीं मिला है तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिये। विज्ञान की मार्फत इजराइल जैसे देश ने रेगिस्तान में भी हरियाली ला दी है। अरब देशों ने भी अपनी पैदावार को बढ़ा लिया है और जब जोर्डन जैसा देश अपने यहां पर नदी से पानी ला सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या इस तरह हम राजस्थान का विकास नहीं कर सकते हैं। इसके लिये हमारी सरकार की कोई कल्पना नहीं है, योजना नहीं है और यह इस सरकार में अभाव है। केवल आप अपने समर्थकों को झूठे वायदे कह कर, झूठी बातें कर कर उनसे बस वोट प्राप्त करते रहते हैं। इसमें भी आप न कोई मर्यादा का ध्यान रखते हैं, न परम्परा का और न लोकतन्त्र का ध्यान रखते हैं। आप तो यह मानकर चलते हैं जैसे राज गद्दी के मालिक आप ही हैं और आपकी संतानें ही हैं। हमारे यहां इस परम्परा का निर्माण आप जरूर करते जा रहे हैं। यह बहस का सवाल है। आप कहते हैं शान्तिपूर्ण ढंग से आपने चुनाव करा दिये। भीलवाड़ा में बैलेट बाक्सों

(श्री रामकिशन)
को पकड़ा गया, एक पी. डब्ल्यू. डी. की जीप थी, इसका स्पष्टीकरण जो आप चाहें वह दें . . .

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : आप क्या कह रहे हैं ? आप गलत कह रहे हैं। वहां कोई बैलेट वाक्स नहीं पकड़ा गया है। यह आश्चर्य की बात है। यह भी कहते हैं कि केमीकल का प्रयोग किया गया। आश्चर्य होता है, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : आप मेरी सुन तो लें। अगर आप सुन लेते तो आश्चर्य नहीं होता।

(व्यवधान, अश्रव्य)

अगर अध्यक्ष महोदय, नाहर साहब मेरी बात सुन लेते तो मेरी तारीफ करते, नाराज नहीं होते। नाहर साहब आजकल ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं जबकि इस उम्र में होना नहीं चाहिये।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि बैलेट बाक्सेज में क्या था ? वे पर्देवाली चार औरतें कहां चली गई, वह जीप का ड्राईवर कहां भाग गया और फिर कैसे पकड़ा गया। ये सब बातें क्या हैं ? मैं तो अध्यक्ष महोदय चाहता हूं हिन्दुस्तान की पवित्रता के लिये ये बातें झूंठी निकलें अन्यथा देश में अराजकता फैल जायगी, हिंसा और मार-काट हो जायगी क्योंकि अब लोग बकसने वाले नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ झूंठी निकले आप ही बतायें ड्राइवर जीप छोड़कर क्यों भाग गया, पर्देवाली औरतें भागकर क्यों चली गई। आखिर भागने का कारण क्या था ? कोई गड़बड़ी होती हैं तभी ऐसे कारण बनते हैं।

सरकार कहती है हमने लोकतन्त्र की सेवा की है। शिवचरणसिहजी है, डिप्टी मिनिस्टर हमारे इलाके के उनसे पूछ लिया जाय हमारे कण्डीडेट के जो पोलिंग ऐजेन्ट थे उनके साथ क्या बीती है। हमारे पोलिंग ऐजेन्टों को बान्ध दिया गया, उनको मारा गया है और वहां से भगा दिया गया है। शिवचरणसिहजी सब जानते हैं। पहले हमारे पोलिंग ऐजेन्टों को बान्धा गया, मारा गया और वहां से भगा दिया गया। यह शिवचरणसिहजी खुद जानते हैं। सदन में नहीं कहेंगे किन्तु अलग से आप पूछेंगे तो कह देंगे। यह तो आप लोगों की हालत है।

राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है इसमें कहीं समाजवाद की दिशा नजर नहीं आती है बल्कि चौमुखी विनाश की तरफ जाती हुई दिखती है। हमारी खेती की जो स्थिति है उसको निवेदन किया, रोजगार की दिशा को निवेदन किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार से एक बात कहनी है हमारे राज्य में खेती की जो सम्भावनायें है उस पर राज्य चल पड़ा है केवल जरूरत है पानी की और बिजली का प्रबन्ध कर दें। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने बताया 2800 गांवों में बिजली जा पाई है। उन गांवों में सब जगह कनेक्शन हो गया हो, यह बात नहीं है। केवल आंकड़ों की बात जरूर है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी बिजली का विकास इसी गति से रहा तो राजस्थान में हम

(श्री रामकिशन)

30-40 साल से पहले अपने खेतों को पानी नहीं दे सकेंगे। राजस्थान सरकार कहती है अब हमने जो योजना बनाई है उसमें हमारे बजट का 63 प्रतिशत खर्चा पानी और बिजली पर करना चाहती है। 23 वर्षों में देखें तो राजस्थान सरकार ने मूल रूप में खेती का विनाश ही किया है। अगर खेती के बारे में पहले ही इस प्रकार का जोर दिया जाता तो आज यह विनाश नहीं होता। हम खेती के मामले में पिछड़ गये। खेती के विकास की जो गति बनी है उस पर हमें विचार करना चाहिये। हमारे राज्य में दो बड़ी चीजें हैं एक तो खनिज सम्पदा और दूसरे उद्योगों के विकास का कार्यक्रम।

अध्यक्ष महोदय, अखबारों में कई बार पढ़ने को मिला है कि मुख्य मंत्रीजी हर महिने उद्योगपतियों को निमंत्रण देते फिरते हैं। कभी कहते हैं इसका परमिट ले ले, इसका लाइसेन्स ले ले, सारी सुविधाओं का जिक्र करते रहते है किन्तु उनको परमिट और लाइसेन्स देने से पहले ही शर्त रख देते है कि तुमको पार्टी के इलेक्शन के लिए इतना चन्दा देना पड़ेगा तो वह उद्योगपति वहीं ठप्प हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारी सारी खनिज सम्पदा की बात निरर्थक और थोथी रह जाती है। यह हमारे राज्य की खनिज सम्पदा की स्थिति है। इन चार पंचवर्षीय योजनाओं में कोई हमारी सारी खनिज सम्पदा का कार्य हाथ में नहीं लिया गया है जबकि हमारे पास इतनी बड़ी सम्पदा है। उस दृष्टि से देखें तो अध्यक्ष महोदय, हमारी जो आमदनी बढ़ाने का तरीका है और हमारे राज्य की आय में जो उसका अंश दान है वह बढ़ा नहीं बल्कि स्थिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी खनिज सम्पदा का 55-56 में जीरो दशमलव पचपन का हिस्सा था-राज्य की आमदनी में। 60-61 में जीरो दशमलव 80 था इसके बाद एक दशमलव 21 रहा और अब जाकर 70 में एक दशमलव जीरो पांच केवल हमारे राज्य का अंशदान रह गया है। जहां राज्य में खनिज सम्पदा में बढ़ौतरी होनी चाहिये वहां खनिज सम्पदा के मामले में बहुत कम विकास हो पाया है बल्कि कहना चाहिए कि विकास स्थिर रहा है और पिछले वर्षों में राज्य की आमदनी गिर गई। हमारे राज्य की हालत तो यह है कि जितने जितने प्रमुख प्रमुख खनिज हैं वे सब मिलते हैं। खनिजों के मामले में हमारी मोनोपोली है, जितना जिप्सम देश में मिलता है उसका अधिकतर भाग हमारे राज्य में मिलता है। सौपस्टोन की मात्रा 95 प्रतिशत हमारे राज्य में उपलब्ध है। राजस्थान में सिल्वर और माईका 22 प्रतिशत मिलती है, लाइम स्टोन 13 प्रतिशत मिलता है। इससे अध्यक्ष महोदय विचार कर सकते है हमारे राज्य के विकास की बड़ी भारी सम्भावनायें है लेकिन राजस्थान सरकार ने खनिज का सही ढंग से उपयोग नहीं किया। क्यों नहीं उपयोग किया क्योंकि कोई भी उद्योगपति से बात हो तो पहले चन्दे का फैसला हो जाय। चुनाव के चन्दे के फैसला पहले तय हो जाय तो खान का ठेका हो जाय नहीं तो ठेका नहीं मिलेगा। हर मामले चन्दे से चलते है। इतना भी इन्तजार नहीं करते कि किसी उद्योगपति को पहले लाइसेन्स

(श्री रामकिशन)

परमिट दे दें और उसके बाद में उससे मांग लें लेकिन यहां तो पहले ही शर्त लगा दी जाती है। चुनाव का चन्दा तो आपको बाद में मिल सकता है लेकिन आने वाले उद्योगपति से पहले चन्दे की शर्त लगा देते हैं इसलिए वह लगा नहीं पाता है।

उड़ीसा राज्य का उदाहरण लीजिये जिसकी खनिज सम्पदा हमारे से कम है। मैं और राज्यों का तो उदाहरण ही देना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी खनिज सम्पदा तो हमसे बढ़ी हुई भी है और हमसे कम भी है। उड़ीसा राज्य ऐसा राज्य है जो हमारे राज्य के समान खनिज सम्पदा रखता है। आज उड़ीसा की आमदनी देखें और हमारे राज्य की आमदनी देखें तो बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देगा। हमारे राज्य की खनिज सम्पदा दो करोड़ 84 लाख के करीब है। लेकिन जब उड़ीसा और हमने दोनों राज्यों के खनिज सम्पदा का काम शुरू किया था तब उस समय की आमदनी और आज की आमदनी में 8 करोड़ रुपयों का अन्तर है। उड़ीसा की आमदनी 11 करोड़ है और जबकि हमारी खनिज सम्पदा की शुद्ध आय तीन करोड़ है। इसका कारण क्या है ? न तो कारखानों का सर्वे कराया गया है और यहां तो उलटा मामला है अध्यक्ष महोदय, कारखानेदार विभाग के पास स्वयं जाकर पहुंचता है। होना यह चाहिए कि विभाग को कारखानेदार के पास पहुंचना चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य है घर घर में, दुकान दुकान में, हर गांव और शहर में इसकी पब्लिसिटी करें जिस प्रकार आप परिवार नियोजन का प्रचार करते हैं उसी प्रकार खनिज सम्पदा का भी प्रचार करें। जिस प्रकार के कारखाने बनाये जा सकते हैं उस प्रकार के साधन बना सकते हैं लेकिन आज राजस्थान के बाहर शायद ही कुछ पढ़े लिखे लोगों के अलावा मालूम नहीं है कि राजस्थान में कितनी खनिज सम्पदा है। सीमेन्ट के कारखाने आज राजस्थान में खुल सकते हैं जिस तरह की सीमेन्ट बनाई जाती है उसमें सफेद और रंगीन सीमेंट भी बनाई जा सकती है। आज उसकी बड़ी भारी मांग है। आप चिप्स के उद्योग पर विचार करें जिप्सम की बम्बई और कलकत्ता में खपत है। हमारे राज्य की इससे बेरोजगारी मिटेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम तो हमारे ढंग से, उसी पुरानी परम्परा से चल रहे हैं। जबकि जरूरत इस बात की है कि खनिज के मामले में तेजी से आगे बढना चाहिए।

बयाने में डकैती हुई आपने उस मोशन को स्वीकार नहीं किया कुछ लड़कों ने जो अलीगढ़ और मेरठ के रहने वाले थे दिन दहाडे लूट कर ले गये। बैर कस्बे के एक माली के यहां से सारा धन लूट कर ले गये और जब पकड़े गये तो कोतवाली में क्या बयान दिया ? हमारा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है यह एक गंभीर चिन्तन का विषय है। उन्होंने बताया हम पढ़े लिखे लोग हैं, एम० ए० किया, बी० ए० किया है, आमदनी का कोई जरिया नहीं, खर्चा ज्यादा है इसलिये डकैती डाली है। हम नक्सलियों का समर्थन करते हैं। आप जरा सोचिये यह बयाने की बात नहीं है, केवल बयाने की घटना का संकेत नहीं है। 8 आदमियों ने 5 हजार की डकैती डाली और माल लूट ले गये। मैंने इस प्रवृत्ति इसे सरकार को चिन्तित

(श्री रामकिशन)
होने के लिये कहा है, सरकार को तैयार हो जाना चाहिये और वह कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिये जिससे हमारे देश की बेरोजगारी घटे। आज उद्योगों के विकास की स्थिति है हमारी प्रकृति ने जहां रेगिस्तान दिया है वहां हमारे साथ न्याय भी किया है और प्रचुर मात्रा में हमें पशुधन दिया है। पशुधन पर कितने उद्योग चलाये जा सकते हैं, इस पर हमारी सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। हम इस नाम पर दो तीन मिल गिना देते हैं जबकि हमारे राज्य का विकास अन्य राज्यों से बहुत कम है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह देते हैं पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी और असलियत को छिपाने की कोशिश करते हैं। अब पूर्ति हो गई तो हमें खेती के कार्यक्रम पर सुदृढ़ और निश्चित योजनाओं पर आगे बढ़ना चाहिये। अब जरूरत इस बात की है कि हम खनिज के विकास के लिए और उद्योग के विकास के लिए मास्टर प्लान बनायें और एक टारगेट निश्चित करें कि आने वाले समय में हमें इन इन उद्योगों को विकसित करना है और यदि आपने खनिज सम्पदा का विकास नहीं किया, उद्योगों का विकास नहीं किया तो अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि इस देश का भविष्य अच्छा नहीं है। केवल चुनाव जीत जाना और दिल्ली की कुर्सियों पर पदासीन हो जाना, इससे काम नहीं चलेगा। जो लोग पदासीन हुए हैं और चुनाव जीतकर आये हैं उनके सामने चुनौतियां हैं। आपने 23 साल तक का समय बिताया लेकिन इन पिछले पांच सालों में जिस तरह की घटनायें हुई उसके हिसाब से लोग अब पकड़ना चाहेंगे। लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी का तत्काल इलाज हो, गरीबी का तत्काल इलाज हो। तत्काल से मेरा मतलब कोई घन्टे दो घन्टे से नहीं है। तत्काल से मेरा मतलब यह है कि शीघ्र ही इन दोनों बातों का इलाज होना चाहिए और अगर आप बेरोजगारी और गरीबी का इलाज तत्काल करने की स्थिति में नहीं हैं तो हिंदुस्तान का नौजवान आपकी इन्तजार नहीं कर सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बात को तो मैं समझता हूं, प्रधान मंत्री जी भी समझती हैं और मुख्य मंत्री जी भी समझते हैं कि चुनावों में आप राजा महाराजा और सेठ साहूकारों का नारा देकर आप सफल हो गए और उनसे जीत गये लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह तो बहुत आसान है। आप सच बोलकर चुनाव जीते हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं और अगर झूठ बोलकर भी जीते हैं तो भी मैं आपको बधाई देता हू। इसका हमें अफसोस नहीं है कि हम चुनावों में पराजित हुए।....

श्री मदनसिंह : राजा महाराजा जीते हैं।

श्री रामकिशन: मैं तो मेरी बात कह रहा हूं। आप तो राजा हैं ही। मैं निवेदन कर रहा था कि आप जीत गये आपको बधाई लेकिन आपके पास अब कोई बहाना नहीं है। लोकसभा के चुनावों में जीत जाने के बाद अब आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा बहुमत नहीं अब आप नहीं कह सकते कि हमारे पास बहुमत नहीं होने के कारण से

(श्री रामकिशन)

हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब तो आ फटाफट संशोधन कर सकते हैं और आप चाहे जब कर सकते हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी आपने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा है ? जरूर पढ़ा होगा। उसमें क्या एक भी लाइन समाजवाद के बारे में है ? क्या उसमें कोई समाजवाद की ओर कोई दिशा है खेती के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार के मामले में या शिक्षा के मामले में है क्या कोई दिशा ? क्या किसी मामले में समाजवादी दर्शन है। वैसे इस अभिभाषण में शिक्षा का भी जिक्र किया गया हैं। राजस्थान की शिक्षा की हालत क्या है। आप एस. टी. सी. ट्रेण्ड बैठे हैं। धौलपुर में भूख-हड़ताल कर रहे हैं। आप उनकी मत सुनो लेकिन आप उनको कम से कम काम तो दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उनको क्या काम दें तो उसके बारे में मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं और वह सुझाव यह है कि राजस्थान में पढे लिखे 88 हजार हैं और ट्रेनिंग किये हुए 16–17 हजार हैं। आप उनको तत्काल मास्टर बनाओ लेकिन आप चाहें तो आप एक साक्षर सैना बना सकते हैं और आप उनको कह सकते हैं कि हम आपको 40–50 रुपया महीने का देंगे और तुम सारे लोगों को साक्षर बनाओ। अगर आप इस तरह का अभियान चलायें तो जो हमारे नौजवान बेकार हैं जो कभी तो नकसलियों की पूजा करते हैं, कभी माओ की पूजा करते हैं, कभी लेनिन की पूजा करते हैं और कभी किसी की पूजा करते हैं। तो कम से कम हम यह तो कर सकते हैं कि जो आपने 3।। करोड़ रुपये की योजना का बेरोजगारी मिटाने का प्रावधान किया है मैं कहता हूं कि जो ट्रेण्ड एस. टी. सी. हैं इनको आप 50–60 रुपया दो और एक टारगेट निश्चित कर दो कि इस गांव में एक साल के अन्दर सबको साक्षर करना है और इस टारगेट को जो पूरा कर देता है आप उसको विशेष प्रोत्साहन दे सकते हैं और सरकारी नौकरी में ले सकते हैं और अभी जो युवाशक्ति का विकास हो रहा है उसमें विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका दृष्टिकोण है क्या ? आपने इस ओर कोई दिशा दी है क्या हम दूसरे मामलों में पैसा बरामद करते हैं, अनाप-शनाप बजट का पैसा बरबाद होता है लेकिन जिन कामों की जरूरत है वह हम नहीं करते हैं।

इस संबंध में दूसरा और सुझाव है। सिचाई मंत्रीजी यहां नहीं हैं उन्होंने राजस्थान नहर का जिक्र किया। यह कई बार चर्चा हो चुकी है कि राजस्थान का नेतृत्व कमजोर है, उसमें कोई दम नहीं है। अगर दम है तो यह राष्ट्रीय योजना है और अभी तक राज्य के पास है और केन्द्र सरकार पर इसको हाथ में लेने के लिए पूरा दबाव नहीं डाला गया। आप सारा पैसा राजस्थान नहर पर लगायें इससे मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी पूरी हो लेकिन अकेले राजस्थान की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि इसको पूरा कर ले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भरतपुर जिले के बारे में कि वहां पर 32 बांध टूटे हुए पड़े हैं। यह बांध कोई आपने नहीं बनवाये। यह बनवाये हैं राजा महाराजाओं ने आपकी निगाहों में ऐयाशी थे, पूंजीपति थे और सामन्ती थे, उन्होंने बनवाये थे और अब राजस्थान सरकार

(श्री रामकिशन)

उनकी मरम्मत भी नहीं करा पा रही है और जब यह स्थिति है तो वहां के लोग आपको प्रगतिशील कैसे मान लेंगे ? वहां पर कुल 264 बांध बनवाये और आज उनमें से 232 बांध टूटे पड़े हैं। आज सुखाड़ियाजी बड़े जोरों से कहते हैं कि हमने भरतपुर के महाराजा को हरा दिया, हमने राजस्थान में दो सेठों को हरा दिया तो अब आप इन्दिराजी से कहिए कि इस राष्ट्रीय महत्व की नहर को तो मान लें और अपने हाथ में ले लें। लेकिन आप यह नहीं करेंगे आप तो वहां जाते हैं और क्या करते हैं कि वहां जाकर इस चक्कर में घूमते हैं कि वहां पर किस को मंत्री बनाते हैं। आप यह मत समझना कि राजबहादुरजी कोई केबिनेट मंत्री हो गए तो हमारे लिए वबाल बनेंगे। आपकी राजनीति को आप ही जानें। यह जो राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं इनको छोटी राजनीति के साथ मत जोड़िये। आपको इन चीजों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर जो मुद्दे उठाये हैं विकास के संबंध में, राजस्थान सरकार की जो दिशा है, राजस्थान सरकार का जो दृष्टिकोण है चाहे खनिज सम्पदा हो, चाहे दूसरी सम्पदायें हों वह दृष्टिकोण क्रांतिकारी दृष्टिकोण नहीं है, निर्माणकारी दृष्टिकोण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगा राजस्थान की पुलिस के सम्बन्ध में। आपने कहा है कि राजस्थान की पुलिस ने डकैतों के पकड़ने में बहुत प्रगति की है। अभी कुछ दिन पहले राजाखेड़ा थाने में हमारे डिप्टी मिनिस्टर श्री प्रद्युम्नसिंह जी बैठे हैं। वहां पर गांव से एक मोहरसिंह नाम के एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ लाई। मोहरसिंह जाति का राजपूत है और उसके 7 बच्चे हैं। पुलिस मोहरसिंह को 28 दिसम्बर को पकड़ कर लाई घर से और कहा कि थाने में चलो। उसका दो दिन तक पता नहीं चला कि कहां है और एक तारीख को उसको पुलिस की वर्दी पहना कर जंगल में ले जाकर गोली मार दी। अध्यक्ष महोदय, ऐसी अमानवीय वारदात हो जाये तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए एजीटेशन हुआ और उसके बावजूद भी कोई सुनाई नहीं है। एक गरीब जो कि डकैत हो, चोर हो, लेकिन बैंक का गबन था उसमें चालान हुआ था और हाई कोर्ट में केस चल रहा था और पुलिस वाले उसको पकड़ कर लाये और पुलिस की वर्दी पहना कर उसको गोली मार दी गयी। यह सूचना मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचा दी गयी है, गृह, सचिव तक पहुंचा दी गयी है, गृह मंत्री जी के पास भी पहुंचा दी गयी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वैसे हमारे जिले में डकैती उन्मूलन हुआ है और इसकी मुझे खुशी है लेकिन डकैतों के नाम पर निरपराध लोगों की आप हत्या कर दें इससे तो राजस्थान सरकार की बदनामी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह निवेदन करूंगा कि आपका यह समाजवाद का मायाजाल है। अब यह मायाजाल 6 महीने में हटने वाला है। हम तो समाजवाद का नारा बहुत पहले से लगाते थे लेकिन हम शक्तिहीन थे और हमारी बात किसी ने नहीं सुनी और आपने

(श्री रामकिशन)

नारा लगाया 6 महीने से। लेकिन जो समाजवाद की कसौटी है जमीन का वितरण, धन का वितरण, आमदनी की समानता और समानता के माध्यम से समानता, राष्ट्रीय उद्योग का विकास होना चाहिये और इन सारी सम्भावनाओं की कसौटी पर हम कसें तो मैं समझता हूं कि आज सरकार चाहे चार साल और ले ले लेकिन आज तक की दिशा बिड़ला और टाटा बनाने की दिशा रही है, समानता वाली दिशा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस तरह सरकार समाजवाद लायेगी। आप सीलिंग के लिए कह रहे हैं कि हम जमीन बांटेंगे लेकिन जमीन है कहां जिसको आप बांटेंगे। जमीन जितनी बंटनी थी वह लोगों ने पहले ही बांट दी। तो असल में आप समाजवादी नहीं हो आप तो केवल चोरों को सूचना दे रहे हो कि हम तुम्हारे घरों में चोरी करने वाले हैं और इस लिये तुम अपने सामान को हटा लो। कांग्रेस के समाजवाद के नारे के साथ साथ स्वतंत्र पार्टी ने भी समाजवाद का नारा दिया। मैं उनको एक सुझाव दूंगा कि आप समाजवाद को सिद्धान्त रूप में नहीं बल्कि टैक्निकल रूप में अपनाओ। जन संघ भी अपनाये और आस्था के रूप में आपको अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनायेंगे तो परिणाम सामने देख रहे हैं। आप पहले 93 थे और 4–5 महीनों में समाजवाद की छाया फैलेगी तो घट कर 3–4 ही रह जायेंगे और तुम्हारे साथ-साथ हम भी पिस जायेंगे। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि समाजवाद देश की अनिवार्यता है। देश को समाजवाद की जरूरत है और समाजवाद देश का एक धर्म है। इसके विपरीत आचरण करेंगे तो टिक नहीं सकते, जीते नहीं रह सकते। क्या इनमें (कांग्रेस पक्ष) सारे समाजवाद का आचरण करने वाले हैं ? अभी श्री नाइक ने सीलिंग कम करने के लिए इन्कार कर दिया, लेकिन वह करनी पड़ेगी। जापान में 7 एकड है काश्तकार काम चला सकता है। वहां पर अधिक से अधिक सिंचित भूमि 7 एकड है और कम से कम 3 एकड है, तो आप यहां 20–25 एकड रख लें अगर गरीबी मिटाना चाहते हैं तो। मैं सारी बातों की चर्चा नहीं करूंगा। केवल समाजवाद के नाम का जाप करने से समाजवाद नहीं आयेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन के माननीय सदस्यों को कहूंगा कि अभिभाषण के लिये धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अगर कर सकें तो निन्दा जरूर करें और निन्दा करके सरकार को किसी मजबूत तथ्य पर अपने कदम बढाने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को और चुनाव के दिनों में सरकार द्वारा जनता को दिये गये आश्वासन इन दोनों के सामन्जस्य की दृष्टि से यदि देखा जाय तो मुझे कहीं भी किसी प्रकार का सामन्जस्य नजर नहीं आता। सदन के माननीय सदस्य और इस राज्य की सारी जनता इस बात से परिचित है कि चुनावों के दिनों में सताख्ढ दल की ओर से गरीबी

(श्री भैरोंसिंह)

मिटाने, भुखमरी मिटाने, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने, गरीबी और अमीरी के बीच में जो असमानता है उसको दूर करने आदि ऐसी कई बातों का आश्वासन दिया गया है । यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार का आश्वासन देकर विजय प्राप्त करने वाले दल से जनता इस बात की अपेक्षा करे कि राजस्थान विधान सभा के बजट अधिवेशन के आरम्भ में या लोक सभा के आरम्भ में भारत सरकार द्वारा और राज्य की विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा कुछ इस बात के संकेत दिये जायेंगे कि किस तरह से इन आश्वासनों की पूर्ति हो सकेगी । मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस अभिभाषण में और अब तक राज्यपाल महोदय के जो अभि-भाषण हुए हैं उनमें यदि किसी प्रकार का कोई अन्तर है तो वह केवल एक ही बात का अन्तर मिलेगा कि पिछले अभिभाषण कुछ अंश के साथ सार्थक थे तो यह अभिभाषण पूर्णतया निरर्थक है । यदि यही हमको संकेत मिलता है कि इस प्रकार से आश्वासनों की पूर्ति होगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा मैं उसका उल्लेख आगे करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह आज सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में सिवाय एक बिहार को छोड़कर प्रति व्यक्ति आय सब से कम है । अध्यक्ष महोदय, यह भी आज दुनियां जानती है कि हमारे देश की नेशनल ग्रोथ का जो पर्सेन्टेज है वह अन्य देशों के मुकाबले में बिलकुल ही कम है, और यदि मैं यह कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी कि हमारी नेशनल ग्रोथ इकानामिक पाइन्ट आफ व्यू से अन्य देशों से सबसे कम है, तो ज्यादा सही होगा इसी आधार के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, इस देश में हमारे राज्य की जो इकानामिक ग्रोथ का जो पर्सेन्टेज है वह अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ यह भी बात सही है कि हमारे देश पर लगभग सात हजार करोड़ रुपयों का कर्जा है, और उस कर्जे में हम भी भागीदार हैं, और हमारे प्रदेश पर लगभग 600 करोड़ रुपये का कर्जा है । अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश को इस बात का परिचय है कि देश में केन्द्रीय सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से स्वायत्त–शासन संस्थाओं की ओर से पिछले वर्षों में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के टैक्सेज लगाये जा चुके हैं । आज जितने भी इकानामिक एक्सपर्टस हैं वे चाहे टैक्सेशन के मामले के हों उन्होंने अध्ययन किया है, छोटी आय के मामले में अध्ययन किया है, सब दुनिया के लोग यह मान कर चलते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर टैक्स अब नहीं लगाया जा सकता है । टैक्स लगाने की गुन्जाइश सेच्यूरेशन पाइन्ट के ऊपर पहुंच गई है और यदि आज टैक्स लगाने का प्रावधान रखते हैं तो लोगों की रोटी पर उसका असर पड़ेगा और लोगों की इकानामिक कन्डी-शन्स और भी ज्यादा खराब होगी ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ बेरोजगारी का प्रश्न है । मैं ऐसा समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में कितने बेरोजगार हैं उसके अलग अलग सूत्रों से अलग अलग

(श्री भैरोंसिंह)

आंकड़े उपलब्ध होते हैं । अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि लगभग साढ़े चार करोड़ बेकार आज हिन्दुस्तान में हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार की यदि पत्रावली को देखा जाय तो जिस प्रकार से उन्होंने बेकारों की तीन श्रेणियां की हैं–पूर्ण बेकार, अर्द्ध बेकार और मौसमी बेकार–उन सारे बेकारों की संख्या लगभग साढ़े तेरह करोड़ आती है। साढ़े तेरह करोड़ में से राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार लगभग 13 लाख बेकार हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो पहले प्रारूप राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था उस प्रारूप में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब तक चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार वर्तमान आकार से छः गुना नहीं बना दिया जाय तब तक राजस्थान में जो प्रति वर्ष बेकारों की संख्या आती है हम उस संख्या को भी रोजगार दे सकें इस प्रकार की स्थिति नहीं है । उस आधार पर यह विचार करें कि राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना का आधार जो प्रारम्भ में बनाया गया और जिस आकार के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इस आकार को छः गुना बढ़ाये बिना काम नहीं चल सकता है तो उस आकार से चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो अब राज्य सरकार ने बनाया है, जो टार्गेट फिक्स किये हैं, जो फण्ड्स का एलोकेशन किया है, वह कम है । उस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान में जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या है उस बेकारी समस्या का समाधान राज्य सरकार कर पायेगी, इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर जो मंहगाई है उससे राजस्थान की और सारे देश की जनता पीड़ित है। यदि इस मंहगाई के लिए 61–62 को बेस ईअर मान कर चलें तो 20–8–68 को प्राइस इन्डेक्स 163 पहुंच गया, 10–7–69 को 174 पहुंच गया और 18–7–70 को 180–6 पहुंच गया, और उसके वाद 0–6 उसमें इजाफा हुआ है । तो उस स्थिति में हमें यह मन्जूर करना पड़ेगा कि पिछले वर्षों से लगातार मंहगाई बढ़ती जा रही है। हम मंहगाई रोकने की चर्चा अवश्य करते हैं लेकिन वास्तव में मंहगाई पर कण्ट्रोल नहीं होता है । मंहगाई बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, यह आप को जानकारी होगी कि हिन्दुस्तान का जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, उसका इजाफा जिस प्रकार हुआ है 1960–61 में, सबसे गरीब इस तबके को माना जाता है । रिजर्व बैंक ने अपने एक जरनल में यह बताया है कि यह स्थिति 67 तक पहुंच गई है। आप इससे आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। हम इस बात का अन्दाजा लगा कर चलें कि राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार का अभिभाषण दिया है, उसमें किसी प्रकार का संकेत मिलता है जिसके आधार पर सन्तोष किया जा सकता हो या जनता को सन्तोष दिया जा सकता हो।

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के लिए राज्यपाल महोदय ने पेज 6 पर कहा है, जिसका जिक्र भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया हैं,–'अभी हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी को घटाने की दृष्टि से एक योजना स्वीकृत की है। जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए प्राथमिकता उन परिवारों को दी जायेगी जिनमें अभी कोई भी व्यक्ति नहीं कमा रहा है।

मैं समझता हूं प्राथमिकता देने की बात यह पहली बार राजस्थान सरकार ने स्वीकार की है। इस प्रकार की मांग विरोधी दल के सदस्यों द्वारा पहले भी उठाई गई है। चाहे वह भूमि के अलाटमेण्ट का प्रश्न हो, चाहे काटेज इण्डस्ट्री में ऋण देने का प्रश्न हो, सदन में कई बार यह रखा गया है कि जिन लोगों के पास काम का कोई साधन नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाये। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने इसको अपने अभिभाषण में स्थान दिया है। मैं राज्य सरकार से एक बात पूछतां हूं कि क्या राज्य सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि भविष्य में चाहे अलाटमेण्ट का प्रश्न हो, चाहे कर्ज देने का प्रश्न हो या नौकरी देने का प्रश्न हो–किसी प्रकार का प्रश्न हो राज्य सरकार इस नीति को लेकर चलेगी? जैसे कि एक परिवार में किसी प्रकार का रोजगार नहीं है तो उसको प्राथमिकता दी जायेगी? अगर यह सिद्धान्त स्वीकार करते हैं, तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीबी और भुखमरी मिटाने के लिए पिछले 10 वर्ष के कारनामों को देखना पड़ेगा। आप को समान रूप से पूंजी को वितरित करना होगा। यदि एक व्यक्ति ने सत्ता के आधार पर पूंजी अकेमुलेट करने की कोशिश की है? तो पहला काम राज्य सरकार का यह है कि जिन लोगों ने अपने खुद के व्यक्तित्व के आधार पर यह किया है, सबसे पहले उसका बाइफरकेशन किया जाएगा। उनका वितरण किया जाय। तो जनता के सामने हम बहुत बड़ा उदाहरण रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो उससे यह समझ कर कोई चले कि एक जिले में एक हजार लोगों को काम दिया जायेगा, रोजगार दिया जाएगा–मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस दृष्टि से राजस्थान में जिस प्रकार की भूमिका है उस भूमिका के आधार पर राज्यपाल महोदय ने राजस्थान की इस ज्वलन्त समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, इसका कोई संकेत नहीं किया है। इस संकेत के अभाव में किसी भी प्रकार के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करना किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चुनावों की दृष्टि से एक बात राज्यपाल महोदय ने अवश्य कही है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से लोक सभा भंग की गई थी और चुनाव कराये गये। मैं समझता हूं कि इससे

(श्री भैरोंसिह)

ही समाजवाद आने वाला नहीं है । चुनाव में बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल गया । सरकार उन लोगों की समस्या को किस प्रकार हल करने वाली है, यह विचार करें तो समय लगेगा । बाद में क्या परिणाम निकलेंगे, वह हम सब देखेंगे । लेकिन इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का यह कहना कि चुनाव बहुत ही शान्तिपूर्ण हुये हैं, मैं समझता हूं कि वास्तविकता को छुपाने का प्रयास किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने चुनाव लड़े हैं । सन् 1952 से चुनाव लड़ते आये हैं । सन् 1952 में स्व. पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जिस किसी को कांग्रेस का टिकट दे देंगे वही आ जाएगा । जनता उसी को वोट दे देगी । 1952 में जनता ने पार्टी देखी । 1957 में जनता ने पार्टी भी देखी और केण्डीडेट भी देखा । 1962 में भी जनता ने पार्टी देखी केण्डीडेट भी देखा । लेकिन पार्टी के माध्यम से नहीं जीत सकता । पर्सनलिटी से भी नहीं जीत सकता । जिसके पास दण्ड होगा, वह जीत सकता है । 62 से 67 तक यह प्रभाव बढ़ता ही गया । लेकिन अफसोस की बात यह है कि 67 से दण्ड की बहुत जबरदस्त आवश्यकता हुई । अब यह निर्णय हो चुका है कि जिसके पास साधन होंगे, जिसके पास आदमी होंगे, जिसके पास दण्ड होगा वही चुनाव जीत सकता है । इसका मतलब मोटा यह निकाल सकते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड सकता है । साधनहीन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है तो डेमोक्रेसी का यह परिणाम निकला है कि कोई व्यक्ति बिना इन सब चीजों के चुनाव नहीं लड सकता है और न चुनाव जीत सकता है । तो हम लोकतन्त्र का मजाक कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाये कि कांग्रेस में किसको क्या साधन मिले ? कहां से मिले ? कितना धन कहां से मिला ? किससे मिला ? कांग्रेस विरोधी दल पर यही आरोप लगायेंगी । आप लोगों ने पैसा कहां कहां से लिया है ? किस व्यापारी से, किस कम्पनी से ? किस लाइसेन्स या परमिट के आधार पर लिया है ? यह सारा अकाउण्ट राजस्थान विधान सभा की मेज पर रख दें । किस रूप में कहां से धन लिया है ? हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना होगा, यदि आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहें तो यह उचित न होगा । अध्यक्ष महोदय, मै यह मान कर चलता हूं । पेम्फलेट चाहिए, पोस्टर चाहिये छपाई चाहिए । यह खर्चा होता है । उस खर्च के लिए राजनैतिक दल चन्दा भी करते हैं लेकिन चन्दा करने की कुछ सीमायें हैं, चन्दा किस प्रकार लिया जाय उसकी कुछ व्यवस्था है । आज विरोधी दल के कोई चन्दा लेंगे तो भिखारी के रूप में जाकर खड़े हों, उनके पास डण्डा नहा है । वह किसी को ओब्लाइज कर सकते हों–इस प्रकार की स्थिति में नहीं हैं । हम लोग चन्दा उगाते हैं, लेकिन कोई दस, कोई पांच और कोई ज्यादा से

(श्री भैरोंसिंह)

ज्यादा कृपा करे तो सौ रुपये इस प्रकार चन्दा देता है । इस प्रकार चन्दा लेते हैं, इसमें शक नहीं है । यह आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बने, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा लें–इससे अपने को प्रसन्न कर लें कि हमने विधान सभा में यह कहा, उन्होंने यह कहा । इन सारी चीजों की जड़ में बुराई को खत्म करने की चेष्टा हो–ऐसी व्यवस्था करे, वालियन्टरीली व्यवस्था करें । पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारायें मजबूर करने के लिए आयें इसको देखने की आवश्यकता नहीं है । सब पार्टी मिल कर फैसला करें । मैं मेरी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, बाकी के आप लोग तैयार हों तो मैं चुनाव के एक एक पैसे का हिसाब, चुनाव में जो एक एक पैसा लिया है उसका हिसाब विधान सभा की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं । मैं चाहूंगा राजस्थान सरकार इस चन्दे के मामले को विधान सभा की टेवल पर प्रस्तुत करे ताकि तस्वीर जनता के सामने आ सके कि किस किस से पैसा लिया है। यह कह कर चलना कि इधर से पूंजी पति, राजा-महाराजा, चुनाव लडे हैं, और कांग्रेस की तरफ से गरीब चुनाव लडे हैं। मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे, गरीब चुनाव लडे, राजा महाराजा, सेठ साहूकार चुनाव लडे इससे इन्कार नहीं कर सकते, कुछ तो सेठ-साहूकारों के शरीर कांग्रेस साइड में थे, लेकिन यह अपने पैसे से चुनाव लडे । लेकिन बाकी जो चुनाव में लडे, कांग्रेस पार्टी जो पैसा खर्च कर रही थी, वह जो रुपया लगा रही थी चुनाव में, वह सेठ-साहूकारों का पैसा था । इसलिए उनका रुपया तो जीत गया, लेकिन उनका शरीर हार गया । कांग्रेस जीती है या विरोधी दल हारे हैं यह स्थिति नहीं है। आप यह मानते हैं, कांग्रेस के नेता मानते हैं आज, क्या बिडला जी ने कांग्रेस पार्टी को चन्दा नहीं दिया ? मैं समझता हूं, यह खडे होकर कह दें, लेकिन सुखाडिया जी इन्कार नहीं कर सकते । आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी इन्कार नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री इन्कार नहीं कर सकतीं कि साहू जैन ने पैसा नहीं दिया, इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकते । कोई जे.के. में पैसा नहीं दिया, इससे इन्कार नहीं कर सकते । उदयपुर की स्पीनिंग मिल है, जयपुर की नेशनल बालबेयरिंग फैक्ट्री है, इन कम्पनी से कांग्रेस पार्टी को चन्दा नहीं मिला–इससे इन्कार नहीं कर सकते . . . .

श्री **रामनारायण चौधरी (मंडावा)** : नहीं मिला ।

श्री **भैरोंसिह** : आपको पता नहीं है ।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : आप झुंझुनू में रहते हैं, आपको पता नहीं है, चन्दा वसूल किया था ।

श्री **भैरोंसिह** : मैं कहता हूं कि चन्दा इकट्ठा हम भी करते हैं । मैं इन्कार नहीं करता । मगर चन्दा इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास जाना पडता है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : राजस्थान के पचपन करोड में से रुपया मिला ?

श्री भैरोंसिह : ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, इस सन्दर्भ में मैंने बात कही थी और इस नीयत से कही थी कि आरोप प्रत्यारोप न हों। लेकिन विधान सभा के अन्दर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसके कारण से जनमानस के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कि लोकतन्त्र की व्यवस्था है इसमें कहीं न कहीं इतनी कमियां हैं कि वास्तविक रूप में जो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वह न चुनाव लड़ सकते हैं, न जीत सकते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। मैं भी लड़ा हुआ था। पराजित हुआ हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं मैं कोई यह बात कहूं कि मैं हारा नहीं हूं तो यह कोई मान नहीं सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : शानदार बहुमत मिला है।

श्री भैरोंसिह : शानदार बहुमत मिला है–यह स्वीकार करता हूं। लेकिन राम नारायण जी, यह बात कहना चाहता हूं कि यह शानदार बहुमत ही कांग्रेस की कब्र खोदेगा। यह जीत ऐसी है जो कांग्रेस की कब्र खोदेगी–इसकी चिन्ता है। यह कांग्रेस कहीं लोकतन्त्र को ही ले नहीं डूबे–इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जनता के अन्दर जो आपने आशाएं जगाई हैं, जनता को आशाओं के महल दिखाये हैं, जिस प्रकार की बातें जनता के सामने रखी हैं–वह वातावरण छः महीने में नहीं बना, वह आशाएं छः महीने में पूरी नहीं हुई तो आपने बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुना होगा–इनके भाषण का सारांश यही था कि जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं की गई तो यह वार जो 1971 के अन्दर विरोधी दलों के ऊपर पड़ा है, यह वार 1972 में मंत्रियों के ऊपर पड़ेगा। इसमें समझ लें। आपके लोग भी सतर्क हो गये हैं, कि हम जनता को आकांक्षाएं बढ़ाने में बहुत आगे चले गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : गरीब अमीर का संघर्ष था, न वातावरण बनाया गया, न वातावरण बनाने का प्रयास किया गया, इस चुनाव में गरीब की जीत हुई है।

श्री भैरोंसिह : यह रामनारायण जी कह सकते हैं कि अमीर गरीब का संघर्ष था।

श्री मदनसिंह : सबसे बड़े गरीब थे दरबार, और इधर हुए खड़े, वह दोनों बहुत गरीब थे।

श्री भैरोंसिह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैं जीत-हार की बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो जीते हैं उनमें कितने गरीब हैं और कितने अमीर–आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं, तब आपको पता लगेगा कि गरीब और अमीर की लड़ाई थी या नहीं ? आप कहते हैं क्योंकि आप जीतकर चुने गये हैं, इसलिए कह सकते हैं कि गरीब और अमीर का संघर्ष था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजा–महाराजा और जनता

Page No 50

(श्री भैरोंसिंह)

की लड़ाई नहीं थी, यह पार्टियों की लड़ाई थी, यह सिद्धान्तों की लड़ाई थी। उसमें व्यक्ति शामिल हो गये, व्यक्तियों के कार्यक्रम शामिल हो गये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, बदकिस्मती यह है कि इन चुनावों में शक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई जगह राजनैतिक दलों की सभाएं हुई, मैं यह स्वीकार करता हूं कि सभाओं में कई जगह पत्थर फेंके गये। मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि यदि मेरे दल द्वारा किसी भी सभा के अन्दर पत्थर फेंकने की कोई कार्यवाही की गई है, तो मैं समझता हूं, वह भी उसी प्रकार कन्डेम करने लायक है, जिस प्रकार और लोगों को किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक सीमा है। सभा में नारे लगाना, सभा में काले झण्डे दिखाना–यह 1952 से प्रक्रिया चलती आ रही है। इस प्रक्रिया मे सभाओं में विघ्न पैदा होता है, कई बार सभाओं में विघ्न पैदा नही होता। लेकिन यह बदकिस्मती है, उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दो जिलों–नागौर और झुंझुनू जिलों में जिस प्रकार की हिंसक कार्यवाही की गई उस हिंसक कार्यवाही से अब तक दिमाग में एक चीज पैदा होने लग गई है कि अगर चुनाव लड़ना है तो पहले अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करो अपनी सुरक्षा के बाद में अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था करो और जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक चुनाव लड़ने का साहस मत करो। अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले में पूरे चुनाव में किस स्थान पर किस प्रकार की घटनाएं हुई, गाड़ियों को वहां तोड़ा गया, गाड़ियों को सड़कों से निकलने नहीं दिया, कार्यकर्ता गये उनकी जेबों से पैसा निकाल लिया, उनकी घड़ियों को छीन लिया, उनके कपड़े उतरवा लिये, उनको लाठियों से पीटा गया, एक कार्यकर्ता की आंख फूट गई, गाड़ियों में स्टेपनि नहीं छोड़ी, गरम कम्बल नही छोड़े, और सबसे ज्यादा शर्म की चीज यह आई है, अध्यक्ष महोदय, आप ही के आसन के ऊपर 1952 से लेकर 1957 तक जिस व्यक्ति ने इस आसन को सुशोभित किया था, वह विरोधी दल की ओर से प्रचार करने के लिए कुछ गांवों में गये, उनके साथ में मैं कहना नहीं चाहता, उस प्रकार से अमानुषिक व्यवहार किया गया कि जिसे सदन में कह नहीं सकता . . .

श्री रामनारायण चौधरी : गलत है।

श्री भैरोंसिंह : और कहा जाय तो सुनने वालों को शर्म आयेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : गलत है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्यों चिल्ला रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि यह सब चीजें गलत हैं तो मैं रामनारायण जी से एक बात पूछना चाहता हूं. . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : रामनारायण जी से क्या पूछते हैं, वह राजस्थान की इन्दिरा गांधी से काफी परेशान हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, लगभग सौ मसले पुलिस में दर्ज किये गये हैं, अमुक स्थान पर हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, अमुक स्थान पर हमारे कार्यकर्ताओं की जीप तोड़ दी गई, अमुक स्थान पर हमारे कार्यकर्त्ताओं के कपड़े फाड़ दिये गये, अमुक स्थान पर कार्यकर्त्ताओं के ऊपर पथराव किया गया। मैंने......

श्री रामनारायण चौधरी : एक भी उदाहरण बता दीजिये कि जनसंघ के कार्यकर्त्ता को कहीं रोका गया हो ?

श्री गंगासहाय : मेरे साथ हुआ है, मेरे पर जूते फेंके, मेरे कपड़े फाड़े।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह वही व्यक्ति हैं जो बिड़ला के पैसे से जीते।

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनू में कहां गये थे ? आप झुंझुनू में कहां गये थे ?

श्री गंगासहाय : आप कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : बात झुंझुनू की चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : रामनारायण जी के और सरकार के सामने सारा मामला साफ हो जाय, इसलिए मैंने जो नोट तैयार किया है वह पढ़ कर सुनाता हूं, जिसमें तारीखवार, घटनाक्रम लिखा है, गांव है, तारीख है। आप चाहें तो सदन की मेज पर रख दूं और चाहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : मेज पर रख दीजिये। समय बच जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हम सुनेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें सुनाना चाहूंगा कि दिनांक 15-2-1971 को राणासर में विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रदेश के भाकान्द के उपाध्यक्ष श्री नरोत्तमलाल जोशी को 20 25 व्यक्तियों ने रोक कर उनकी जीप की जबरदस्त तोड़फोड़ की उनको 6 घण्टे तक रोके रखा। उनके एक साथी श्री सरदारसिंह चोरडिया को एक पेड़ के बांध कर उनकी पिटाई की।

श्री रामनारायण चौधरी : तोड़फोड़ किसने की ?

श्री भैरोंसिंह : श्री सरदारसिंह चोरडिया की पिटाई की और उनकी जेब में से 80 रुपये निकाल लिये।

दिनांक 26-2-1971 को बाकरा ग्राम में श्री नरोत्तमलाल जोशी की दो गाड़ियों को रोक लिया था उनके ड्राईवर का सिर फोड़ दिया था तथा सिर पर पत्थरों से हमला किया गया। इस प्रकार से एक और घटना बहुत सीरियस खेतड़ी से पिलानी आते समय दिनांक 27 फरवरी 1971 को देवरोड़ नामक ग्राम के पास विरोधी दल के नेता श्री देवेन्द्र कानोडिया की कार पर हमला किया गया जिससे कार को बहुत नुकसान हुआ और श्री कानोडिया की एक आंख फूट गई। मैं यह भी, अध्यक्ष महोदय

(श्री भैरोंसिंह)

को कहना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किसी ने अपनी आंख फोड़ ली ? कोई अपने पोस्टर फाड़ सकता है लेकिन कोई आदमी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि दूसरे को बदनाम करने के लिए अपनी आंख फोड़ दे। अध्यक्ष महोदय, पोलिंग ऐजेन्ट के रूप में काम करते हुए पोलिंग पार्टी की मोजूदगी में पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलते हुए ...

श्री रामनारायण चौधरी : उनकी आंख का चश्मा ब्रेक से अड़ा था इसलिए उनकी आंख फूट गयी। लेकिन समाचार पत्रों में गोली से आंख फूटने की खबर निकल गई।

श्री मदनसिंह : उनका चश्मा ब्रेक से अड़ने के कारण उनकी आंख फूट गई। तो लड्ढाजी की गाड़ी जो जली क्या खुद उन्होंने शराब पीकर जलादी थी ?

श्री भैरोंसिंह : मैं रामनारायण जी से कुछ कहना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको मालूम है यह समाचार पत्रों में प्रसारित हुआ कि उनकी आंख में गोली लगी और उनकी आंख फूट गई लेकिन बाद में जांच से यह बात साबित हो गई कि गाड़ी जा रही थी, अचानक ब्रेक लगने से उनका चश्मा ब्रेक से अड़ा और उनकी आंख फूट गई। तथ्य तो यह है न किसी ने पत्थर मारा और न कोई गोली चली जिससे आंख फूट गई। इस सच्चाई को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता आप गांव गांव में जाकर इसकी जांच कर लीजिए। किसी ने उनको पत्थर मारा हो जिससे उनकी आंख फूटी यह बात जांच में सत्य निकले तो कहिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामनारायण चौधरी ने कुछ भी कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय उनके पास में सत्ता है वह कुछ भी कहें वह सत्ता के बल पर बोल रहे हैं अगर सत्ता किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होती तो रामनारायणजी न इस प्रकार की कोई कार्यवाही होती और होती तो इस प्रकार की लीपा पोती करने की आपकी हिम्मत होती भी नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैसूर में क्या हुआ, यू. पी. में क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : मैसूर में हुआ हो, कहीं हुआ हो उनको मैं नहीं कहता।

श्री रामनारायण चौधरी : यह हवा थी जो की आपके विपरीत जा रही थी। आप किसी को दोष मत दीजिये, आप लोगों का ही दोष है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह भारतीयकरण का दोष है।

श्री भैरोंसिंह : श्री रोशनलालजी, भारतीयकरण के नारे का जवाब आप पत्थर से देना चाहते हैं तो ...

श्री रोशनलाल शर्मा : पत्थर से नहीं।

श्री मदनसिंह : लड्ढाजी की गाड़ी जली उसके लिए क्या कहते हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा: जो बात आप कहते हैं उसका जवाब राजस्थान ने दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी आप सुनिये, विरोधी दल के खिलाफ हवा चल रही थी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको निवेदन करदूं, भारतीयकरण के जवाब लाठी-पत्थर से देना चाहेंगे तो मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई घर में चुप बैठने वाला नहीं है, कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा: शाहपुरा में आपने लाठी चलवायी हैं। शुरूआत आपने की है, जनसंघ ने की है। आप लाठी और पत्थर से जवाब देंगे तो, हम भी देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप इस बात के लिए तैयार तो हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा: हम भी तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप तैयार हैं कि चुनाव लाठी और ताकत के बल पर हों।

श्री रोशनलाल शर्मा: हम अहिंसा के बल पर चुनाव लड़ते रहे हैं। लाठी आपके स्वयं सेवकों ने चलाई है कांग्रेस वालों के ऊपर और किसी ने लाठी नहीं चलाई।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह तो गांधीजी के नालायक लड़के पैदा हुए हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : गान्धीजी के अहिंसा के सिद्धान्तों को मानने वाले हम ही रहेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : कैसे रहेंगे यह तो भ्रष्टाचारी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह तथ्य सत्तारूढ़ दल वालों को बुरा लगेगा, दुनिया में एक हवा पैदा किये हुए है और वो कर भी रहे है कि गरीबी के आधार पर चुनाव लड़ा है, गरीबों के वोटों के कारण चुनाव जीत कर आये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वास्तविक गरीब हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर नहीं आने दिया गया, उनको गांवों में घेराव कर रोक लिया गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह कार्य किसने किया है वोटरों को रोकने का कार्य भी आप लोगों के द्वारा किया गया है, जागीरदारों द्वारा ही किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है कि जागीरदार आपको ऐसे बुरे लग रहे हैं . .

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वोटरों को रोकते हैं इसलिए बुरे लग रहे हैं।

श्री मदनसिंह : जागीरदार बुरे लगते हैं तो आप अपने मुख्य मन्त्रीजी को कह दीजिए की जागीरदारों को अपने दल से निकाल दें। उन्होंने ऐसा करवाया है। शाहपुरा में ऐसा करवाया होगा, मसूदा में ऐसा करवाया होगा। जागीरदारों ने तो हमेशा लोगों की रक्षा की है और करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सारी घटनाओं के विवरण में न जाकर एक बात और सदन के सामने रखकर कहना चाहूंगा कि यह कांग्रेस किस एक्सटेण्ड तक चली गई है इस बात का यह प्रमाण है कि

(श्री भैरोंसिंह)
पिलानी निर्वाचन क्षेत्र अडावता में दिनांक 28-2-1971 व 1-3-71 की मध्यरात्रि को पोलिंग पार्टी जहां पोलिंग सामान के साथ सो रही थी वहां पर रात को करीब 1 बजे चार व्यक्ति जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, आये उनके दो के पास पिस्तोल थी और एक के हाथ में हैण्ड ग्रेनेड था। आये और उनको प्रिसाईडिंग आफिसर के पिस्तोल गले के पास लगा दी और बक्सा जिसमें बैलट पेपर व अन्य कागजात थे खोस कर ले गये। रात्रि को तीन बजे झुन्झुनू जिलाधीश को सूचना देने पर दूसरे बैलट पेपर भेजे गये। अभी तक कोई भी इस विषय में गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इसके लिए कहेंगे कि यह बात भी गलत है लेकिन कलेक्टर इस बात को मानेगा कि बैलेट पेपर ले गये थे और मैंने वापिस दूसरे बैलट पेपर भेजे हैं। अगर यह बात गलत होगी तो दूसरे बैलेट पेपर भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता और बाद में माननीय सदस्य यह बात कह देते हैं कि यह बात गलत है।

श्री रामनारायण चोधरी: ले कौन गया ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं . . .

श्री रोशनलाल शर्मा : ले कौन गया ? बिड़लाजी के आदमी ले गये।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवधान नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिड़ला जी का आदमी हो चाहे कोई भी हो यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : अगर इसको लाइटली आप लेते हैं तो कोई भी केन्डीडेट नहीं बचेगा और आप इस बात को देखेंगे कि कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : बहुत मिलेंगे।

श्री मदनसिंह : यह अच्छी बात नहीं है आप अच्छी बात को प्रोत्साहन दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शांता, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू में जो घटना हुई है उनका मैंने उल्लेख किया है लेकिन नागौर भी किसी प्रकार से पीछे नहीं रहा वहां यह आम चीज थी कि विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने नहीं देना, विरोधी दल के लोग अपने झण्डे गांव में नहीं लगा सकते। अगर किसी ने लगा लिया तो उसको फाड़ दिया गया है। कार्यकर्ताओं को पीटा गया एक घटना का उल्लेख मैं लम्बा चौड़ा नहीं करना चाहता हूं केवल इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

दिनांक 22 फरवरी को रात्रि को साढ़े नौ बजे स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं में श्री बद्रीविशाल भंवर तथा उनके साथी मूंडवा से जायल लौट रहे थे। रास्ते में तरनाऊ गांव के पास दो जीपों ने इनका पीछा किया जिसमें श्री चैनाराम, श्री जीवनसिंह कोलिया सरपंच आदि थे। इनके साथ 15–20 अन्य

(श्री भैरोंसिंह)

गुण्डे थे । श्री चैनाराम ने स्वतंत्र पार्टी की जीप रोक कर पिस्तौल दिखाई तथा भयभीत करके सभी कार्यकर्ताओं को नंगा कर दिया तथा राइफल की मूंठ एवं होकियों से अमानुषिकता पूर्ण उनकी पिटाई की उनके कपड़ों को पेट्रोल डालकर आग लगादी तथा श्री बद्री विशाल भंवर को जिन्दा जलाने का प्रयास किया । मैं एक बात पूछना चाहता हूं और मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि पुलिस आपके पास थी आप सारे मामले की इन्वेस्टीगेशन करके दोषी व्यक्तियों को अदालत में पेश कर देते कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है । मैं समझता हूं कि चुनाव का जहां तक संबंध है इस प्रकार के अपराध हों अगर कोई और उनका किसी प्रकार की कार्यवाही यदि नहीं हो लोग सही घटना को भी सही मानेंगे ही लेकिन लोगों के दिमाग में एक भ्रान्ति भी पैदा होगी कि सब घटनायें सरकार के पोषण से हो रही हैं । अब मैं अध्यक्ष महोदय एक संक्षेप में एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा कि पिपाड़ के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री सभा करने गये उसके पहिले गोपालगढ़ के चुनाव सम्पन्न हो गये थे सच बात है जहां मुख्यमन्त्री जाये वहां आसपास के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर उनके जुलूस निकालें । पीपाड़ के बाजारों में भी जुलूस निकाला वहां पर राजमाता के पोस्टर और पर्दे लगे हुए थे जुलूस वालों ने आपत्ति की कि हम राजमाता के जो पर्दे लगे हैं उनके नीचे से नहीं निकलेंगे राजनीति में काम करने वालों में सहनशीलता होनी चाहिये लेकिन जो वहां पर जो पोस्टर लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे उनको फाड़ डाला इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया सो दुकानों के सामने जो रखा हुआ सामान था उन्होंने जला दिया । उसके बाद मुख्यमंत्रीजी की सभा हुई उसमें कोई विघ्न नहीं हुआ मुख्य मन्त्री जी वहां से रवाना हुए तो उसके बाद में एक मन्त्रीजी ने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मेरी कार पर पथराव हुआ । पथराव हुआ या नहीं उसकी मुझे जानकारी नहीं लेकिन यदि कोई पथराव हुआ तो पुलिस में उसके खिलाफ में उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? उस पथराव के जवाब में एक मंत्री महोदय भाषण देते हैं कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा । अब वह पत्थरों का जवाब पत्थरों से किस प्रकार मिले मुख्य मन्त्री महोदय, वह सारी भीड़ स्वतंत्र पार्टी के कार्यालय की ओर गई । पीपाड़ मैंने भी देखा है और भी कई लोगों ने देखा है । यदि जुलूस निकालना था तो किले के सामने होकर जाने की क्या आवश्यकता थी ? दूसरा भी रास्ता है । वह किले की तरफ बढ़े और किले पर हमला करने की चेष्टा की । तो यह सही है, मैं स्वीकार करता हूं लोगों ने अपने बचाव के लिए ऊपर से पथराव किया । दोनों तरफ से पत्थरबाजी · · · · ·

सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य : आपको अब · · · · · ·

श्री भैरोंसिंह : जब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो आप क्यों उछल रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह किस ने कहा कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने पर जिन्होंने कहा वह बोल पड़े ।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमंत्री जी वहां पर मौजूद थे। जो कुछ मैं बोला हूँ, 10–15 हजार आदमी मौजूद थे। पत्थर का जवाब पत्थर से देने की बात किसने कही? आप नाम बता दें। किस मंत्री ने आम सभा में जिसमें 15 हजार आदमी खड़े हों, यह गैरजिम्मेदारी की बात नहीं कही। आपका मतलब किससे है?

श्री भैरोंसिंह : आपसे है।

श्री परसराम मदेरणा : यह झूठ है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको शायद दूसरों ने जानकारी दी होगी कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कहीं नहीं कहा गया और यदि कही गई बात है तो सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ जिन लोगों ने बताया, मैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं हूँ, उनको मुख्यमंत्री गैरजिम्मेदार नहीं कह सकते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (श्री वृद्धिचन्द्र जैन के खड़े होने पर) : आप बैठ जाएं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्यों बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया।

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद जुलूस किले की ओर जा रहा है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है। वहां मुख्यमंत्री के बचाव के लिए जोधपुर से पुलिस आई, काफी पुलिस तैनात है। क्यों पुलिस दोनों पार्टियों के बीच में खड़े होकर बीच बचाव नहीं कर सकती थी? पुलिस दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती कि शांतिपूर्ण जुलूस निकल जाय, ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती थी, लेकिन दोनों तरफ से जो पत्थर फेंके जा रहे थे। एक पार्टी से कहा पत्थर बंद करो और बन्द हुए। उसके बाद पुलिस चली गई। पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हैं उनको छोड़कर एडीशनल एस. पी. चले गये। उन लोगों ने दरवाजे पर पैट्रोल डाला, आग लगाई और दरवाजा खोलकर आग लगाने के बाद किले में प्रवेश किया 4 जीपों को जला दिया, 2 ट्रैक्टर जला दिए और कई साइकिलें जलाई। अगर किले को छोड़कर लोग भागते नहीं तो कार्यकर्ता भी पकड़कर जीपों और ट्रैक्टरों के साथ जलाए जाते।

आप कहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण कराए तो फिर अशांति किसका नाम है? लाठी के बल पर, सत्ता के बल पर, पुलिस के बल पर विरोधी कार्यकर्ताओं के दफ्तरों को इस प्रकार जलायें यह प्रवृत्ति लोगों में पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं इन चीजों को रोका जाए, रोकने की व्यवस्था की जाय।

किस तरह राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया, वह बताता हूं, डीडवाना के जनसंघ के सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया-क्यों? बोर्डिंग हाउस के अन्दर झगड़ा हुआ, एक लड़के गनपत को पीटा दूसरे लड़कों ने। जनसंघ के सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया, जंगले में रखा, जमानत नहीं ली। पहले 52 का मुकदमा बनाया गया फिर 307 में कन्वर्ट किया

Page No 57

(श्री भैरोंसिंह)

गया लेकिन जब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन पेश की गई तो उसका जजमेंट मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए। यह बात भैरोंसिंह नहीं कह रहा है बल्कि राज्य सरकार के मुंसिफ मजिस्ट्रेट कह रहे थे कि किस प्रकार पुलिस ने लोगों को परेशान किया :

"This order will decide the bail application dated 27-1-71 of Shri Raghunath.

The arguments were heard and the case diary was perused by me. On the very outset I am of the opinion that the accused Raghunath should be released on bail if he furnishes bail and personal bond for sum of Rs. 2,000/- to my satisfaction.

The prosecution has arrested him on 24-1-71 on the report of the Principal of Bangur College on the allegations that one student of his hostel named Ganpat Ram was attacked in the midnight while he was sleeping.

I have gone through the statement of injured Ganpat. He has not even mantioned the name of the accused as one of the assailant where in fact he has mentioned the name of other students. It is worth while to mention that Raghunath is not all student of the college and to satisfy me to this fact Shri Shri Niwas Advocate has submitted his affidavit.

Initially on the report of the Principal, the case was registered u/s 452,323 IPC. Later on during the course of the investigation section 307 IPC was further added. I have gone through the injury report. All the injuries were simple. The reason to why section 307 IPC was added is not at all convincing to me. It has been mentioned in the case diary that some deputation of students met with the executive officers and for this reason section 307 was added. As a matter of fact the police ought to have exercised his own discretion rather being guided by the deputation.

In the bail application it has been mentioned that the accused has been arrested for political reasons. Learned counsel for the accused has stated before me that the accused is the Secretary of Local Jan Sangh. I find force in this contention in view of the fact that no arrest of any other person apart from this accused has taken place, when the assailants were named by the injured.

Section 452 I.P.C. is not punishable to life imprisonment and hence for this reason also the accused is entitled for bail.

In the last I wish to add that the police should arrest the real assailants".

(श्री भैरोंसिंह)

अब आप अन्दाज लगाएं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। ऐसी हालत में मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव लड़ना कानूनन न आप राजा महाराजाओं को रोक सकते हैं न जागीरदारों को, न सेठों को, न गरीबों को रोक सकते हैं। जहां तक हमारे संविधान में चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार के अनुरूप चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आपने चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोका। यदि कानून में संशोधन करें कि कोई राजा महाराजा और पूंजीपति चुनाव नहीं लड़ सकता तो समझ में आने वाली बात है लेकिन जब इस प्रकार की रोक चुनाव की नहीं है तो उनका मुकाबला लाठी और पत्थरों से करना चाहते हैं, आगजनी और तानाशाही से करना चाहते हैं तो आप निश्चित मानकर चलें कि आज शायद ये घटनायें हमारे साथ हुई हैं, आज • जिन घटनाओं का शिकार हम विरोधी दल वाले हुए हैं लेकिन मुख्यमन्त्रीजी मैं आपको और आपके साथियों को सावधान करना चाहता हूं कि ये चीजें आप पर रिकोइल करेंगी। आज जिस प्रकार का जनमानस आप बनाकर चल रहे हैं उसमें मुझे आशंका है कि आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार की स्थिति और वातावरण राजस्थान में आप बनाते हैं उसका पहला शिकार मैं हो सकता हूं, पहला शिकार मेरे साथी हो सकते हैं लेकिन दूसरे शिकार के अन्दर सुखाड़ियाजी आप और आपके साथी बच जायें इसकी कल्पना करना, मैं समझता हूं, मुश्किल है। आप चाहे मुझ पर इलजाम लगाएं कि हमने पत्थर फेंके। मैं यदि दोषी हूं, दोष आपकी तरफ से भी हो तो उस पर दोष आप पर है लेकिन ये कार्यवाहियां न हों इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव समाप्त हुआ, हारने वाले हार गए जीतने वाले लोक सभा में चले गए लेकिन हार जीत के कारण जिन लोगों ने किसी दूसरे को वोट दिया है उनके साथ इस प्रकार की ज्यादतियां की जाएं यह तो ज्यादतियों की पराकाष्ठा है। मैं परसों जोधपुर में था। भोपालगढ़ के व्यापारी रोते हुए आए। उन्होंने कहा मुझसे कि 4 दिन से हमारे गांव में आतंक मचा रखा है दुकानों पर पड़े हुए सामान को बाजार में फेंक दिया, सामान को आग लगा दी। एक आदमी को पकड़कर मारा गया। लेकिन· · ·

श्री अध्यक्ष : मैं चला ही जा रहा हूं।

(1.40 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ही घटना नहीं है। जगह जगह से और और चिट्ठियां इस बात की आ रही हैं कि चुनावों के बाद हमारे साथ किस प्रकार की ज्यादतियां की गई हैं। छोटी खाटू से टेलीग्राम आया। बावरी महिलाओं को इस प्रकार से पीटा गया। मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने टेलीग्राम दिया कि महिलाओं को लेकर जयपुर आ जाओ। टेलीग्राम से

(श्री भैरोंसिंह):

आया नहीं लेकिन एक व्यक्ति पत्र लेकर आया है। इस समय उसको मैं सदन में नहीं रखना चाहता हूं। कल वे लोग आ रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी को पत्र देता हूं वे क्या कर रहे हैं। यदि इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। वावरियों की महिलाओं को पीटा गया, उनके मकान तोड़ दिए गये, उनको पीट कर उनका बाजार में जुलूस निकाला गया उनसे रुपये छीन लिए जितनी ज्यादतियां उनके साथ की जा सकती थीं उनके साथ की गयीं। इस प्रकरण की मैं आगे चर्चा करूंगा इस-लिए इस सम्बन्ध में अभी आगे कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): मैं अपना उत्तर 22 तारीख को दूंगा। लेकिन मेरे पास कई ऐसे समाचार आये हैं। यह विश्वास दिलाकर चल सकता हूं कि किसने किस तरफ वोट दिया है, उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादतियां होंगी तो उनको रोका जायगा और अधि-कारियों को इसके लिए आदेश दिये जावेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: पानी बन्द किया गया उनकी ओर से।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सीमाओं की घटनाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): आप चेयर पर बैठे हो और उस वक्त ऑर्डर ऑडर करें वैसा कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में और, खास तौर से सीमावर्ती जिलों में, बाड़मेर से मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ समस्याएं मेरे सामने आयीं उन समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। इसलिए रखना चाहूंगा, चुनाव की दृष्टि से नहीं, किन्तु कई बार उनको सदन में रखा है उस दृष्टि से भी। मैं अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि--उस सारे इलाके का प्रत्यक्ष में अनुभव करने के बाद उन चीजों में राज्य सरकार की कितनी सतर्कता है, यदि इन चीजों को सामने नहीं रखा गया तो वास्तव में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वे भी इस बात की ताईद करेंगे कि बाड़मेर के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। यह आप स्वीकार करते हैं। कई सालों के अकाल के बाद इस साल वहां पर फसल हुई। मैं सरकार से जानकारी करना चाहता हूं कि सरकार ने हुक्म दिया कि दो वर्ष के लगान के अलावा आगे की कोई बकाया है वह काश्तकारों से एक साथ वसूल नहीं की जाय। बाड़मेर जिले में दो साल का लगान और 6। (सवा छः) रुपया जो कर्ज लिया वह वसूल हो रहा है। दो तीन कांग्रेस की पंचायत समितियां हैं उनमें एजुकेशन सेस लगाया गया है वह भी वसूल किया जा रहा है। पंचायत की बकाया है वह भी वसूल की जा रही है। लोग दे सकते हैं या नहीं? सरकार ने एक मात्र यह देखा कि बाजरे की फसल आ चुकी है। मंत्री महोदय जो खाद्य विभाग को देख रहे हैं उन्होंने भी इस सदन में घोषणा की थी कि बाजरे के भाव नहीं गिरने दिए जायेंगे और 52 रुपये क्विन्टल में सरकार खरीदेगी। मैं ऐसा

Page No 60

(श्री भैरोंसिंह)
समझता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में गांव गांव में चले जायं 30 32 रुपये 35 रु. के भाव में बाजरी मिल रही है और किसान को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस समय कर्जा लिया था 61 रुपये उस समय बाजरी का भाव 80रु. 90 रु. क्विन्टल था और अब भुगतान किया जा रहा है 30) 35 रुपये क्विन्टल में। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं उनसे आज वसूली किस कारण से की जा रही है? सरकार ने गलती की। 52 रु. क्विन्टल में अनाज नहीं खरीदा। मंत्री महोदय बोलेंगे तब अपने जवाब में बतायेंगे कि बाड़मेर जैसलमेर से कितना खरीदा? बाजार में कोई ग्राहक नहीं। लोग बाजरे को लेकर घूम रहे हैं। इस वसूली के साथ साथ 61 रुपये का कर्जा बाड़मेर के लोगों से वसूल किया जा रहा है। वसूल करने की आवश्यकता नहीं है। मूल कारण यह है कि जो कर्जा दिया गया, जिस मात्रा में दिया गया, वह 80-90 था और वसूली की जा रही है 30-35 क्विन्टल के भाव में। बाड़मेर जिले में काम न खोल कर 61 रुपया दिया और दूसरे जिलों में काम खोल कर 45 रुपये दिए। यहां केवल 61 रुपये दिए। यह भी ब्याज सहित वसूल करना चाहते हैं। मेरी बात की ताईद बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य भी करेंगे। आप इसके पक्ष में हैं या नहीं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : ब्याज सहित वसूल नहीं किया जा रहा है। दूसरी पोजिशन यह है कि 121। रुपया दिया गया। 61 रुपया तो अनुदान का दिया गया था। 61 रुपया लोन दिया गया था। उस पर इन्ट्रेस्ट नहीं लिया गया। 61 रुपये की वसूली चार इन्स्टालमेन्ट में की जा रही है। हमारे यहां की जनता यह देने के लिये तैयार है और कोई इन्कार नहीं है। मुफ्त में नहीं लेना चाहती। इस प्रकार की भिखमंगी जनता को नहीं करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात इसलिये कही है कि चुनावों की सारी सभाओं में यह कहा गया कि हमें जिताओ, यह 61 रुपया माफ हो जावेगा। मैंने इसलिये पूछा था कि वहां क्या आश्वासन दिया था और यहां विधान सभा में क्या कहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जनसंघ ने ही यह प्रचार किया था कि "हम माफ करा देंगे।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में मैं आपके लिखे हुए भाषण को वहां भेज दूंगा। लोग इन्तजार में बैठे हैं कि 61 रुपये के लिये हुक्म होगा और वसूली नहीं होगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एलीगेशन लगायें तो सही तो लगायें।

श्री भैरोंसिंह : इस जिले में अकाल के दिनों में सड़कें बनी हैं उनकी आज क्या स्थिति है। जिस समय सड़कें बनीं और क्या हुआ उसका उल्लेख यहां कई बार किया जा चुका है। अब उल्लेख पुनः नहीं करना चाहता। यदि उन सड़कों को मेन्टेन नहीं किया जावेगा तो जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है वह बेकार चला जावेगा। सरकार इसकी व्यवस्था करे कि उन सड़कों का किस प्रकार से मेन्टीनेन्स किया जा सकता है।

(श्री भैरोंसिंह)
जैसा माननीय वृद्धिचन्द्रजी कह रहे थे कि हम तो वहां जोर शोर से जीत कर आये हैं....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने सड़कों का नहीं कहा है।

श्री मदनसिंह : 72 में फिर मुकाबला करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य-मंत्री) : आपने यह सोच रखा है कि भैरोंसिंहजी को वहां भेजेंगे।

श्री मदनसिंह : आप भी उदयपुर से नहीं रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन जावेंगे यह पता नहीं है।

जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर आदि का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता लेकिन उनकी इकोनोमिक कन्डीशन्स बराबर गिरती जा रही है। लोगों में एक प्रकार का असंतोष है। इसलिये कि बाड़मेर ज़िले में कोई मैट्रिक पास कर ले, आपको जानकारी होगी, नहीं तो करा लें, काम उसको मिल नहीं सकता, नौकरी उसको मिल नहीं सकती। रोजगार नहीं मिल सकता। मैंने इस इलाके का जितना अध्ययन पहले नहीं किया अब किया है। जैसलमेर, बाड़मेर में गांव गांव में इन्डस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में ऊन के नमदे बनवाकर एक्सपोर्ट किये जा सकते हैं। एक्सपोर्ट में माल की क्वालिटी, इसकी कीमत का निर्धारण आदि आवश्यक है। बड़ा स्कोप है।

मैं समझता हूं राजस्थान में और खास तौर से उन जिलों में ऊन की कटाई के लिये मोबाइल रूप में कोई व्यवस्था कर दी जावे, धुलाई सफाई की व्यवस्था कर दी जावे तो काफी संख्या में वहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहां के बेकारों की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

वहां रंगाई छपाई का काम चल रहा है, उसको भी अगर सरकार उचित प्रोत्साहन दे तो भी इस समस्या के हल में योग मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ऊन के कम्बल और बसणे अपनी खासियत है वहां की। अपनी जिन्दगी में मैंने इतने बढ़िया और मुलायम नहीं देखे। पांच सौ रुपये का एक एक। चुराने का मन करता है। किसी के पास देखेंगे तो छीनने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि यह मेरे पास रहे। ऐसे सुन्दर कम्बल बसणे वहां बनते हैं। पर इसके लिये लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। अगर पर्याप्त साधन उनको दिये जावें तो बेकारी की समस्या का काफी समाधान हो सकता है।

ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन पांच सात जिलों में इस राज्य सरकार ने इस प्रकार का इतना बड़ा रीजनल इम्बेलेन्स क्रीएट कर दिया है अपनी गलत और पक्षपातपूर्ण नीति के कारण कि अब छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलेगा। देश के अन्य भागों में जहां कहीं भी रीजनल इम्बेलेन्स क्रीएट हुआ है वहां विस्फोट हुए

Page No 62

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। पंजाब हरयाणा का झगड़ा चला। हरियाणा आखिर में अलग हुआ। आंध्र और तेलंगाना का मामला हमारे सामने है। आन्दोलन हुए, सम्पत्ति नष्ट हुई राष्ट्र की। अलग से कमेटी बनी। फिर भी तेलंगाना सन्तुष्ट नहीं है। यह कह कर कोई मैं सेपरेटिस्ट टेन्डेन्सी का समर्थन नहीं करना चाहता। पर मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अब इन जिलों में जिस प्रकार का इम्बेलेन्स आपकी गलत और पक्षपातपूर्ण और उपेक्षा की नीति से क्रीएट हो गया है उसको अब साधारण तरीकों से दूर नहीं किया जा सकेगा। उसके लिये आपको असाधारण तरीके अपनाने होंगे। मेरी मांग है कि इन पांच सीमावर्ती जिलों के इक्वल डवलपमेन्ट के लिये अलग से एक शक्तिशाली रीजनल डवलपमेन्ट कौंसिल स्थापित की जावे और जो भी चौथी योजना के डवलपमेंट के टारगेट्स हैं उन जिलों के लिये अलग से एक स्कीम तैयार की जावे और प्लानिंग के आधार पर बाकी के जिलों के समानान्तर वे खड़े हो सकें –इस प्रकार की व्यवस्था की जावे। नहीं तो सीमावर्ती जिले होने के कारण इतनी प्रोब्लम क्रीएट होगी कि उसका अन्दाज आप आज नहीं लगा सकते। लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान से कनफ्लिक्ट हो गया तो आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार की स्थिति चल रही है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर नगर की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर नगर की कई समस्याएं हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आखिर आना यहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बेफिक्र रहें। 52 से लड़ते लड़ते 67 में मौका मिला है तीन बार पछाड़ खाई है। अबकी बार आये हैं तो यह न समझें कि आसमान के हाथ लगा लिया बौने ने।

जयपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण जयपुर में रोजगार के मिलने का है। राजधानी है यह भी कारण है। और भी कई कारण हैं। इसके अनुरूप जो भी सिविल एमिनिटीज हो सकती हैं उसकी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में लगभग 1½ लाख व्यक्ति कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं। कई बार उनके लिये आन्दोलन हुए। सरकार की ओर से समिति भी बनाई गई। उसमें मैं भी एक सदस्य हूं। जितना समाधान होना चाहिये था उतना समाधान इस समिति के द्वारा नहीं हुआ। कई मसले हैं, रेन्ट्स के, प्लाट्स के, मैजरमेन्ट के। इनके सवाल सामने आये। इनको किस प्रकार हटाया जावे, कहां बसाया जावे इसका सवाल खड़ा हो जाता है। नगर विकास मण्डल की समस्या खड़ी हो जाती है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप गरीबी मिटाने की बात सब कर रहे हैं। लोगों की आवास की समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं। जयपुर में जैसी प्रोब्लम है वह न्यूनाधिक रूप में राजस्थान के हर नगर की है।

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर किसी शहर में चले जाइये सब जगह यही प्राब्लम मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि समस्या के समाधान हेतु आपने न तो हाउसिंग बोर्ड बनाया। पर इससे भी समाधान नहीं हुआ। नगर विकास न्यास से समाधान नहीं हो पाया।

मैं इस समस्या के समाधान की गरज से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सर्व शक्तिमान संगठन खड़ा करें और उसके आधार पर एक टारगेट फिक्स अप करके एक तिथि तय कर दें कि इस समय तक आवास सम्बन्धी समस्या हल कर लेंगे। मार्च महीने तक, सितम्बर तक या फलां महीने तक इस का समाधान कर देंगे। नहीं तो अगर ये समस्याएं एक्युमुलेट होती गईं तो आप यह निश्चित रूप से मानकर चलें कि बड़े बड़े शहर इन्हीं आवास की समस्या से उत्पात के केन्द्र बन जावेंगे। वे यहां रोजी रोटी और आवास की अपनी समस्या हल करने के लिये आते हैं। तमाशा देखने नहीं आते। मकान अगर उनको नहीं मिलता तो झोंपड़े बना कर रहते हैं अगर उनसे छेड़खानी की गई, उनको बिना कोई उपयुक्त आल्टरनेट दिये हटाने की कोशिश की गई तो उत्पात होंगे। तो जयपुर में अगर आपको आवास की समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले नगर विकास मण्डल जो आपने बना रखा है उसे ठीक करना होगा, बालचन्द वैद का उससे अभी भला हो सकता है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का भला हो सकता है पर इसके बदले में आप मानकर चलिये कि उतना ही विनाश होगा। ऐसे लोग क्या करेंगे? जिनमें इनीशियेटिव नहीं। जिनमें जनता कि फीलिंग नहीं है, जनता में स्थान नहीं उनको लीडर बना दिया। समाधान की मशीनरी उनके हाथ में पकड़ा दी तो बेसिकली जो इनीशियेटिव चाहिये उसके अभाव में उनके लिये कुछ कर पाना सम्भव नहीं।

लोकतान्त्रिक भावनाओं को देखें तो लोकसभा में और विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं है। म्युनिसिपैलिटियों में बहुमत नहीं है। फिर किस आधार पर आज की इस सरकार ने यह मापदण्ड बना रखा है कि हारे हुए को नगर विकास न्यास का अध्यक्ष बना दें, निगम का अध्यक्ष बना दें, किसी अन्य बोर्ड का अध्यक्ष कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्री पर आरोप लगाना चाहूंगा कि उदयपुर में नगर विकास न्यास बना तो उसकी तो मुख्य मंत्री को बड़ी चिन्ता। जब भी वहां जावें, जाते भी बार बार वहीं हैं, पूछते रहते हैं दिलचस्पी लेते हैं पूरी तरह से कि किस प्रकार से कैसा विकास हो रहा है। सारे कार्यक्रम को देखें, प्लाटों के अलाटमेन्ट तक में दिलचस्पी रक्खें। यहां जयपुर में एक हारे हुए अपने कृपापात्र को दे दिया। तो जयपुर उदयपुर में वे अन्तर करके देखते हैं। बालचन्दजी एक चुनाव में हार गये तो उन पर कृपा करने के लिए न्यास का अध्यक्ष बना दिया, तीसरे चुनाव में रामकिशोरजी हार गये तो उनको बना दिया, कभी कोई कहीं हार गया तो उसको बना दिया। तो इस तरह से हारे हुए लोगों पर कृपा बनाये

(श्री भैरोंसिंह)

रखने की दृष्टि से ये काम सौंपकर जयपुर का आप भला करना चाहें, तो नहीं हो सकता। यहां की आवास की समस्याएं यों हल नहीं हो सकतीं। अगर ठीक तरह से व्यवस्था नहीं होगी, तो व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि आन्दोलन की प्रक्रिया में मैं ज्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, कई बार निवेदन कर चुका, अब मजबूर हैं, लोग। कल भी लोग आये थे, घरों में जाकर कहकर आये हैं--विधान सभा के सामने जाकर बैठे रहे। कोई न कोई कार्यवाही करते रहें-इस आशा से कि सरकार सुनवाई करेगी। पर अब एक बात के लिये सरकार को सावधान करना चाहूंगा। मैं पिछली वार भी मुख्य मंत्रीजी से मिला। पानी का संकट यहां है। सर्दी–गर्मी हमने निकाल ली, बरसात आ गई। हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि जयपुर में बनास योजना की कार्यवाही चल रही है। बनास योजना की बात कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जितनी जनसंख्या है उस अनुपात से आप पानी दे सकेंगे या नहीं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस मौके पर मैं निवेदन करूंगा कि गर्मियों से पहले पहले जयपुर में पानी की प्राब्लम सोल्व की जाये, आप सतर्क रहें वरना जयपुर में पानी का संकट पैदा होगा। आवास का संकट खडा होगा। बेरोजगारी का संकट खड़ा होगा। बीमारियां पैदा होंगी। हाहाकार मचेगा। वैसी स्थिति में इन समस्याओं का हल निकालना है और सावधान रहना है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण न तो राजस्थान की समस्याओं का समाधान करने का किसी प्रकार का कोई संकेत देता है न राजस्थान की वास्तविकता का वास्तविक चित्र ही प्रस्तुत करता है। यह तो परम्परागत इस प्रकार का अभिभाषण है जो फोर्मेलिटीज को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई जान नहीं है। यदि इस अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, जैसा कि रखा गया है, तो उसका मैं समर्थन करने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो चर्चा चल रही है वह मध्यावधि चुनावों के परिणामों की छाया में चल रही है। पक्ष और विपक्ष में, विपक्ष की तरफ हार और पक्ष की तरफ जीत के चेहरे सामने दिख रहे हैं। सन् 1947 के पहले देश में जो इन्कलाब आया था व 23 सालों के बाद फिर सन् 1971 के अन्दर पुनः आया है। सन् 47 के पहले साम्राज्यवादियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ देश का एक विद्रोह था और 1971 के अन्दर देश की पूंजीवादी व्यवस्था, देश में बची खुची सामन्तशाही के खिलाफ संघर्ष था। इस संघर्ष का निर्णय हमारे देश की जनता ने दे दिया है। देश के 28 करोड़ मतदाताओं और देश की 56 करोड़ भुजाओं ने दे दिया है कि देश गरीबों के साथ है या अमीरों के साथ है। देश ने साधारण जनता का गौरव बढ़ाया है। एक तरफ साधारण कार्यकर्ता थे और दूसरी तरफ पैसे वाले इन चुनाव में खड़े हुए थे। इन दोनों ने चुनाव लड़ कर यह साबित कर दिया है कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है और इससे हमारे मुल्क का गौरव ब

(श्री रामनारायण चौधरी)

है । मैंने यहां पर विरोधी पक्ष के नेताओं के भाषणों को गम्भीरता के साथ सुना है । वे समाजवाद की नीति पर यहां पर भाषण करते हैं । आज मुल्क में इन दलों की नीतियों का आपस में जिस तरह से घपला हो गया है वह एक बड़ी भारी विडम्बना है । एक दल समाजवाद की, गरीबों और मजदूरों के हितों की बात करता है और चुनावों में राजा-महाराजाओं और पूंजीपतियों का समर्थन करता है । उससे क्या हुआ है ? देश में इस की एक प्रतिक्रिया हुई है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप देश के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया है । मतदाताओं ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, उनका सफाया कर दिया है । मतदाताओं ने अपना यह निश्चय दे दिया है कि देश के लिये समाजवादी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है । महाराजाओं और उनकी पार्टी का समर्थन कौन से समाजवाद में आता है ? दूसरी तरह हमारे जनसंघ के नेता ने कहा है कि चुनावों के दौरान लाठी चली है और दूसरी तरफ के दंगे फसाद, भय, आतंक की बात हुई है । वे भी इस मध्यावधि चुनावों में एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे । आप बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे थे । वहां पर दो नीतियों का संघर्ष था । भैरोंसिंह जी कोई जागीरदार नहीं हैं, पूंजीपति नहीं हैं, वे एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ भी एक कार्यकर्ता था·····

श्री देवीदत्त गाड़िया : रशिया का पैसा लगा हुआ था·····

श्री रामनारायण चौधरी : बाड़मेर का संघर्ष एक नीतियों का संघर्ष था । वह नीति थी एक तरफ जनसंघ दल की और दूसरी तरफ की नीति थी कांग्रेस दल की । वहां पर कांग्रेस दल की नीति की विजय हुई है और जनसंघ के दल के नीति की हार हुई है । भैरोंसिंह ने जो कहा है उससे मुझे अफसोस है । इनके मुकाबले में दूसरी तरफ कौन थे । वहां पर हिन्दुस्तान के पूंजीपति थे, उनके पैसों का खुला प्रदर्शन था, राजा महाराजा और उनके समर्थकों का खुला प्रदर्शन हो रहा था । उनके मुकाबले सार्वजनिक साधारण कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़ रहे थे·····

श्री देवीदत्त गाड़िया : शिवनाथसिंह को मुरारका ने दो लाख रुपये दिये थे ।

श्री रामनारायण चौधरी: वहां की जनता ने सोच समझ कर यह तय किया है कि वह गरीबों के साथ रहे वरना झुंझनूं, नागौर, सीकर और दौसा के कार्यकर्ता जो कांग्रेस की तरफ से थे वे आर्थिक दृष्टि से उतने सम्पन्न नहीं थे जितने दूसरे पक्ष के उम्मीदवार थे । उनके पास में अतुल धन था और दूसरी तरफ साधनों का अभाव था लेकिन जनता ने अपने मतदान से साफ कर दिया है जिसकी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था । इस प्रकार से यह सब फैसला हो गया है दौसा से नवलकिशोर, भरतपुर से राजबहादुर, झुंझुनूं से शिवनाथसिंह, नागौर से नाथूराम मिर्धा और सीकर से श्रीकिशन मोदी, ये सब साधारण कार्यकर्ता हैं और ऐसे परिवारों से आये है जो सामने वाले के मुकाबले कम साधन सम्पन्न थे । उनका और इनका कोई मुकाबला साधनों में नहीं था । और ये लाखों वोटों से जीते हैं । मुल्क में यह फैसला होना था कि आज हमें किधर जाना है । यह एक सीधा सा प्रश्न है जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

सामने था। यह कहना कि मतदाताओं को दबाया गया, भय दिखाया गया, डराया गया, आतंकित किया गया, यह सब निराधार बात है। न तो कोई आतंकित ही किया गया है, न भय, प्रलोभन ही दिया गया है। यह निश्चित रूप से सही है कि लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज पैसे वालों को, सामन्तों को, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को और उनके समर्थकों को हराना है, यह उस क्षेत्र के मतदाताओं का संकल्प था। इस इलाके से जो फैसला हुआ है वह देश के हित में हुआ है और यह एक शुभ लक्षण है कि जनता की जीत हुई है और निहित स्वार्थ वाले लोगों की नीतियों की हार हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुल्क में जो समाजवादी समाज व्यवस्था लाने की चर्चा है, जो हमारे सामने तरीका है, उसके ऊपर हमें और हमारी सरकार को ध्यानपूर्वक अमल करना चाहिये। समाजवाद कोई सीमित शब्द ही नहीं हैं। समाजवाद एक व्यवस्था है। कुछ कल-कारखानों और कुछ व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार का नियन्त्रण, कारखानों का राष्ट्रीयकरण ही कोई समाजवादी व्यवस्था नहीं है। समाजवादी व्यवस्था समाज में वह एक व्यवस्था है जिस के अन्दर समाज के प्रत्येक तबके को इन्साफ मिले, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की रोटी रोजी की व्यवस्था हो, शिक्षा और चिकित्सा समाज में व्यवस्थित रूप से हो, तो वह एक समाजवादी व्यवस्था मानी जाती है। आज हमारे मुल्क में इस बात की जरूरत है कि हम पिछड़े हुए लोगों को आगे लावें और उनको आगे उठावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे कि आज हमारे प्रदेश में सब लोगों को अदालतों के जरिये या सरकार के जो साधन हैं, जो साधन सरकार के डिस्पोजल पर हैं, जो व्यवस्था सरकार के पास में है उसके जरिये आम जनता को मदद मिले। मैं यह मानता हूं कि समाजवादी व्यवस्था मुल्क में लाना केन्द्रीय सरकार का काम है, प्रदेश की व्यवस्था प्रदेश की सरकारों के हाथों में है, उसकी सीधी जिम्मेदारी उसकी है और इन व्यवस्थाओं में आमुल-चूल परिवर्तन होना चाहिये। आज यदि किसी कल कारखाने का राष्ट्रीयकरण होता है और राष्ट्रीयकरण होने के बाद उसकी व्यवस्था खराब हो जाती है, उस नीति के कारण व्यवस्था खराब हो तो वह राष्ट्रीयकरण और समाजवादी व्यवस्था एक प्रकार का आडम्बर हो जाता है। आज हमें और हमारी सरकार को इस बात से कौन रोकता है, कौन सी अड़चन इस बात में है? जितनी चीजें सरकार के हाथ में हैं उनमें सुधार हो और उन में सुधार नहीं होता है तो यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है सरकारी व्यवस्थाओं में। यदि ऐसी कोई व्यवस्था है जो जनता को इन्साफ नहीं दिलाती है तो हमें इसमें सुधार करना चाहिये। जो अदालतें है, हमारे संविधान और कानून के अन्तर्गत—उनमें आज क्या हालत है। यह राज्य

(श्री रामनारायण चौधरी)

सरकार का विषय है कि लोगों को न्यायिक न्याय, निर्णय मिले और इन अदालतों के मार्फत सस्ता इन्साफ उन लोगों को मिले इसकी समुचित व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आज अदालतों में साफ रूप से देखियेगा–जितने भी ज्युडिशियल कोर्ट्स है, रेवेन्यू कोर्ट्स है, उनके अन्दर क्या हालात है? क्या हमें उनके काम से सन्तोष है? क्या ज्यूडिशियल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स के अन्दर हमारे लोगों को आसानी से और सस्ता इन्साफ मिल रहा है? और यदि नहीं मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि शासन में जो बैठे हैं वे इस बारे में भूल में हैं। आज अदालतों में 10/15 और 20 वर्षों से मुकदमें चल रहे हैं और उनका कोई विचार नहीं हो रहा है इतने वर्षों तक क्यों ये चल रहे हैं? तारीखों पर तारीखें पड़ती जा रही हैं। इसका कोई हिसाब नहीं है कि कितने दिनों के अन्दर इनका फैसला हो जाना चाहिये अदालतों में जिस रूप का भ्रष्टाचार है अदालतों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार, पक्षपात चलता है, यह राज्य सरकार का काम है, उसको देखना है कि प्रदेश की जनता को सस्ता और निष्पक्ष, बिना किसी भय के इन्साफ मिले–इसकी तरफ देखा जाना चाहिये। आज रेवेन्यू कोर्ट और दूसरी कोर्टों में जितनी देरी से मुकदमों का फैसला होता है, वह जल्दी होना चाहिये ताकि लोगों को शीघ्र इन्साफ मिले। मैं समाजवाद की मांग करने वाले और जिनके हाथ में समाजवादी व्यवस्था लाने का काम है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं यदि प्रशासन में, अदालतों में हम इन्साफ नहीं करेंगे, इन्साफ करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करेंगे और जनता को यह भरोसा नहीं दिलायेंगे तो लोगों में बड़ा भारी असन्तोष फैलेगा और लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जायेगी। आज आप साधारण से साधारण लोगों से पूछेंगे कि क्या हालत है तो वे यही कहेंगे कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। पैसे उसके पास नहीं हैं मुकदमा लड़ने के लिये और केसेज इतने लम्बे चलते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय अपनी सरकार से सस्ता इन्साफ करवायें ताकि लोग राहत से रह सकें।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वह है शिक्षा की उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के मामले में सभी बैचेन हैं पढ़ने वाले बेचैन। पढाने वाले अध्यापक बेचैन और लड़कों के माता पिता हैं वे भी इस शिक्षा से बेचैन। तो इसका क्या कारण है? आज शिक्षा का स्तर हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश में कितना गिर गया है? इस बात की हमें जांच करनी चाहिये और हमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये। आज कई देहाती प्राइमरी और सेकेन्डरी स्कूलों की यह हालत है कि बिना अध्यापकों के कक्षायें खाली पड़ी रहती हैं। समय पर उनको शिक्षा नहीं दी जाती हैं। स्कूल के स्कूल खाली पड़े रहते हैं। जहां पर साइन्स का विषय है एन्युअल एक्जामिनेशन आ गया है लेकिन वहां कोई विज्ञान के विषय को पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। इस प्रकार के स्कूल खोलने से क्या फायदा? विज्ञान के अध्यापक वहां नहीं भेजते हैं–लड़के बिना

(श्री रामनारायण चौधरी)

शिक्षा के बैठे हैं। लड़कों का सारा समय बिना पढ़े निकल गया और माता पिताओं का खर्चा लग गया। यह कारण है जिससे समाज में असन्तोष फैलता है और यही असन्तोष आगे जाकर भंयकर रूप धारण कर लेता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को कि शिक्षा की तरफ उचित ध्यान दे। शिक्षा समाज की बुनियादी है। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वह एक सुयोग्य नागरिक बनेगा, अनुशासन प्रिय सिपाही बनेगा और मुल्क के काम आयगा।

आज चिकित्सा के बारे में भी यही हाल है। गरीबों की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है। आज वे ही लोग चिकित्सा का फायदा उठाते हैं, जिनके पास पैसा है। सरकार को माकूल व्यवस्था करनी चाहिये। जितने चिकित्सा के साधन हमारे पास हैं उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो–यह देखना है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था में गरीब कर्मचारियों को जो लो पेड एम्पलाइज हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है। जितना बजट चिकित्सा के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होता है उसके हिसाब से देखेंगे तो तीन बटा चार हिस्सा यानि तिहाई हिस्सा तो गजेटेड आफिसर उठा लेते हैं और वन फोर्थ यानि चौथाई हिस्सा नान गजेटेड स्टाफ यानि लो पेड एम्पलाइज उठाते हैं। एक एक अधिकारी का एक एक हजार का मेडिकल रिएम्बर्समेंट होता है। मेरा निवेदन है गरीब कर्मचारी किस प्रकार अपना इलाज करवाये यह हमें सोचना है। मैंने ऐसे कर्मचारियों से बात की जिन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को एक मुश्त किसी रूप में दिया जाय तो वह अच्छा है ताकि उनको 20 या 25 या जो कुछ भी हो हर महीने मिलता रहेगा। आज गरीब कर्मचारियों की यह हालत है कि दो दो, तीन तीन वर्षों से बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। मुझे चूरू जिले के अध्यापक ने बताया, दो दो, तीन तीन वर्षों से मेडिकल बिल पड़े हैं उनके भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। एक गजेटेड आफिसर जो स्वयं ड्राइंग आफिसर होता है उसका एक भी बिल अन–पेड नहीं मिलेगा। इसका क्या कारण है ? गरीब कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है। जिनके हाथ में बिल बनाना और पास करना है वे अपने तो करते हैं और गरीब कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जो हमारे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनकी चिकित्सा की कोई स्थाई व्यवस्था हो। उनको सरकारी मशीनरी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरा मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं। आज मुल्क की सफलता के लिये, लोकतन्त्र को बचाये रखने के लिये दो तबके ऐसे हैं जिनकी निहायत आवश्यकता है। हमें हमारे सैनिकों की आवश्यकता है और प्रदेश में हमें हमारे सिपाहियों की आवश्यकता है। ये दो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है जो कि देश के लोकतन्त्र को सुरक्षित रखने के लिये अनिवार्य हैं। भारत सरकार ने यह उचित निर्णय किया है, उनको एड हाक ग्रान्ट दी है। भारत की सेनाओं में काम करने वाली सेवाओं को अधिक इन्क्रीमेंट दिया जाय। प्रदेश सरकारों

(श्री रामनारायण चौधरी)
का भी यह काम है कि हमारे पुलिस में काम करने वाले जो लो पेड एम्पलाइज हैं जिनकी जिम्मेदारी इतनी गहन है उनकी दशा की तरफ देखकर हमें सोचना पड़ेगा लेकिन हम बराबर उपेक्षा कर रहे हैं। मैं इस बात की उम्मीद करता था जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को एडहाक इन्क्रीमेंट दिया गया है उसी तरह कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिये जो अपनी जान हथेली पर रख कर चलते हैं, प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं और जो और विभागों को दिया गया है उसको देखते हुये कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं तमाम कर्मचारियों को अलग रख कर पुलिस के कर्मचारियों की तरफ विशेष ध्यान देकर ऐड हाक इन्क्रीमेंट देना चाहिये।

हमारे प्रदेश में पंचायत राज की उपलब्धियों पर भी गौर करना चाहिये। महात्मा गांधी ने आजादी से पूर्व अपने प्रवचनों में बार बार यह कहा था। देश का स्वराज्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक गांव की एक इकाई होगी और पंचायतें होंगी और गांवों का फैसला करेंगी। ग्रामीण जनता को अदालतों से मुक्ति मिलेगी। आज पंचायत राज सफल है या नहीं मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं पंचायती राज पर एक कमीशन बैठाया जाना चाहिये और उस कमीशन की मार्फत जांच करानी चाहिये कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। यदि कोई कमी है तो उनको दूर करना चाहिये और पंचायती राज को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाना चाहिये। मैं पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों की चुनाव प्रणाली की वजह से देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी भारी लूट और वैमनस्यता का वातावरण बना हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी फूट मची हुई है, वहां के निवासियों के अन्दर मन मुटाव है। लोकतन्त्र के लिये खतरा है। हमें यदि जनतन्त्र को मजबूत करना है तो हमें गांवों को और पंचायत इकाइयों को मजबूत बनाना होगा, ग्रामीण व्यवस्था को ताकत देनी पड़ेगी पंचायतों को मजबूत करना होगा। इस बात की जांच के लिये एक अनुसन्धान कमेटी बैठाकर उसके जो निष्कर्ष आये उन पर पूरा ध्यान देना चाहिये। इसमें सबसे पहली बात यह है कि पंचायतों के चुनाव इस प्रकार से हों ताकि गांवों में कम से कम आपसी मनमुटाव और फूट पैदा हो। यह मूल प्रश्न है जिसके ऊपर विचार करना चाहिए। बड़े बड़े कस्बों और शहरों के आधार पर देश का जो लोकतंत्र है वह सुरक्षित नहीं है। शहरों और कस्बों के अन्दर फासिज्म है और आर. एस. एस. जैसी संस्थाओं के मार्फत तानाशाही प्रवृति की भावनाएं फैल रही हैं...

श्री देवीदत्त गाडिया : आर. एस. एस. तो ऐसी संस्था है जो राष्ट्र की देशभक्ति और चरित्र निर्माण का काम करती है। रामनारायण जी आपको ज्ञान ही नहीं है। आप तो दूसरी संस्थाओं को प्रश्रय देते हैं और उनसे सांठगांठ करते हो और हमारे नवयुवक यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जाते तो जो आज भ्रष्टाचार आपको कांग्रेस में दिखाई देता है वह दिखाई नहीं देता। कांग्रेस से तो आज नैतिकता का ह्रास हुआ है और वह आपके कारण से

(श्री देवीदत गाड़िया)
हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यदि देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आप ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बनाओ । गांवों को ताकत दीजिये और यदि आप गांवों को मजबूत नहीं बनायेंगे गांवों को ताकत नहीं देंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब कि देश में फासिज्म होगा और उसका मुकाबला करने के लिए गांव के लोग ही सक्षम हैं जो कि अनुशासित हैं, जो ईमानदार हैं और जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो जातिवाद के आधार पर छात्रावास खोले हैं उसमें सारी चीजें पैदा होती हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 71 में मध्यावधि चुनाव हुए हैं । आप अनुसंधान करवा सकते हैं कि यह गांवों की व्यवस्था के कारण से ही है कि कांग्रेस इतनी विजयी हुई है । आज ग्रामीण व्यवस्था के मजबूत होने के कारण और ग्रामीण व्यवस्था में एकता होने के कारण यह विजय प्राप्त हुई है । गांवों में मामूली सी फूट होने के कारण कहीं कहीं पर इन विरोधियों के पैर जम पाये वरना गांवों में पूर्ण एकता होती और ठीक प्रकार की व्यवस्था होती तो इनका एक भी व्यक्ति जीतकर नहीं आ सकता था । इनकी जयपुर में जीत हुई है, इनकी जोधपुर में जीत हुई है, इनकी बीकानेर में जीत हुई है, इनकी उदयपुर में जीत हुई है तो यह सब सामन्तवादी व्यवस्था और सामन्ती भावनाओं के कारण से इनकी जीत हुई ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कांग्रेस की जीत भ्रष्टाचार की जीत है । कांग्रेस स्वयं नीति के आधार पर नहीं जीती है, सता के वल पर जीती है और अपने जातिवाद के आधार पर जीती है, पुलिस की गुण्डागर्दी के कारण से जीती है, और पुलिस की मदद से जीती है । नीतियों के आधार पर नहीं जीती है··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज··

श्री रामनारायण चौधरी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामों को मजबूत करने के लिए, ग्रामों की व्यवस्था के लिए जो गांवों में फूट है उससे लोगों को बचायें । इसको हमारे पंचायत मंत्री जी देखें कि गांवों में किस प्रकार से पंचायतों के चुनाव कराये जायें । पंचायतों के चुनाव इस प्रकार से हों कि जिसकी वजह से गांवों की पंचायतों में राजनीति से बचा जा सके । राजनीति गांवों में भी लाना चाहते हैं जिससे कि इनके पैर जो शहरों में जम चुके हैं गांवों में जम जायें । ये गांवों में पंचायतों के चुनावों के जरिये अपने पैर वहां भी जमाना चाहते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इस व्यवस्था में यदि आप सुधार लायेंगे तो आप मुल्क का बहुत बड़ा भला करेंगे ।

दूसरा निवेदन यह है कि आज सरकारी अधिकारियों के जो प्रमोशन महज

(श्री रामनारायण चौधरी)
सीनियोरिटी के आधार पर और कान्फिडेन्शल रिपोर्ट के आधार पर होते हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यशाली व्यवस्था है। इसमें हम किस प्रकार से आंक सकेंगे कि कान्फिडेन्शल रिपोर्ट देने वाला अधिकारी किस स्तर का है और वह महज व्यक्तिगत कारणों से कान्फिडेन्शल रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क्स देकर यह स्थिति बना देगा कि वह आगे कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो जो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं उनकी कान्फिडेन्शल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मुख्य मंत्री को होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट की कान्फिडेन्शल रिपोर्ट के आधार पर उनके नीचे के अधिकारी का गला किस प्रकार से घोटा जाता है इससे उनको बचाया जाना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि डाकुओं का सफाया किया गया है। मैं मानता हूं कि राजस्थान में जो डाकुओं का आतंक था उसको समाप्त किया गया है . . .

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सफेद पोश डाकुओं का आतंक खतम नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भी तो सफेद पोश हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कहां हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपस में बात न करें।

(श्री प्रद्युम्नसिंह एवं श्री गाड़िया एक साथ बोलने लगे)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कौनसी जनता की सेवा की। पूंजीपतियों के लड़के और समाजवाद का नारा लगायें। धौलपुर में लोगों को लूट खाया और वह समाजवाद का नारा लगा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिनके घरों में लाखों रुपया है वह समाजवाद की बात करते हैं . .

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री प्रद्युम्नसिंह के एक साथ बोलने पर) आर्डर, आर्डर प्लीज!

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जमीनों पर कब्जा कर लिया . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने नाजायज कब्जे कर लिए हजारों बीघा जमीन पर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। माननीय उपमंत्री जी।

(शोरगुल : व्यवधान)

(श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री प्रद्युम्नसिंह एक साथ बोलने लगे)

श्री देवीदत्त गाड़िया : गुलामी करते हैं सुखाड़ियाजी की . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य) आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर . .

श्री देवीदत्त गाडिया : आप डाके डलवाते हैं फिर किस बात का नारा लगाते हैं।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : भाषण काफी लम्बा हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

मैं आपका ध्यान झुंझुनूं जिले की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। झुन्झुनूं जिला राजस्थान के उन जिलों में से है जिसने वक्त वक्त पर देश के प्रत्येक ऊंचे काम के अन्दर महान योगदान दिया है। आज झुन्झुनू जिले के अन्दर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक जिले में जहां नहरें हैं उन जिलों को छोड़कर बाकी ऐसे जिलों में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां बिजली की व्यवस्था किसानों के कुओं के लिए आपको करनी चाहिए। झुंझुनूं और सीकर जिले के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वहां पर आगे के सौ सालों के अन्दर भी नहर आने की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले के किसानों की तरक्की के लिए, वहां के किसानों की गरीबी को दूर करने के लिए वहां पर बिजली का कोटा बढ़ाया जाय और किसानों को अधिक से अधिक कुओं पर बिजली उपलब्ध कराई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष ने समय ज्यादा ले लिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आज नहीं बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कन्टीन्यू है। चार दिन का समय जोड़ा गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इधर से नम्बर आना चाहिए। उधर से दो को समय दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : सब स्थिति पर विचार करके उसके बाद में समय दिया जा रहा है। समय ठीक दिया जा रहा है। श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, गत 15 मार्च को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिए पी. के. चौधरी साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने चुनाव के बारे में जिक्र किया है शान्तिपूर्ण चुनाव हुए हैं राजस्थान में उसके बारे में जिक्र

(श्री मोहनलाल मोदी)

किया है और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के समाजवाद में विश्वास करके कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। आज विरोधी दलों ने एक प्रकार का वातावरण पैदा किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पक्ष ने चुनाव में बड़े गलत तरीके अपनाये, लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण विरोधी पक्षों की तरफ से हुआ है वह इतना भारी है कि अपराधजनक माना जा सकता है। उन्होंने पैसे के बल से जनता के वोट खरीदने चाहे, जनता के मन को खरीदना चाहा। झुन्झुनूं और सीकर में जिन करोड़पतियों को खड़ा किया गया उन्होंने करोड़ों रुपया वहां पर खर्च किया और आज वे अपने अपराध को दबाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हैं··

एक माननीय सदस्य : आप भी करोड़पति हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आज आपके कहने के लिए मैं करोड़पति हो गया हूं जब कि करोड़पतियों का सफाया हो गया है और उसके पहले तो कभी भी आपने करोड़पति नहीं कहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लखपति हैं करोड़पति हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : वहां पर उन करोड़पतियों ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया और उनके साथ सामन्तवादी मिल गये, जागीरदार मिल गये और जागीरदारों ने इस प्रकार का वातावरण वहां पर पैदा किया कि कई गांवों में हमारे कार्यकर्त्ताओं को घुसने नहीं दिया। वहां पर उन गरीब वोटर्स को रोका गया। वोट देने से रोका गया।

श्री मदनसिंह : वोट के लिए आप कह रहे हैं मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : सुनने की शक्ति रखिए दांता साहब।

श्री मोहनलाल मोदी : वहां पर इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया कि वोटर्स को धमकाया गया, वोट देने के लिए आने नहीं दिया गया। यह कहा गया कि वोट डालने के लिए गया तो बाद में किस जमीन में से निकलोगे, किधर से जाओगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि माधोपुर के एक गांव के दो तीन कार्यकर्त्ता मेरे पास आये थे। अभी होली का त्यौहार था तो उन्होंने बताया कि होली का डांडा जो लगाया जाता है वह उनको नहीं रोपने दिया गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की और पुलिस की मदद से होली जलाई गई। यह स्थिति आज गांवों में पैदा की गई है।

कई माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : शेम, शेम।

श्री मोहनलाल मोदी : आज जनता ने पूंजीवाद और जातिवाद को खत्म कर दिया है। मैं सही मायने में यह कहना चाहता हूं कि चुनावों के पहले रात में गांव गांव जाकर सीकर और झुन्झुनूं जिले में 50–50 हजार और लाख लाख रुपये वोटर्स को देने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने समझ लिया था कि पैसे के बल पर विजयी होंगे। चुनाव का रिजल्ट निकलने से पहले

(श्री मोहनलाल मोदी)

ही उन लोगों ने गाजे बाजे की पूरी तैयारी कर ली थी। लोग यह समझ कर चलते थे कि हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस की जीत का उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन जनता ने पैसे को ठुकरा दिया और अपना वोट सही समाजवाद की नीति पर दिया।

आज विधान सभा में जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसमें समाजवाद की तरफ कोई संकेत नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम इस वक्त शहरी सम्पत्ति के ऊपर सीलिंग लागू करने के लिए इसमें संकेत जरूर देना चाहिए था। मैं सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने बजट में ऐसा प्रावधान जरूर रखें और शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग जरूर करें।

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक एक हजार आदमियों को एक एक जिले में रोजगार देने का निर्णय लिया है। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि बहुत से पढ़े लिखे लोग बेकार हैं। एक हजार आदमियों को एक एक जिले में रोजगार देकर बेरोजगारी किस प्रकार से मिटा सकेंगे? जो हमने जनता को विश्वास दिलाया है कि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करेंगे तो इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस सरकार को एक एक जिले में 5-5 हजार लोगों को रोजगार देने का निर्णय लेकर चलना चाहिए।

आज जो स्थिति है हमारे राजस्थान में वह मैं आप से कहना चाहूंगा। हरिजनों के लड़के जो पढ़े लिखे हैं वे 4-5 साल से बेकार है, और उनको सर्विस नहीं मिल रही है। हमें हमारे समाज-कल्याण विभाग के द्वारा यह बताया गया है कि इनकी संख्या 28% राजस्थान में कर दी है। जितनी सर्विसेज हैं उनका 28% उनके लिए रिजर्व रखा जायगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कोरे कागज पर ही 28% देखा जाता है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि मेरे जिले के अन्दर बहुत से हरिजन लड़के बेकार फिर रहे हैं। पढ़े-लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी दिलाने का जो दफ्तर है, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज वह नौकरी दिलाने का नहीं बल्कि नौकरी दिलाने में रुकावट पैदा करने वाला दफ्तर है। आज सभी पढ़े लिखे बेकार लड़कों के नाम उनके यहां से नहीं भेजे जाते हैं, सही लिस्ट उनके पास नहीं है। पिछले वक्त का जिक्र करता हूं कि सीकर में 65-66 के लड़के जो एस. टी. सी. ट्रेण्ड हैं उनको नहीं लिया गया और 68-69 और 69-70 के लोगों को लिया गया है। ऐसी स्थिति जब तक दूर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस प्रकार का निर्णय लें कि जो एस. टी. सी. ट्रेण्ड लड़के हैं 65-66 के उनको प्रायोरिटी के हिसाब से सर्विस दें ताकि जो पढ़े-लिखे नवयुवक हैं उनका तो असन्तोष दूर हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मोदीजी, किस को सुना रहे हो? कोई मंत्री नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों का आना जरूरी है।

(श्री मदनसिंह)
कई दफा विधान सभा में यह बात हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय विराजमान हैं।

एक माननीय सदस्य : वे पहले रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य : समाजवाद की बात चले तो मंत्रियों को समाजवाद की बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू में हुआ उस वक्त तो थोड़ा बहुत कर्जा मिला, लेकिन बैंकों की ऐसी स्थिति है कि आज किसानों को बैंकों से कर्जा नहीं मिलता है। पंचायत समितियों के माध्यम से जो कर्जा उनको मिलता था, वह उनको मिलता नहीं है। किसान परेशान हैं। पंचायत समितियों द्वारा उनको कर्जे की व्यवस्था कराई जाये। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा नीम के थाने में है। वहां के जो बैंक के एजेन्ट हैं, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि 10 मील से दूर के रहने वाले हों, इसलिए हम दरख्वात रिजेक्ट करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह स्टेट बैंक ने 10 मील की दूरी लगा दी है, उसको हटाया जाये। एक जगह एक दो किसान कर्जा लेने वाले हैं तो उनको कर्जा नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि कम से कम 15-20 किसान हों तो उनको कर्जा देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। किसानों को कर्जा चाहिए। किसी गांव में किसानों के दो कुवे हैं तो किसी के 4 कुवे हैं। वह कहते हैं इकट्ठी 15-20 दरख्वात एक गांव की होंगी तो कर्जा देंगे। इसलिए कर्जा किसी को मिल नहीं पाता है। एक और बात है, इन बैंकों में पहले भ्रष्टाचार नहीं था अब भ्रष्टाचार हो गया है। कहते हैं कि जयपुर से सैंक्शन लेकर आयेंगे तब कर्जा मिलेगा। ऐसी सूरत में सही फायदा नहीं हो पाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को अधिक से अधिक कर्जा मिले और सरल ढंग से मिले, इसकी व्यवस्था की जाये।

खनिज उद्योग के बारे में राजस्थान में बहुत ही सौभाग्य की बात है। खनिज सम्पदा हमारे प्रदेश में बहुत है। लेकिन सही ढंग से खनिज के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं किया जाता है। खनिज पहाडों में मिलते हैं। वहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि खनिज सम्पदा का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए सड़कों का निर्माण होना चाहिए। मशीनरी के साधन भी उपलब्ध कराये जायं जिससे कि साधारण आदमी भी लाभ उठा सके। अभी सलेदीपुरा खण्डेला के पास खनिज का पैराइट्स के काफी भण्डार पाये गये हैं। उसका लाभ लिया जाये वहीं कारखाना लगाया जाये। रामपुरा के पास लाइम स्टोन है। वहां सीमेन्ट फैक्ट्री लगाई जा सकती है। वहां बिरला बन्धुओं को लाइसेन्स देने की चर्चा चल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि बड़े उद्योग लगाये जाने चाहिए, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत लोगों

(श्री मोहनलाल मोदी)
को नहीं दिये जाने चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाना लगाना चाहिए। राक-फास्फेट से 2.50 करोड़ की इन्कम बताई गई है। जबकि यह इन्कम हमको कम से कम 5 करोड़ की मिलनी चाहिए। इस पर 5 करोड़ शुद्ध लाभ मिलना चाहिए। कहां खर्चा हो रहा है। हमारी इन्कम में कहां खर्चा अधिक हो रहा है।

समाज कल्याण के कार्यों का यहां जिक्र किया गया है। पहले हरिजनों, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए साढ़े 12 प्रतिशत स्थान सर्विस में सुरक्षित थे। अब 28 प्रतिशत कर दिये हैं। अब तो कोई बेकार नहीं रहना चाहिए। आज हरिजनों का कोई भी बच्चा बेकार नहीं रहे। हमको सबसे पहले उनको नौकरी देनी चाहिए जो गरीब हैं। जिनके घर में खाने को नहीं है। किसी घर में 10 नौकरी करते हैं, उसमें 11वें को भी नौकरी मिल जाये। देखा यह जाता है कि उसी के घर के व्यक्ति को नौकरी मिलती है। पढ़े लिखे व्यक्ति फिरते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं राज्य मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप ऐसी परम्परा डालें जिससे कि हरिजनों के पढ़े लिखे बच्चे बेकार नहीं रहें। अगर उनको सर्विस नहीं दी जाये तो उनको बेकारी का भत्ता दिया जाय। जब तक कि उनको सर्विस नहीं मिले।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि अभी गान्धी शताब्दी वर्ष में हमारे यहां जयपुर में यू. आई. टी. द्वारा हरिजनों के नाम से प्लाट अलाट किये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सब बड़े लोगों को दिये गये हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं को दिये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक भी प्लाट किसी गरीब आदमी को नहीं दिया गया। कोई एम.एल. ए. है। कोई एम. पी. है। कोई कलेक्टर है। ऐसे लोगों को प्लाट दिये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने जिनका उल्लेख किया है, उनके नाम बता दें।

श्री मोहनलाल मोदी : वह आपके लिए छोड़ दिये हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप नाम बतायें।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने प्लाट दिये हैं, वह किसके नाम दिये हैं?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप नाम नहीं दे सकते हैं?

श्री मदनसिंह : नाम बता दें।

श्री मोहनलाल मोदी : उनके नाम हैं, छगनलाल, गणपतलाल डांगी, लादूराम सुलानिया, पन्नालाल बारूपाल, रामचन्द्र मीणा, जिलाधीश इस प्रकार के लोग हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : जगन्नाथ पहाड़िया नहीं है?

श्री मोहनलाल मोदी : आप ऐसे लोगों को देते हैं। जिनको ऊंची तनख्वाह मिलती है, उनको देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जिनके बंगले अलग है।

श्री मोहनलाल मोदी : उनका कैंसिल करके हरिजनों को दी जाये। समाज-कल्याण मन्त्री महोदय, आप हरिजनों के मुहल्लों में गये हो तो आपने देखा होगा कि घरों पर फूस के छप्पर तक नहीं हैं। छोटे छोटे कच्चे घर हैं जिनमें मां, बाप, बेटे, बहू उसमें रहते हैं। आप अन्दाज लगाइये। आप राज्य से सहायता देना चाहते हैं। सहायता हरिजनों के नाम से देना चाहते हैं। लेकिन यह उनको दी जाती है, जिनको सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण की सहायता उन लोगों को दीजिये जो वास्तव में उस सहायता के अधिकारी हैं। 179600 भूमिहीन लोगों को जो जमीन दी है उसके बारे में मेरी मान्यता है कि वह कागजी कार्यवाही है। किसी को कब्जा नहीं मिला। किसी पर केस दायर हो गया है। अलॉटमेण्ट तो कर दिया लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह केस लड़ सके। आप दो, चार या पांच बीघा जो भी जमीन उसे दें वह ऐसी दें जिसमें किसी और का दखल नहीं हो। अगर कोई झगड़ा होता है तो उसकी व्यवस्था करें। आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपके आफीसर स्पॉट पर जाकर फैसला कर दें। मेरे क्षेत्र में भी हरिजनों को जमीन अलॉट की है। उसका भी यही मामला है। किसी हरिजन को अलॉट हुई तो कब्जा नहीं मिला। अगर हुआ तो स्टे हो गया। केस दायर हो गया। हरिजनों की इतनी क्षमता नहीं है कि वह केस जाकर लड़ सकें। ऐसे केसेज में लिमिट होनी चाहिये। ऑफिसर स्पॉट पर जाये और वहीं फैसला करें तभी सही माने में कुछ हो सकता है।

पेयजल के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में पेयजल की इतनी बड़ी कमी है, मैं अभी चुनाव के सिलसिले में मंडावर साइड में गया था। वहां चालीस गांवों की बेल्ट है, वहां पर खारा पानी है। लोगों को मीठा पानी नहीं मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारी राज्य मन्त्री, जो जन स्वास्थ्य विभाग की मंत्री हैं, वह झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं, लेकिन उनका ध्यान इन गांवों की ओर नहीं जाता है कि वहां ऐसी स्थिति है। जो मन्त्री है, वह अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी का ही ध्यान रखती हैं, बाकी के लोग प्यासे मरें, भूखे मरें—उनका कोई ध्यान नहीं रखता है। जन स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री, हमारे झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर पेयजल के बारे में तीन अच्छी योजनायें सेंक्शन करा लीं, जिनमें से दो काम कर रही हैं। डांगरी में सात सौ की आबादी है, वहां पर पाइप लाइन लग रही है। मावल में तीन सौ की आबादी है, वहां पर भी पाइप लाइन स्कीम है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या इस तरह राजस्थान के अन्दर आप समाजवाद लायेंगे, जब कि अपने पेट को ही भरने की बात करें, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी को ठीक करने की बात करें? मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, कालीखारी की स्कीम मंजूर हुई है, वहां पर दो हजार से कम की आबादी है, जब कि तय यह किया गया है कि दो हजार से कम की आबादी के अन्दर ऐसी स्कीम मंजूर नहीं की जायगी, मगर वह क्योंकि राज्य मंत्री हैं इसलिए किसी भी तरह कर लेती हैं। मैं निवेदन करना

(श्री मोहनलाल मोदी)

चाहता हूं, आपको सारे राजस्थान का ध्यान रखना है, आपको एक जिम्मेदारी की जगह पर बैठाया है वह केवल आपकी कान्स्टीटयूएन्सी के लिए नहीं बैठाया गया है। आपको सारे राजस्थान का ध्यान रखना है, उन जगहों का ध्यान रखना है जहां पर खारा पानी है। मंडावर में चालीस गांव हैं, वहां पर मीठे पानी की व्यवस्था करके आपको चालीस गांवों का उद्धार करना चाहिए था या कि अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जिस जगह दस कदम पर कुए हैं वहां करना चाहिए था? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में जिस जगह पेयजल की कमी है, जहां खारा पानी है, वहां मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले कदम उठाया जाय। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, दांतारामगढ़ तहसील के अन्दर एक बाढ़ कस्बा है, उस कस्बे के अन्दर पानी की टंकी बनी हुई है, 110 कनेक्शन वहां दिये हुए हैं। चार तारीख को वहां वोट पड़ते हैं वहां के लोगों ने बारह आना कांग्रेस के पक्ष में मत दिये तो वहां पर पांच तारीख से पानी बन्द कर दिया, यह कह कर बन्द कर दिया कि यह योजना घाटे में चल रही है, इसलिए गांव वालों से सात रुपये के बजाय दस रुपये लिए जायेंगे। यह स्थिति है राज्य कर्मचारियों की, जिनके लिए विपक्ष वाले यह कहते हैं कि यह कांग्रेस का पक्ष लेते हैं.....

श्री मदनसिंह : हम नहीं कहते। हमारे पक्ष में हैं राज्य कर्मचारी। मैं तो कहता हूँ कि यह तारीफ के लायक काम करते हैं, न्याय करते हैं, कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के राज्य में।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं उल्टा आरोप लगाता हूं इस बात का, चार तारीख को वोट पड़ते हैं, जब बारह आना लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिये तो पांच तारीख से पानी बन्द कर दिया।

श्री मदनसिंह : नहीं दिया तो सरपंच इनका है। हमको वोट दिये तो बन्द करवा दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : आप सुनने की शक्ति रखिये।

वहां बीस दिन से पानी बन्द है। कांग्रेस को वोट देने से वहां पर यह मुसीबत आई है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को निवेदन किया गया है किन्तु पानी जारी नहीं किया गया है। वहां के लोग डेढ़ मील से पानी लाते हैं। आज लोग वहां परेशान हैं। वहां ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। पानी के 110 कनेक्शन हैं उसके बाद भी कहते हैं कि घाटे में योजना चल रही है। घाटे में योजना है, तो मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस योजना को पंचायत के सुपुर्द कर दें, उसको सम्भला दें। वह एक दिन में पानी की व्यवस्था ठीक कर लेगी।

थोड़ा सा मैं बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के पास आज हरियाणा छोटी सी स्टेट है, छोटी सी जगह है, जहां गांव गांव में बिजली दे दी है। उसका जो बोर्डर है, उससे हमारा सारा इलाका मिलता है। हमारे यहां के लोगों को इस बात से बहुत बड़ी जलन सी पैदा हो रही है। उनका मानस बहुत दुःखी है इस बात से कि एक फर्लांग के ऊपर तो लाइट जलती है, वहां कुओं पर पम्प लगे हुए

(श्री मोहनलाल मोदी)

हैं, उनको पानी मिल रहा है, उसके बराबर में राजस्थान में, राजस्थान के एरिया में जो गांव आ गये हैं उनको न तो पानी मिलता है और न बिजली। ऐसी स्थिति हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे बोर्डर का एरिया हरियाणा के नजदीक पड़ता है, जो पांच-पांच, छः छः मील का एरिया है, वहां आप किसी भी प्रकार –आपको कठिनाई तो जरूर होगी क्योंकि राजस्थान के साधन कम हैं, फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी देकर हरियाणा गवर्नमेंट से बातचीत करके बिजली की व्यवस्था पूरी कीजिए। मेरा एरिया भी पास में पड़ता है। मैं कई दिनों से निवेदन करता आ रहा हूं, मेरे क्षेत्र में काफी पानी है, काफी कुए हैं, जमीन उपजाऊ है–वहां बिजली नहीं पहुंच रही है। इसलिए हरियाणा के नजदीक होने के कारण हमारे यहां के लोगों का मनोबल टूटता जा रहा है। वह कहते हैं कि हम हरियाणा में होते तो अच्छा था, बिजली तो मिलती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली पहुंचाने की तरफ पहले ध्यान दें। बिजली से पैदावार बढ़ती है, पैदावार महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आप विशेष ध्यान रख कर अधिक से अधिक गांवों में, जहां ज्यादा से ज्यादा कुए हैं, पानी ज्यादा है, काफी जमीन उपजाऊ है वहां प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक बिजली सप्लाई करने का प्रबन्ध करें।

इन सारी बातों को कहते हुए जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज !

श्री आदित्येन्द्र !

श्री आदित्येन्द्र (डीग): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का यह वर्तमान अधिवेशन सन् 1971 का प्रथम अधिवेशन है, यह अधिवेशन अब कि बार एक ऐसे समय में मिल रहा है जब कि तमाम देश में एक अजीव प्रकार की हलचल है, अभी हाल ही में मध्यावधि चुनाव सम्पन्न हुए उनका परिणाम हम सभी ने सुना और उन परिणामों में एक बात साफ सामने लाई गई कि नई कांग्रेस की विजय हुई, 350 सदस्य उनके आये, पार्लियामेन्ट के मेम्बर बन कर जब कि पूरी पार्लियामेंट की स्ट्रेन्थ 518 है, और दूसरी पार्टियां जीतने की आशा कर रही थीं उनके उतने सदस्य नहीं आ सके। इस बार एक अजीव बात हुई और मैं समझता हूं कि जो पार्टी विजयी हुई उस पार्टी के लीडर्स को भी और स्वयं प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा जी को भी ऐसा विश्वास नहीं था, ऐसी वह आशा नहीं कर रही थीं कि हमारी ऐसी निर्णयात्मक स्थिति में विजय होगी। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि यह रिजल्ट्स इस प्रकार के क्यों आये और न उन कारणों में जाने से कोई लाभ है। अब तो देखना यह है कि जो तथ्य हमारे सामने हैं उन्हीं पर हमें विचार करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस सत्र में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ वह मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का द्योतक नहीं है। वैसे आम तौर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रूलिंग पार्टी के कार्यक्रमों

(श्री आदित्येन्द्र)

और नीति के बारे में कुछ इशारा मिलता है, आगे शासनारूढ़ दल इस प्रकार से चलना चाहता है। तो यह समझ में नहीं आता····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कोरम का अभाव है।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्यों के आने से गण-पूर्ति के पश्चात्)

श्री आदित्येन्द्र : तो इस समय कुछ भी आम जनता में विश्वास पैदा किया है और आम जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाया है यह तो ठीक है, मैं भी जानता हूं लेकिन ऐसा करने से बड़ी भारी जिम्मेदारी नयी कांग्रेस पर आयी है, कांग्रेस हुकूमत पर आयी है। उस जिम्मेदारी को अगर कांग्रेस की हुकूमत ने नहीं निभाया तो उसके बाद क्या होगा–यह हम स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं। आज नारा तो हमने समाजवाद का दिया है और यह ठीक है कि आज इस नारे को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। आज कोई भी दल इस नारे के बिना नहीं चलना चाहता है चाहे वह समझे या न समझे कि समाजवाद क्या है और वास्तव में अभी तक शायद हम कोई भी नहीं समझे हैं कि समा-जवाद क्या है। समाजवाद में हरेक स्त्री पुरुष की क्या स्थिति होगी। भारत के लोग किस प्रकार रहेंगे-इसको हम कोई नहीं जानते, और न हमने इसकी कोई परिभाषा की है और इसलिये डर यह भी है कि कहीं हम कम्युनिज्म की तरफ नहीं चले जायं, वैज्ञा-निन समाजवाद की तरफ न चले जाये–यह भी हमें देखना पड़ेगा आज बहुत से लोग यह समझते हैं कि समाजवाद का अर्थ केवल राष्ट्रीयकरण है जबकि हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ भी अब तक हुआ है वह न जाने राष्ट्रीयकरण है या समाजीकरण। उसको समाजीकरण कहें या उसको एक तरह राष्ट्रीय-करण कहें। राष्ट्रीयकरण न कहकर अगर हम यह कहें कि वह हुकूमत के अन्दर आ गयी है तो उस चीज को ज्यादा कह सकते हैं लेकिन यह जो कुछ भी हो रहा है आजकल-इस बात के ऊपर भी जो हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। मैं यहां तक तो सम-झता हूं कि इस सम्बन्ध में केवल राष्ट्रीय-करण से काम नहीं चलेगा। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के बाद में किस तरह उसका अमल हुआ ? दोनों पक्षों की ओर से, ट्रेजरी बैंचों की ओर से जो माननीय सदस्य बोले हैं और विरोधी पक्ष की ओर से जिन माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, उन दोनों के विचारों से एक बात साफ है कि उसका अमल ठीक नहीं हो रहा है। बैंकों से जो कर्ज मिल रहा है वह कर्जा एक तरह से देखा जाय तो छोटे लोगों के लिये नहीं मिल रहा, बड़े आदमियों के लिए ही मिल रहा है। अगर कर्ज मिलेगा काआपरेटिव सोसाइटी या किसी और बैंक से तो वह कर्ज ट्रेक्टर के लिए ही मिल सकता है। वह कर्ज उन लोगों के लिए नहीं मिल सकता जो कि ट्रेक्टर नहीं खरीद सकते। जिनके पास थोड़ी जमीन है, जो छोटा सा धन्धा करते हैं, जो कि अपने घर में ही थोड़ी पूंजी लगा कर या उनके परिवारों के लोग जो काम करते हैं आज उनके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो इस तरह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी हम देखें तो आज डेढ साल हो गया इस

(श्री आदित्येन्द्र)

डेढ़ साल में वास्तव में जो गरीब हैं उनको मदद नहीं मिलती है। इस तरह से दूसरा जो काम राष्ट्रीयकरण से हुआ आज राजस्थान में ट्रान्सपोर्ट को देखलें जो बसेज का राष्ट्रीयकरण हुआ है उस बस के राष्ट्रीयकरण की हालत हम देखें तो वास्तव में हम सबको बड़ा दुख होगा। जब कभी भी हम यहां से थोड़ी दूर ही, थोड़ी देर के लिये यात्रा करते हैं 100–150 मील की भी, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब कभी मैं जयपुर से भरतपुर या आगरा गया मैंने हमेशा यह देखा कि गाड़ी थोड़ी देर के बाद ही 40 मील की यात्रा के बाद कम से कम एक बार जरूर गाड़ी, बस जरूर खराब होगी, घंटे भर वहां पड़ी रहेगी। दूसरी बात यह है कि ड्राईवर बीच में ठहर जायेगा 10 मिनट के बजाय वह वहां 25 मिनट ठहर जायेगा और ठहरने के बाद अगर उसे 50 किलो मीटर रफ्तार से गाड़ी चलाना है तो वह 60–70 किलो मीटर की रफ्तार कर देता है। इस तरह सब हालत उन सभी को मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस हालात में अगर हम सुधार नहीं कर सकते हैं तो सुधार नहीं करने से नतीजा यह होगा कि यह समाजवाद जिस के बारे में हम इतनी चर्चा करते हैं और जिसके बारे में हमारे देश के प्राइममिनिस्टर समाजवाद की बात करती हैं वह समाजवाद नहीं आयेगा। आज कभी कभी हम आरोप लगाते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर और हम यह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है और बहुत बड़े पैमाने पर है। ये भ्रष्टाचार बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारियों में भी है और छोटे से छोटे कर्मचारियों में भी है। सन् 1947 में हमने एक नयी हवा देखी जबकि हमने एक नया नारा दिया उस वक्त कर्मचारियों में भ्रष्टाचार कम हुआ। उस वक्त एक बार सरकारी कर्मचारियों के मन में एक बात आई कि इस शासन में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और उन्होंने एक बार तो रिश्वत लेना छोड़ दिया था लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे राजनैतिक नेता ही भ्रष्ट हैं और रिश्वत लेते हैं तो उन्होंने भी सोचा हम भी इस काम को शुरू क्यों नहीं करें। मैं तो आज भी ज्यादा आरोप सरकारी कर्मचारियों पर तो नहीं लगाता हूं लेकिन मैं जो कुछ भी है उसमें दोष राजनैतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं का ही ज्यादा मानता हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि शासनारूढ़ दल वालों के ही जो कार्यकर्ता हैं वे ही भ्रष्ट हैं या उनके दोष हैं चाहे कोई भी नेता है, एम. एल. ए. है उन्हीं पर दोष लगावे या वही दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक हम इस दोष को नहीं मानेंगे उसे स्वा..र नहीं करेंगे तब तक हम किसी प्रकार देश .ो आगे नहीं ले जा सकेंगे। आज हमारे सामने चेलेन्ज है और वह चेलेन्ज यह है कि आज या तो समाजवाद हम शान्तिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के जरिये डेमोक्रेसी के जरिये या तो स्थापित करलें और अगर स्थापित नहीं कर सकें तो इसका दूसरा मार्ग वही है जिस रास्ते पर चल कर चीन

(श्री आदित्येन्द्र)

ने समाजवाद की स्थापना की, रूस ने समाजवाद की स्थापना की, या और दूसरे देशों ने समाजवाद की स्थापना की। लेकिन हिन्दुस्तान में हमने एक नयी चीज 1947 से पहले दी थी। 1947 की आजादी एक दूसरे और नये तरीके से प्राप्त की गई और उसकी वजह से हमारा तमाम दुनिया में नाम हो गया और बहुत से लोगों के लिये यह एक प्रकार से एक नयी स्थिति थी और उन्हें सन्तोष भी हुआ कि यह एक नया रास्ता है जिस रास्ते पर चल कर हम अपने आपको सुखी बना सकते हैं, समृद्धिशाली बना सकते हैं, लेकिन इन 22–23 सालों में हमने देख लिया कि हम शायद इस रास्ते पर चलते हुए अपने आपको सुखी नहीं बना सकते। हम, एक तरफ देखा जाय तो लोकतन्त्र को ही भुला रहे हैं और लोकतन्त्र से भी दूर होते जा रहे हैं जो कुछ भी आज हो रहा है और विधान सभा में और दूसरी विधान सभाओं के बाहर कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है कि हम यह नहीं देखें कि आज 5–7–10 आदमियों कि हत्या नहीं हुई, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन यह न देखें कि आज गोली नही चली।

(3.10 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

वहां हम कैसे कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र है ? सच्चा लोकतंत्र इससे साबित नहीं होगा। मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं ज्यादा सुझावों के लिए न मेरे पास समय है और न इस समय मौका ही है ऐसे मौके दूसरे आयेंगे, उनमें सुझाव दूंगा। कुछ ऐसे सुझाव मेरे अलावा बहुत से और हमारे साथियों ने दिए हैं। पिछले तीन-चार सालों में 1967 के चुनावों के बाद भी दिये हैं लेकिन शायद या तो सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है या सरकार ध्यान देना चाहती है, तो सरकार में हिम्मत नहीं है।

सबसे पहले सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वास्तव में हम समाजवादी व्यवस्था अपने देश में या राज्य में कायम करना चाहते हैं तो यह जो हमारा बड़ा मंत्रिमंडल है 40 आदमियों का, इस 40 व्यक्तियों के मंत्रिमंडल को छोटा करना पड़ेगा। आप चाहे कितना जोर लगायें अगर इस मंत्रिमंडल को छोटा नहीं कर सकते तो मेरा कहना है और मैं समझता हूं दूसरे लोगों का भी कहना है कि आप समाजवाद नहीं ला सकते। आज क्या बात है ? क्यों नहीं ऐसा कर सकते ? अक्सर दलील दी जाती है कि हालात बड़े अजीब हैं। बड़े से बड़ा आदमी चाहे वह लोकसभा सदस्य है चाहे विधान सभा सदस्य है, अगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं और डर यह है कि अगर इस मंत्रिमण्डल को छोटा किया जाए और कम से कम आदमी उसमें लिए जायं तो डर है कि यह मंत्रिमंडल कहीं टूट न जाए। कांग्रेस सरकार है उसके लोग टूटकर दूसरे दलों में चले जाएं, यह वे समझते हैं। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं और अपने सभी विरोधी दलों से अपील करना चाहता हूं कि यदि कोई मंत्रिमंडल टूटने के कारण लोग दल बदलकर हमारी पार्टियों में आना चाहते हैं हमको उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, उनको अपना सदस्य

(श्री आदित्येन्द्र)

नहीं बनाना चाहिए । हम चाहते हैं कि आप मंत्रिमंडल छोटा करें । मंत्रिमंडल में 15 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए जो अच्छे से अच्छे आदमी हों । जहां एक ओर इससे खर्चे में कमी आएगी वहां आम जनता में विश्वास पैदा होगा कि यह वास्तव में काम करना चाहते हैं ।

आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जीत हुई । इसलिए हुई कि हमने समाजवाद का नारा तो दिया । ठीक है समाजवाद का नारा तो दिया लेकिन मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी जो बनी है, उसकी विजय नहीं है । वास्तव में देखा जाय तो यह एक व्यक्ति की विजय है याने प्रधान मंत्री की विजय है । प्रधान मंत्री ने नारा दिया और प्रधान मंत्री ने जगह जगह पर इस डेढ महीने या 40 दिन के अन्दर जिस फुर्ती के साथ 15-15 20-20 जगह पर पहुंच गई और उन्होंने भाषण किए और अपनी बात को कहा । वह वास्तव में एक बात थी और उसने इस हवा को बनाया लेकिन क्या हम विश्वास नहीं करते कि आज अगर हम सब जगह पर खर्चा कम करें और सबसे पहले जो हमारी सर्वोच्च व्यवस्था है उसमें अपना खर्चा कम कर दें और मंत्रिमंडल को छोटा कर दें तो दूसरे लोगों पर भी इस बात का असर पड़ेगा ।

एक बात मैं और कहना चाहता था लेकिन उसको आज नहीं कहूंगा । आज शायद उस बात का इतना असर न हो जितना कि होना चाहिए और उस बात को इसी अधिवेशन के अन्दर अपनी बात को कहूंगा उस समय कि और क्या करना चाहिये लेकिन इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की कमी का अच्छा असर होगा ।

दूसरी बात जहां कहीं राष्ट्रीयकरण करें और चाहे मिल हो या फैक्ट्री । जैसे मान लीजिए गंगानगर शुगर मिल और दूसरी फैक्ट्रीज हैं जिनको हम पब्लिक सैक्टर में खोलना चाहते हैं, उनमें शासन इस प्रकार नहीं चलना चाहिये जैसे एक सरकारी महकमे में चल रहा है । उनमें हमें देखना चाहिये कि जो वहां बड़े से बड़ा अधिकारी है और वहां का जो निम्न से निम्न वर्ग का कर्मचारी है उन दोनों की आमदनी में ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए । मेरे हिसाब से उन दोनों की आमदनी में 3 गुने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए । अगर छोटे से छोटे कर्मचारी को 200) रु. दें तो बड़े से बड़े कर्मचारी को 600) रु. देना चाहिये वह सब लोग एक समाजवाद में रहते हैं । वहां जरूरत नहीं है कि कोई आई. ए. एस. जाय या आर.ए. एस. जाए । हम दूसरे देशों से उदाहरण लें । आज अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च अधिकारी हैं और एक चपरासी है, जिस समय दोनों आफिस में बैठते हैं तो वहां जरूर छोटा कर्मचारी सर्वोच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करेगा लेकिन जब वह आफिस के बाहर आ जाते हैं और अपने निजी जीवन में आते हैं किसी होटल में जाते हैं या शादी व्याह में जाते हैं तो आपस में बराबर का वर्ताव करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं लेकिन हमारा जीवन अभी तक सामंतवादी है ।

(श्री आदित्येन्द्र)

संत विनोबाजी ने तीन सूत्र बताये हैं जो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही है कि हमारा जीवन या संस्कार सब एक तरह से सामंतवादी हैं याने सामंतवाद में हम पले हैं। हमारे संस्कार जन्म से आखिर तक अगर हमारे ब्याह शादियां होती हैं तो भी उनमें सामंतवाद है। अगर दूसरा कोई काम होता है, मान लीजिए बिजनेस का प्रारम्भ होता है कि किसी फैक्ट्री का उद्घाटन होता है तो उसमें सामंतवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। पहले जो श्रमदान करते थे जो सादगी का जीवन बिताते थे, वहां पर भी हमारे संस्कार सामंतवादी थे। उद्घाटन मंत्री से ही कराना चाहते हैं। मंत्री से परिश्रम नहीं कराना चाहते उनसे कहा जाता है कि आप केवल हाथ लगायें वही काफी है, बाकी काम हम सब करेंगे। श्रमदान बंद हो गया। मंत्री महोदय और दूसरे नेता एक जगह आ गए। टोकडी कंधे पर रख दी और फावड़ा रख दिया, यह चीज हमने देश में देखी।

चीन के बारे में हम भला बुरा कहते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि वहां पर क्या है? वहां 8-10 साल पहले मैंने स्वयं कई बार अखबारों में पढ़ा है वहां पर जो श्रमदान हो रहा था, सुरक्षा से नदियों पर बंरक्स बनाए जा रहे थे और 40-40 मील तक काम हो रहे थे उनमें चाऊ-एन-लाई और माओत्सेतुंग जो राष्ट्रपति थे, सब लोगों ने वहां की शिविरों में उन्होंने और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तीन तीन दिन तक काम किया। उनको पसीना आ गया, 6–6 घंटे तक लगातार काम करते रहे लेकिन आज कोई काम नहीं करना चाहता। हम समझते हैं यह बडा आदमी है यह छोटा है तो एक तरह से हमारा जीवन और संस्कार सामंतवादी हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं वह पूंजीवादी हैं। हरेक चाहता है कि एक बार मैं सत्ता में आ गया तो उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर एक बार एम. एल. ए. बन गया या एम. पी. बन गया, एम. एल. ए. की बात तो दूर यदि पंच या सरपंच भी बन गया। तो वह भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, जो एक बार किसी पद पर पहुंच गया, चुनाव में आ गया तो उसने अपने काम के अलावा कमाना भी शुरू कर दिया। रिश्वत लेना भी शुरू कर दिया। सिफारिश लेना भी शुरू कर दिया। काफी रुपया ले लिया। हमारी जो आकांक्षायें हैं वे इस तरह की हैं। हमारा जो उद्घोषण है, स्लोगन है यह जरूर समाजवाद का है।

अब आप यह देखें कि मन, वचन और कर्म तीनों बातों में अलग हैं। हमारे संस्कार सामन्तवादी हैं।हमारी आकांक्षायें पूंजीपति हैं और हमारे उद्घोष समाजवादी हैं। इन तीनों में कोई मेल नहीं। तीनों में विषमता। विनोबाजी ने कहा कि टिटोनस की बीमारी है। वहां क्या होगा? वहां तो मृत्यु ही अनिवार्य है। मुझे बड़ी भारी आकांक्षा भी होती है। मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है। 350 आदमी आपके आ गये। राष्ट्र आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने आपको उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के उपयुक्त बनायें। यदि नहीं, तो यह चेतावनी भी साथ है कि अगले चुनाव जो आने वाले हैं फरवरी या मार्च 72 में,

(श्री आदित्येन्द्र)

8-10 महीने बाकी रहे हैं, इन दस महीनों में काम करके नहीं दिखाया गया तो पलड़ा उलट भी सकता है जो आपने आवाज लगाई हैं कि ये तो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, उनके हाथ में सत्ता न चली जाय और पलड़ा उनके हक में न हो जाय, अब वही पलड़ा आपके कारनामों के कारण, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की तो कम्युनिस्टों के हाथ में जावेगा और उनके बारे में नयी कांग्रेस और दूसरे दल के लोग क्या कहते हैं, वह यह कहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की भूमि नहीं है कि वहां पर कम्युनिज्म पनप सके यहां तो गांधीजी की ही विचारधारा पनप सकती है। यदि आप गांधीजी की विचारधारा को एक प्रतिशत भी मानकर काम करें तो अच्छा काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में अधिवेशन चल रहा है और आम रस्म है वह अदा कर दी। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो गया। यही सरकार का कार्यक्रम और नीति है और इसी प्रकार करना चाहते हैं तो आप ही बतायें कि कहां समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

हमने शिक्षा के क्षेत्र में, मैं मानता हूं, उन्नति की। वहां पर 10-12 बच्चे पढ़ते थे वहां सौ बालक पढ़ते हैं। दस गुना लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमने सन् 47 के बाद ही इस बात की घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी ही सब ही लोगों के लिए शिक्षा मुफ्त चलायेंगे। दसवीं, ग्यारहवीं कक्षा तक 15-16 वर्ष के बच्चे के लिये निःशुल्क शिक्षा देंगे। सब ही लोगों के लिये निःशुल्क शिक्षा कहां है। आज भी हम उस बात से सैंकड़ों कोसों दूर है और इस चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में जाय तो जितने औषधालय हैं या बड़े बड़े होस्पिटल्स हैं उनको जाकर देखें तो वहां पर गरीब आदमी का तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता। गरीबों के साथ जो व्यवहार होता है वह देख लीजिये। दवाइयां गरीब को न देकर बड़े बड़े आदमियों को दे दी जाती हैं। वैसे तो नहीं मिलती है। वे चोरी से बहुत से लोगों के पास चली जाती हैं गरीब आदमी के लिये एक भी नहीं मिलती। बाहर से पेटेन्ट दवाइयां मंगवानी पड़ती हैं। जयपुर अस्पताल में ही चले जाइये। सवेरे से शाम तक देखिये कि यहां पर कैसे लोगों के साथ और खास तौर से गरीब लोगों के साथ व्यवहार होता है। यही हाल सब अस्पतालों में होता है। हम पहली पीढ़ी के थे। हमने भी इस तरह के भाषण किये थे कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद चिकित्सा मुफ्त होगी, डाक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, डाक्टर हमारे पास आयेंगे। एक एक डाक्टर के चार्ज में पचास पचास घर होंगे। वह उनके पास जावेगा और यदि कोई बीमार हो जावेगा तो डाक्टर पर जुर्माना होगा।

आवास और घरों की बात को तो गांवों में जाकर देखिये कि आवास और घरों की कोई सुविधा है क्या? खास तौर से निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके लिए कोई मदद नहीं है। आपने उनके लिये कोई साधन भी है या नहीं किये। शिड्यूल्ड कास्ट और दूसरे लोग हैं उनकी हालत जाकर देखिये। मैं स्वयं भी गांव का रहने वाला हूं। जिन गांवों में मैं गया, 15 वर्ष से मैं भी उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं कर सका। गवर्नमेन्ट तो करना नहीं

(श्री आदित्येन्द्र)

चाहती। मैं कर नहीं सका। एक तरफ आबादी बढ़ रही है। छोटी सी जगह में चालीस पचास घर हो गये हैं। जिस जमीन पर बसे हुए हैं वह ना काफी हैं। चारपाई नहीं बिछ सकती। कीचड़ वहां रहता है और वहां लोग पड़े रहते हैं। जिस प्रकार इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को जमीन देते हैं, एक्वीजिशन करते हैं, सौ सौ एकड़ है, कम से कम पंचायतें दो चार एकड़ जमीन तो रिक्विजिशन करे वह भी गांव के पास में। सार्वजनिक जमीन हो अथवा सरकारी जमीन हो तो किसी से भी मांग कर लें तो वे लोग रह सकते हैं लेकिन गांवों में आवास के नाम मात्र की व्यवस्था नहीं है। शहरों में कर्जा आवास के लिये देते हैं। मैंने तो कर्जा कभी देखा ही नहीं। भरतपुर में दो चार लाख से कभी अधिक मंजूर नहीं हुआ। सौ-दो सौ लोगों में से किसी को 8 हजार मिल गया, किसी को दो हजार, ड़ेढ हजार मिल गया। यह भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो थोड़े से साधन सम्पन्न लोग हैं। जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं जो अपने आवास बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं कच्चे ही, उन कच्चे मकानों में रहना चाहते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यहां जयपुर में ही झुग्गो झोंपड़ियों में जाकर देख लीजिये। कितनी कच्ची बस्तियां हैं। बीस-बाईस वर्ष में भी इन्तजाम नहीं हो सका।

आज हम बार बार सोचते हैं कि अबकी बार नहीं तो अगली साल हो जावेगा। उस साल भी नहीं होता है तो सोचते हैं अगली साल हो जावेगा। इसी से सन्तोष कर लेते हैं। पचास घरों का तो इन्तजाम कर लिया, पर बाकी पचास हजार या दस हजार घरों का प्रबन्ध कैसे होगा। यह विचार नहीं। अगले दस सालों में और अधिक हो जावेंगे। यह समस्या तो दिन पर दिन और बढ़ती जावेगी। तो आज इस तरह से हमारे सामने यह देखना है कि जो कुछ भी घटनाएं आज हमारे देश में हो रही हैं हमारे पड़ौसी देश में पूर्व पाकिस्तान में बंगाल देश में जिसे पूर्व बंगाल कहते हैं, हो रही हैं, वे आज क्या हैं ?

जनता चाहती है आज कि वह सुखी बने। समाज में से विषमता समाप्त हो। हम इस विषमता को समाप्त करना नहीं चाहते। जो काम आज हम करते हैं, बड़ों के लिये करते हैं।

एक चीज और कहना चाहता हूं स्वयं पर ही। मैं यहां का सदस्य हूं। विधान सभा राज्य में सर्वोच्च संस्था है जो प्रदेश के लिये कानून बनाती है। आज से 1।। वर्ष पहले हमने एक ऐसा विधेयक रखवाया सरकार की ओर से जिससे हमें स्वयं को इमोल्यूमेंट्स बढे हुए मिलें। उस पर बहस हुई। 400 रुपया जो हमारा वेतन उस समय था, उसकी जगह 500 किया और 21 रुपया रोज के लिये 31 रुपया कर लिया। और भी साधन कर लिये। उस समय हम सभी पार्टियों ने, विरोध जरूर किया, लेकिन सरकार की ओर से यह कहा गया कि हमने तो यह विधेयक इसीलिये प्रस्तुत किया है कि हमने सभी पार्टियों से पूछ लिया था और पार्टी के नेता उस समय राजी थे। यद्यपि असन्तोष सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से ही प्रारम्भ हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्य यह कह रहे थे कि

(श्री आदित्येन्द्र)
आपने मंत्रिमण्डल तो बड़ा बना लिया। 110 सदस्यों में से 40 आदमियों को या यों कहिये हर तीन सदस्यों से एक को मंत्री बना दिया। इसके लिये अधिकारों की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं, गाड़ियां मकान, मोटर नौकर चाकर जितने भी मिलते हैं वे सब और दूसरी सुविधाएं और अलग। हमारे लिये कोई सुविधाएं नहीं। वह असन्तोष बहुत व्यापक हुआ। उसे ठंडा करने के लिये उस समय यह सोचा गया कि कुछ इमोल्यूमेन्ट्स ही सदस्यों का बढ़ा दिया जावे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर यह सोचा गया दूसरों से मिलकर कुछ कम किया जावे ताकि लोग गलत न समझें। तो उस समय भी थोड़ा विरोध हुआ। मुझे भी यह नहीं जंचा, बिलकुल ठीक हो, ऐसा नहीं मालूम पड़ा। मेरे मित्रों ने भी कहा। पर अन्दर ही अन्दर मन उदास सा हो रहा था कि आज हम गलती क्यों कर रहे हैं। इसका आगे जाकर अच्छा नतीजा नहीं होगा। लेकिन उस समय मेरे मन में यह भी आया कि मैं अगर आपको यह कह दूं कि मैं नहीं लेना चाहता तो मेरे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं सोचने लग जावेंगे लोग कि मैं हिपोक्रेट हूं। इसलिये चुप रहा। पर आज जब समाजवाद का नारा व्यापक रूप से हमारे सामने आया है तो मैं समझता हूं कि आज समय आ गया है कि हम इस गलती को ठीक कर लें।

श्री किशनलाल : आप छोड़ो।

श्री आदित्येन्द्र : मैं छोड़ रहा हूं आज से। एक साल पहले जो बात हुई, 31 रुपया रोज की, उसकी जगह 21 रुपया रोज और 500 रुपया की जगह 400 रुपया मासिक लूंगा। दोनों ही पुरानी चीजों को लूंगा। 31 की जगह 21 और 500 की जगह 400 रु. लूंगा। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई त्यागी हूं, या तपस्वी हूं, इसका दम्भ मैं नहीं करता। मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि स्वयं चाहता हूं कि मैं भी स्वयं अपनी रक्षा चाहता हूं देश की रक्षा करना चाहता हूं। इसलिये नहीं चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है जो कुछ बड़े आदमी हैं वे थोड़ा नीचे हों और अगर वे फायदा करना चाहते हैं गरीब के लिये तो उसके लिये कुछ करें।

श्री किशनलाल : डेढ़ साल से लिया वह भी वापिस दे रहे हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : शायद वे समझे नहीं हैं कि मैं त्यागी नहीं हूं, तपस्वी भी नहीं हूं। यह मैंने पहले ही कह दिया है। लेकिन अगर इस बात को कहेंगे तो इसके लिये भी कह दूंगा, पर आज नहीं कहूंगा। न इतना त्यागी बनना चाहता हूं। पर चाहता हूं कि आप इस बात को गम्भीरता-पूर्वक लें। जो कुछ आज हो रहा है, देश में जो हवा आ रही है, जो चेतना और क्रान्ति आ रही है, उसकी ओर देखें और वास्तविकता की ओर से आंखें मूंद कर न चलें। इस के लिये अब बहस का समय नहीं है। बहस में पड़ जावें इसकी, यह भी सवाल नहीं है। मैं भी कांग्रेस में था किसी दिन। आज भी सिद्धान्तों को उन्हीं को मानता हूं। आइडियोलोजी का अन्तर नहीं है। पर यह मानता हूं कि जो कुछ

(श्री आदित्येन्द्र)

भी आज हम कर रहे हैं और जो कुछ भी हमारे सिद्धान्त हैं उनमें तालमेल हो। आज तालमेल नहीं है।

तो मैं इतनी बात कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे अपील करता हूं और कहता हूं कि सरकार पर भी आप स्वयं जोर डालें कि जल्दी से जल्दी कोई विधेयक यहां लाया जावे कि जिससे आज से 1।। साल पहले जिस स्थिति में थे, उसमें आ जावें। और अगर कोई कार्यवाही करना चाहते तो मैं आज तो नहीं कहना चाहता इस बात के लिये मुझे सूझता भी नहीं कि क्या कर सकता हूं, इस सम्बन्ध में तो इतना ही कह सकता हूं कि जो चीज मुझे रियायत लगती थी वह छोड़ दी। लेकिन वह रियायत इसलिये नहीं छोड़ी कि मैं कोई त्यागी हूं या अपने आपको दूसरों से अधिक तपस्वी हूं।

अब में एक चीज यह कहना चाहता हूं कि अगर हमें सही माने में समाजवाद लाना हैं तो हर प्रकार के शोषण को समाप्त करना है। यह जो रीजनल इम्बेलेन्स है, क्षेत्रीय असन्तुलन है इसको भी हमें समाप्त करना होगा। सदस्यों में भी जो ज्यादा प्रभावशाली हैं वे अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करवा लेते हैं। दूसरे लोग जो कम प्रभावशाली हैं या रूलिंग पार्टी के हैं वे अपनी कान्स्टीट्युएन्सीज में कुछ करा लेते हैं। पर यह साफ है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में अगर देखा जावे तो उनमें जितने मिनिमम से मिनिमम काम भी होने चाहिये वे भी नहीं हुए। उदाहरण के लिए मैं जिस क्षेत्र से आता हूं भरतपुर या अलवर से तो उन्हीं जगहों के लिये नहीं, पूर्वी राजस्थान को भी देखें तो सन् 57 तक जो कुछ भी काम हुआ वह हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। सड़कें भी बनीं सब जगह पर तो 57 तक बनीं। इसके बाद और जगहों के लिये सिंचाई वगैरह की बड़ी बड़ी योजनायें बनीं दूसरी जगहों के लिए बनीं, बिजली के लिये रुपया मन्जूर हुआ वह दूसरी जगहों के लिये। गोवर्द्धन कैनाल के लिये बड़ी बड़ी बातें हुईं, चर्चाएं हुईं, कहा गया कि 2-3 करोड़ रुपया खर्च किया जावेगा, एक ऐसी व्यवस्था इसके द्वारा कायम की जावेगी कि फिर पूरे वर्ष भर पानी मिलता रहेगा, पर वह चर्चा चर्चा ही बन कर रह गई। कार्य रूप में परिणित नहीं हुई।

अगर भरतपुर के एरिया में थोड़ा सा पानी ज्यादा बढ़ा दिया जावे तो भरतपुर के एरिया के गांवों पर पानी आता है दूसरी नदियों से जैसे रूपारैल से तो उन नदियों का पानी कम किया जा सकता है।

उस समय जबकि वहां पर पानी उस तालाब से देंगे ही लेकिन उस काम के लिये वहां पर पानी नहीं दिया गया। इसलिये नहीं दिया गया कि वहां पर उनकी तरफ से कोई उनका प्रवक्ता, स्पोक्समैन नहीं था। आज इसलिये जरूरत इस बात की है कि यह जो क्षेत्रीय चीजें हैं, यह जो इम्बेलेन्स है उसको खतम किया जाये। दूसरा जो कोआपरेटिव सेक्टर है उसको भी इफीशियेन्ट किया जाना चाहिये। जो करप्शन फैल रहा है उसको समाप्त करना चाहिये। पब्लिक सैक्टर की जो चीजें खराब हैं उनको अच्छा बनाया जाना चाहिये। उसके अन्दर नुक्सान निरन्तर बढ़ता जा

(श्री आदित्येन्द्र)

रहा है। इसका नतीजा क्या होगा, यह होगा कि लोग समाजवाद से दूर चले जायेंगे। लोग यह समझेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें हैं उनमें तो नुक्सान ही नुक्सान होता है। जहां कहीं भी चर्चा चलती है उसके विरोध में यह बातें कही जाती हैं—उनमें नुक्सान होता है, भ्रष्टाचार होता है और निहित स्वार्थ के लोगों को फायदा पहुँचाया जाता है। पहले सेठ लोग इसका फायदा उठाते थे और आज सरकारी कर्मचारी इससे फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम बातें सभापति महोदय, मैंने यहां पर कही हैं और अब इन बातों को समाप्त करना चाहता हूं। यहां पर जो कुछ भी मैंने कहा है उससे कोई यह न समझें कि मैंने कोई चीज बढ़ा कर के कही है। आज तो मैंने वही बात कही है जैसा मैं अन्दर से महसूस कर रहा हूं, जैसी मेरी आत्मा कहती है। इस तरह की बहुत-सी बातों को देखता हूं तो दुःख पाता हूं। मगर आपको यह मौका और मिला है और पूरी तौर से आज यह मान लिया है कि जनता ने आपका विश्वास किया है। जो भी हो विधान सभा में या जो मंत्रिमण्डल है राज्य का या केन्द्र का मंत्रिमण्डल है, आज उनके लिये कोई बहाना नहीं है कि कोई उनके कार्य में आज बाधा डाल रहा है। आज उनके लिए पूर्ण बहुमत है, दो तिहाई बहुमत उनको मिल गया है और उसके बाद भी नहीं कर सकते हों तो मैं यह मानता हूं कि यह लोकतन्त्र के लिये अन्तिम अवसर है। अगर लोकतन्त्र में अब भी कुछ नहीं कर सके और इन तमाम बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और खाली हम यहां पर वाद-विवाद में ही लगे रहे तो यह निश्चित है कि एक दिन वह आयेगा कि हम पछतायेंगे और वह समय ऐसा होगा कि हमारे पछताने से भी कोई लाभ नहीं होगा। वह अग्नि होगी उसमें अपने को भी स्वाहा करेंगे और देश को भी स्वाहा करेंगे।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, विरोधियों को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री व्यास।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के तीन सदस्य बोल चुके हैं और हममें से किसी को भी अवसर नहीं मिला है।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास (टोंक) : सभापति महोदय,

श्री डूंगाराम राजोरिया : विरोधी पक्ष को भी मौका मिलना चाहिये। कांग्रेस के तीन सदस्य बोल चुके हैं। हमें भी अवसर मिलेगा या नहीं यह बता दीजियेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आगे नहीं। आपके दल ने समय ले लिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारे दल की ओर से आज कोई नहीं बोला है।

श्री जुझारसिंह : किस किस को बोलना है यह बता दीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : समय मिलेगा या नहीं यह स्पष्ट कर दीजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : मैं प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें समय दिया जायेगा या नहीं, ये दो बातें हैं। स्वतंत्र पार्टी की ओर से आज एक भी सदस्य नहीं बोला है। आसन की तरफ से इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि समय मिलेगा या नहीं। ये दो बातें हैं।

श्री सभापति : समय के बारे में नहीं कह सकता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमें तो कह दीजिये कि समय मिलेगा।

श्री सभापति : समय रहा तो आपको भी मिलेगा। माननीय सदस्य ज्यादा समय ले लेते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : समय का निर्धारण कर दीजिये और प्रत्येक को बोलने का अवसर मिलना चाहिये। कांग्रेस के दो सदस्य बोल लिये हैं और तीसरा नम्बर हमको मिलना चाहिये। आज हमारे में से कोई भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप जल्दी समाप्त करेंगे माननीय सदस्य! समय का ध्यान रखें। आर्डर प्लीज। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : सभापति महोदय, गत 15 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के धन्यवाद का प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों के अन्दर जनता का जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ है, उसके बाद में सभी लोग यह आशा लेकर के चल रहे थे कि समाजवाद के लिए राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कुछ दिशाएं बताई जायेंगी और कोई नीति समाजवाद की सामने आयेगी लेकिन अभिभाषण के पश्चात् और उस के बाद में उस पर जो चर्चा इस सदन के अन्दर हुई इधर के माननीय सदस्यों और उधर के माननीय सदस्यों के द्वारा उसको सुन कर मुझे भारी निराशा हुई है। चुनावों में हारने के कारणों को यहां पर बताया गया। यह कहा गया कि लोगों को आतंकित कर, सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस ने वोट बटोरे हैं परन्तु किसी से भी यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है कि समाजवाद के नारे ने जादू का सा असर सारी जनता के दिल और दिमाग पर किया है। गरीबी को मिटाना और बेरोजगारी को खत्म करना ये दो मुख्य बातें कांग्रेस के घोषणा-पत्र में थीं उसका भी काफी हद तक असर हुआ है और सफलता मिली है। इन सब से ऊपर और जबर्दस्त फैक्टर हैं वह युवाजनों का, नवयुवकों का। नवयुवकों का यह दृष्टिकोण ही इस सफलता के लिये जिम्मेदार है। उनके दृष्टिकोण में निरन्तर परिवर्तन आया है। पहले हम देखते थे कि नवयुवक या तो अब तक राजनीति से दूर रहते आये हैं और या जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, वह कांग्रेस के विरोध में रहते थे इस दृष्टिकोण के कारण वे कांग्रेस से दूर होते चले जा रहे थे। अब की बार उनके दृष्टिकोण में

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)

भारी अन्तर आया है, उसका कारण है गरीबी को मिटाना और बेरोजगारी को मिटाना, समाप्त करना। यह जो नारा कांग्रेस ने दिया था उसकी वजह से नवयुवक कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए हैं। इस नारे ने उनको कांग्रेस की तरफ आकृष्ट किया है। और उनके इसी सुदृढ़ समर्थन के कारण यह सम्भावना हो सकी है और कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई है इन चुनावों के अन्दर। कांग्रेस को इन चुनावों में भारी सफलता जो मिली है वह नवयुवकों और विद्यार्थियों के समर्थन के कारण ही मिली है। परन्तु राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर नवयुवकों में व्याप्त असन्तोष के प्रति कोई दिशा या आश्वासन भविष्य के लिये कार्यक्रम नवयुवकों के लिये, कोई योजना आदि ऐसा कुछ भी इस भाषण में नहीं है। इसी प्रकार विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा यहां पर जो चर्चा उठाई गई है उसके अन्दर भी इस बात को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसलिये एक बात समझ लेनी चाहिये कि किसी भी देश में कोई परिवर्तन होता है, चाहे वह शांतिपूर्ण तरीके से हो, या अन्य तरीके से हो, उसकी महान जिम्मेदारी नवयुवकों की होती है। नवयुवक ही ऐसी क्रांति के अगुआ होते हैं। परन्तु आज जो नवयुवकों के अन्दर असन्तोष है, उनके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण एक तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के विषय में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर इस बात का संकेत किया है, इसका रेफेरेन्स दिया है लेकिन विस्तारपूर्वक कोई योजना हमारे सामने नहीं रखी है। माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में अपने अपने सुझाव रखे हैं। लेकिन मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि यहा पर भाषण में कहा गया है दस-बीस हजार या एक लाख लोगों को युवकों को रोजगार दे देने से यह समस्या हल नहीं हो जायेगी। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि एक हजार आदमियों को एक एक जिले के अन्दर रोजगार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। एक हजार आदमियों को रोजगार दे दें, दो हजार को दे दें या बीस हजार को दे दें, उससे ही कोई इस समस्या का हल होता नहीं दिखता है। उन बेरोजगारों का क्या किया जायेगा जो हमारी शिक्षा पद्धति के द्वारा हर वर्ष तैयार होते जा रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि हमारी इस शिक्षा पद्धति के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि बेरोजगारी को मिटा सकें। हमारी वर्तमान शिक्षा ही बेरोजगारी से सम्बद्ध है। जब मैं यह देखता हूं कि हमारे माननीय सदस्य अपने भाषण के दौरान यह कहते हैं हमारा यहां पर स्कूल नहीं खोला जा रहा है, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर जो मेडिकल कालेज है उसमें असुविधा है। यह मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविद्यालय जो बेरोजगारी को प्रोड्यूस करने के कल-कारखाने हैं, बेरोजगारी बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, उनके लिये कहते हैं कि हमारे यहां खोल दीजिये। सब तरफ से मांग आ रही है हमारे यहां विश्वविद्यालय बना दीजिये विश्वविद्यालय बना देने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। शिक्षा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, शिक्षा की पद्धति को बदला नहीं जायगा आमूलचूल परिवर्तन कहीं किया जायगा अ

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)

शिक्षा की पद्धति से ऐसे लोग नहीं बनायेंगे तो सेल्फ सफिशियेन्ट एस्टेब्लिश हो सके तब तक बेरोजगारी की समस्या दूर होने वाली नहीं है। आज की शिक्षा पद्धति नौकर तैयार करती है। जितनी शिक्षण संस्थायें हैं वे सब नौकर तैयार करती हैं। सभापति महोदय, बहुत दुःख का विषय है गांव के अन्दर एक किसान के यहां 200 बीघा जमीन है और उसका लड़का जाकर एग्रीकल्चर कालेज में दाखिल होता है और जब वहां से पढ़कर निकलता है तो ए. इ. ओ. बनना पसन्द करता है, तहसीलदार बनना पसन्द करता है और दूसरी नौकरी करना पसन्द कर लेता है किन्तु वह अपनी जमीन को जाकर आधुनिक तरीके से खेती के उत्पादन को बढ़ाना पसन्द नहीं करता है और भी जितनी टेक्निकल संस्थायें हैं चाहे इंजीनियरिंग की हो और चाहे किसी की हो वह करने के बाद नौकरी ढूंढना चाहता है और अगर उनमें से कुछ करना भी चाहते हैं तो सरकार की सुविधायें नहीं हैं। आज शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कुछ अर्से पहले माता-पिता अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना पसन्द करते थे और उसको मैथेमेटिक दिलाते थे किन्तु आज इंजीनियरों की भी यह हालत है कि बेरोजगार हो गये हैं और मैं उन माता पिताओं को एक चेतावनी देता हूं जो अपने बच्चों को डाक्टर बनाना पसन्द करते हैं। डाक्टरों की भी आने वाले समय में ऐसी ही दुर्दशा होने वाली है, वे भी बेरोजगार होने वाले हैं। पहले केवल एक राजस्थान विश्वविद्यालय था उसके बाद उदयपुर में एक विश्वविद्यालय खोल दिया और फिर एक विश्वविद्यालय जोधपुर में भी खोल दिया। जो एक विश्वविद्यालय था वह ठीक था उसी के स्तर को ऊंचा करते लेकिन विश्वविद्यालय खोलने की तो होड़ लगी हुई है पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार मेडिकल कालेज चार चार खोल दिये हैं लेकिन उन कालेजों में इक्विपमेंटस नहीं है। ऐसे मेडिकल कालेज खोलने से क्या फायदा? उनका कोई विकास नहीं होता है।

यही हालत देहातों की है, देहातों में कोई विकास नहीं होता। मेट्रीक्यूलेट्स दिनों दिन निकलते जा रहे हैं उससे कोई विकास हमारे देश का होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, जब एक आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो वह शिक्षक बनता है। पहले तो वह सोचता है मैं आइ. ए. एस. बन जाऊं, आर. ए. एस. बन जाऊं, तहसीलदार बन जाऊं लेकिन जब दुनियां में कोई जगह नहीं मिलती है तो सोचता है, चलूं मास्टर बन जाऊं। एस. टी. सी. ट्रेन्ड मास्टर होता है। विशेष इसकी ट्रेनिंग होती नहीं। शहरों के अन्दर बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ाने के लिए मोन्टेसरी स्कूल हैं वहां मोन्टेसरी अध्यापक उनको पढ़ाते हैं बाकी देहातों में नहीं है। इन सब बातों को सोच समझकर शिक्षा में परिवर्तन किया जाय। टेक्निकल शिक्षा सबको दिलाई जाय और उनको इस प्रकार बनाया जाय कि डिग्री हांसिल करके समाज के अन्दर कुछ योगदान कर सकें। आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय है या दूसरे विद्यालय हैं उनके अन्दर किस प्रकार की शिक्षा हो रही है उसे आप सब लोग जानते हैं। फर्स्ट ईयर, टी. डी. सी. से लेकर एम. ए. तक पढ़ाते हैं और वे पास होते रहते हैं। राज्य सरकार

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)
विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बारे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। इन सब बातों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है।

आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर, सभापति महोदय, नक्सली नारे लगाये जा रहे हैं, नक्सली पोस्टर विश्वविद्यालय प्रिमिसेस में लगे हुये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की जानकारी में है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम, किसी को जानकारी में है या नहीं। मै वहां गया हू इसलिये मुझे मालूम है और यह वास्तविक तथ्य है। अब उन पोस्टरों को हटा दिया गया है लेकिन राजस्थान सरकार की जानकारी में यह बात आई या नहीं यह तो सरकार ही जाने। इसके लिये मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता हू ....

श्री बालसिंह सोढ़ा : दामोदर जी से पूछो।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : यह प्रवृत्ति अगर राजस्थान में पनपी तो ...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उनमें से एक पोस्टर अपने पिताजी के घर पर लगा देते, तो मालूम हो जाता।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : यहां भी खतरा पैदा हो सकता है। आज राजस्थान के नवयुवकों ने, राजस्थान के गरीब समाज ने समाजवाद को मान लिया है और यह जो कांग्रेस को सफलता मिली है वह नवयुवकों की वजह से मिली है। नवयुवक चाहते हैं कि देश में समाजवाद आयें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपको लीडर मानने के लिये ...

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : चुप रहेंगे या क्या आप बीच बीच में ...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जवान हैं।

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : दिल से जवान है, निपट लेंगे आप बीच में डिस्टर्ब न करें। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आज जब नवयुवकों ने इस बात को समझ लिया है और मूल रूप से स्वीकार कर लिया है कि देश के अन्दर समाजवाद लाना है और देश के अन्दर गरीबी और अमीरी के फर्क को मिटाना है, बेरोजगारी को दूर करना है तो उन्होंने एक रास्ता अपना लिया है। नवयुवक यह भी चाहते हैं कि शान्तिपूर्वक और कानून से आ जाय तो अच्छा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हू जिन नवयुवकों का कांग्रेस को जिताने में हाथ है वे समाजवाद को भी लायेंगे। समाज के बहुत बड़े अन्तर को खत्म करना होगा और अगर आप नहीं करेंगे तो वे अपने आप करेंगे–नक्सली तरीकों से करेंगे। किन्तु, सभापति महोदय, यह कोई अच्छा रास्ता नहीं है। इसको लॉ एण्ड आर्डर कह कर टालना नहीं होगा। जब तक हम सोशियो-इकॉनोमिक तरीके से सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)

आज मध्यावधि चुनावों के अन्दर बहुत लम्बे चौड़े भाषण और आरोप लगाये जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आतंक फैलाया गया। झुंझुनूं और नागौर में बड़ा आतंक फैलाया और भी सब जगह की बातें कही गईं। सभापति महोदय, आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि यह शुरुआत किसने की। झुंझुनूं जिले से शिकायत आई है, नागौर जिले से शिकायत आई है। यह शिकायत का मसला जयपुर शहर क्या कम रहा। विरोधियों ने हमारे जुलूस पर पत्थर फेंके। हमारे पी. के. चौधरी साहब को जुलूस में पत्थर लगा। जयपुर की करीब करीब सभी सभाओं में हमें डिस्टर्ब किया गया लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। हम अनुशासन में रहे। स्वतन्त्र पार्टी वालों ने और जनसंघ वालों ने हमें कई बार डिस्टर्ब किया है। आखिर यह सब किसने सिखाया पहले आतंक तो विरोधियों ने ही फैलाया है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सब इन्हीं से सीखा है। यह कार्यवाही जारी रही तो कांग्रेस को हमारा समर्थन मिलेगा और विरोधियों को नहीं बोलने दिया जायगा, यह स्पष्ट बात है। राजस्थान के अन्दर चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुये चूंकि राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां की जनता अपने राइट्स को अच्छी तरह समझती है और जहां जनता अपने राइट्स के लिये चिल्लायेगी वहां शान्ति रहेगी। इसके पश्चात् . . .

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : प्रोग्रेसिव स्टेप आप क्या सजेस्ट करते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : राज्यपाल महोदय पर जो इतना खर्च होता है क्या इस खर्च का होना आप उचित समझते हैं ?

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : सभापति महोदय, जितना आप बोल चुके हैं उसको मैं नहीं बोलूंगा। मुझे तो अब कोई नई बात निकाल कर लानी पड़ेगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो आप कह चुके हैं उसे दोहराऊंगा नहीं। राज्य सरकार समाजवाद लाना चाहती है और शान्तिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना चाहती है। समाजवाद के लिये कानून बनाना चाहती है वक्तन फवक्तन राज्य सरकार से इस प्रकार के कानून भी बनाये हैं, जैसे सीलिंग का कानून बनाया है। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं राज्य में जो आई.ए.एस. और आई. पी. एस. आफिसर्स हैं वे ही सारे राज्य के काम को एग्जीक्यूट करते हैं, मिनिस्टर्स तो केवल पॉलिसी बनाते हैं। उनका एग्जीक्यूशन करना उन अफसरों का ही काम है वे ही एक्ट बनाते हैं, बिल वह बनाते हैं और वही पेश करते हैं और वही एग्जीक्यूट करते हैं। सीलिंग लॉ जब बना, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय राज्य सरकार ने मोलत दे दी। उसके पश्चात् क्या हुआ, गांवों में देखने को मिलता है कि साधारण जमींदार जिसके घर में दस-बारह आदमी हैं उनको सीलिंग के नोटिस दिये जाते हैं जिनके खाते नहीं बंट सके और बड़े बड़े जागीरदारों ने और सबने जमीन बांट दी।

एक माननीय सदस्य : नये जागीरदारों ने ?

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : नये और पुराने जागीरदार दोनों ने बांट दी। इस

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)
ब्यूरोक्रेसी के सहारे आप कोई समाजवाद का कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते। सभापति महोदय, आज आई. ए. एस. आफिसर्स की यह हालत है कि वह किसी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर से सीधे मुंह बात नहीं करते। जनता का आदमी उनके पास जा नहीं सकता। ऐसी हालत में क्या समाजवाद उनके जरिये आ जायेगा, मुझे बहुत सन्देह है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और एग्जीक्यूट करती है मशीनरी। जब तक मशीनरी को ठीक नहीं किया जायेगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता।

इसके पश्चात्, सभापति महोदय, निवेदन यह है कि पहले राजा महाराजाओं के जमाने में . . .

श्री मदनसिंह : प्रेसीडेन्शियल गवर्नमेन्ट हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : वह सुझाव आप दे देना।

पहले राजा महाराजाओं के जमाने में एक प्रोटेक्टेड क्लास हुआ करती थी ब्राह्मण और ब्राह्मण यदि कोई जुर्म करता था तो उसका कोई काग्नीजेन्स नहीं लिया जाता था। आज उसी तरह से प्रोटेक्टेड क्लास है आई. ए. एस.। यह आई. ए. एस. आजकल के ब्राह्मण हैं। मंत्रिमण्डल के सदस्यों को सारा कुछ हाउस में पेश करना पड़ता है और विपक्षी सदस्यों के सही और झूठे आरोप लगते हैं और उसका सामना करना पड़ता है मंत्रियों को। ये आई. ए. एस. के आदमी प्राटेक्टेड हैं, वह कुछ भी करें उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है 'They are beyond reach'। यहां पर हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार हो सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार एक ह्यूमन नेचर है और यह भ्रष्टाचार एक लिमिट का सवाल है। इसकी लिमिट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर करप्शन का कोई जिक्र ही नहीं है। समाजवाद की बात ने भ्रष्टाचार की बात को दबा दिया। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि समाजवाद नहीं आ सकता जब तक कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो। आज एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को चलाना होता है तो, सभापति महोदय आप हैरत में पड़ जायेंगे कि पटवारी का चालान नहीं होता, कभी सिपाही का चालान नहीं होता, कभी एस. पी. का चालान नहीं होता। आपने कभी देखा है चालान होते ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक दो एस. पी. का तो चालान करवा दो।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : मैं तो कह रहा हूं, आप भी तो हां में हां मिलाओ।

सभापति महोदय, यहां तो यह है कि व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं। . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो उदयपुर डिविजन का कायदा है।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : तो, सभापति महोदय, इसी प्रकार से हरिजनों की बहुत बड़ी समस्या है। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हरिजनों को हम ऊपर नहीं उठा सके हैं। मैं यह बिलकुल मानता हूं कि शताब्दियों से हरिजनों का शोषण हुआ

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)
है और ब्राह्मण और राजपूतों ने मिल कर किया है। लेकिन आज शोषण कौन कर रहा है। आज तक हमने किसी भंगी को एम. एल. ए. बनते नहीं देखा। यह बड़े बड़े लोग भी वहां जाकर चाय नहीं पीयेंगे। हम तो फिर भी जाकर पीलें। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन पर है।···

श्री मदनसिंह : हमारे तो बटलर ही भंगी थे।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : जो लोग हरिजनों से आते हैं और यदि उनको कोई मंत्री पद या कोई पद मिल जाता है तो वह भी ब्राह्मणों से ज्यादा मिक्स-अप होने की कोशिश करते हैं और अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। यह सही है कि गांधी शताब्दी के वर्ष में हरिजनों को जमीन का अलॉटमेन्ट का सवाल आया, तो इसको किस प्रकार से टाला गया और इनको किसी को भी अच्छी जमीन का अलॉटमेन्ट नहीं हुआ और हुआ भी तो रद्दी जमीन का और अच्छी जमीन का तो पजेशन ही नहीं दिया गया। इस स्थिति के अन्दर, सभापति महोदय, मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 23 वर्ष क्या 2300 वर्ष भी ऐसे ही होता रहा तो समाज का नीचे गिरा हुआ तबका ऊपर उठकर आने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, बीच में एक बात और निवेदन कर दूं कि इधर वाले जो माननीय सदस्य हैं वह गलत बात करते हैं, गलत आरोप लगाते हैं और इधर वालों को मजबूर कर देते हैं। सरकार यदि कोई वाजिब बात करती है और सरकार यदि कोई वाजिब काम करे, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि सरकार चाहे अच्छा काम करे या बुरा उसकी हमेशा आलोचना ही की जाती है। यह विरोधी पक्ष की बहुत ही गलत बात है।

इसी तरह से सहकारी समितियों की काफी चर्चा की गयी। सहकारी समितियों को अच्छी स्प्रिट से चालू किया गया और यदि वे सफलतापूर्वक काम करें तो समाज की काफी सेवा कर सकती हैं लेकिन, सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर कोई भी सदस्य डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली किसी भी सहकारी समिति से सम्बन्धित हो या उसकी जानकारी रखता हो, तो वह जानता है कि सहकारी समितियों में क्या होता है। जो उनमें कमजोरी है उसको हमें नहीं छिपाना चाहिए और मैं समझता हूं कि कितना ही अच्छा कानून हो अगर वह फेल हो जाये तो हमें कमजोरी माननी चाहिए और उस संस्था को खत्म कर देना चाहिए। संस्थाओं को कागजों में घसीटने से कोई फायदा नहीं है।

इसी प्रकार से चिकित्सा का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर विचार किया गया और चर्चा भी की गयी है लेकिन चिकित्सा भी आज आम आदमी को उपलब्ध नहीं होती है, यह बिल्कुल सही बात है। एस. एम. एस. हास्पिटल के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। कायदा यह है कि जूनियर स्पेशेलिस्ट यदि किसी मरीज की बीमारी को घातक समझता है तो फिर सीनियर स्पेशेलिस्ट को रेफर कर देता है और सीनियर स्पेशेलिस्ट के वहां पर दिन मुकर्रर होते हैं कि वह फलां फलां दिन आउटडोर में बैठे

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)

सभापति महोदय, आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रोफेसर्स में से एक दो आते हों तो बात दूसरी है लेकिन अक्सर कोई भी आउटडोर में नहीं आते। प्रोफेसर्स सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जो या तो फीस देता है या फिर जो टेलिफोन कराते हैं। और ब्यूरोक्रेसी एक तरह से सवाई मानसिंह हास्पीटल में आगई है और वहां तो सबसे बद्तर हालत है। जनाना हास्पीटल की तो और भी बुरी स्थिति है। जनाना हास्पीटल के बारे में तो यह समझ लेना चाहिए कि वहां पर बीमारी का इलाज होना दूभर है बल्कि वहां मरीज को भर्ती कराने से और भी केस काम्प्लीकेटेड हो जाता है।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, आर्मी पर्सोनल इसमें के एलाटमेंट की इसमें चर्चा की गई है। इस विषय में, सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि आर्मी पर्सोनल में सभी होंगे तो आर्मी के सिपाही रिक्रूट और हवलदार को पहले एलाटमेंट नहीं होगा, और अगर आंकड़े देखे जायं और तथ्य सामने लाये जायं तो जिस अनुपात में आफिसर्स नियुक्त होते हैं आर्मी में उस हिसाब से आफिसर्स को जो ज्यादा जमीन मिली है उनके ताल्लुकात के कारण और सिपाही को जमीन नहीं मिली है। अगर उसको जमीन मिलती है तो कब्जा नहीं मिलता है और कब्जा मिलता है तो मुकद्में बाजी करनी पड़ती है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक बात में और निवेदन करना चाहूंगा कि अदालतों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि मुंशिफ मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों के उपस्थिति के अन्दर रीडर खुले आम रिश्वत लेता है, और बिना नियत राशि को लिये दावा नहीं लेता है, दरख्वास्त नहीं लेता है। गम्भीर मसला तो सेशन्स केसेज का है। पिछले कुछ अरसे में सेशन्स केसेज को एक्सपेडाइट करने का एक तरीका निकाला गया है, और आज भी मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की गिनती उन दो-तीन प्रान्तों के अन्दर ऐसी है कि जहां एक सेशन्स केस को निपटाने के लिये साल भर से ज्यादा टाइम लगता है। साल भर की अवधि इतनी बड़ी होती है कि मुल्जिम तो क्या मुल्जिम से सहानुभूति रखने वालों को भी पर्याप्त टाइम मिल जाता है कि वे प्रोसीक्यूशन की विटनेसेज को टेम्पर विथ कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि कई दफा मुल्जिम कानून की गिरफ्त से बाहर निकल जाता है।

इसी प्रकार जमीनों के विषय में मै निवेदन करना चाहता हूं। मै यह नहीं मानकर चलता हूं कि राजस्व मण्डल के अन्दर या राजस्व अपीलेट अधिकारियों के यहां सब फैसले कानून से सही होते हैं फिर भी एक जुडिशियल बोडी है रेवेन्यू लाज के लिए। एनोमोलस पोजीशन यह है कि रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी के पास जिस मुकद्में में कमजोरी नजर आती है और आपकी सचिवालय तक पहुंच हो गई है तो सेटिलमेंट के अन्दर तो सीधा कर दिया है। एलाटमेंट के मसलों को लेकर खास तौर से कि सेक्रेटेरियेट में नान-जुडिशियल मैटर्स तो जायेंगे हीं लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जो कि रेवेन्यू बोर्ड में भी जा सकते हैं और सेक्रेटेरियेट में भी जा सकते हैं। इसका भी डिविजन करना बहुत जरूरी है।

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)

सभापति महोदय, विना किसी चार्ज के लगाये मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि व्यक्तिशः मेरे से सम्बन्ध रखता हो तो, राजस्व अपील अधिकारी का जो पद है वह बड़ा महत्वपूर्ण पद है। राजस्व अपील अधिकारी कई कलेक्टर्स की अपीलें सुनता है। जयपुर में जो आज राजस्व अपील अधिकारी लगे हुए हैं उनके लिए मैं नहीं कहता और जो पहले लगे हुए थे उनके लिए मैं नहीं कहता। एक जनरल बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिटायरमेंट में साल, डेढ़ साल रह जाता है उस अधिकारी को राजस्व अधिकारी लाकर बैठा देते हैं। मैं नहीं कहता कि किस उम्र तक राजस्थान में बैठते हैं, लेकिन उसका परिणाम यह होता है कि लेन देन के मामले बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी रिटायरमेंट एज है। उनको वापस तो नहीं आना है। दूसरी एनोमोलस पोजीशन यह होती है कि कलेक्टर्स आई. ए. एस. होते हैं और राजस्व अपील अधिकारी सीनियर आर. ए. एस. स्केल के होते हैं तो कलेक्टर्स के अण्डर आटोमेटिकली उनके प्रति वह सेक्टिरी और रेस्पेक्ट नहीं होती है क्योंकि राजस्व अपील अधिकारी सीनियर आर. ए. एस. स्केल का होता है और वह स्टे ऑर्डर कर देता है तो उसकी अनुपालना नहीं की जाती है।

इसके अलावा, मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि समय को लेकर समाजवाद की हम बात करते हैं तो कुछ हमको करना चाहिए और हमको खुद करना चाहिए और राज्य सरकार से अनुरोध करें, और अगर करेंगे तो किसी पर अहसान नहीं करेंगे। विरोधी दल के लोग समझते हैं कि नहीं करें तो अच्छा है ताकि जनता हमारे खिलाफ हो, लेकिन जो वायदे हमने किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि आम जनता विशेष तौर से नवयुवकों की आशाएं बहुत ऊंची उठ चुकी हैं। सभापति महोदय, गांवों के अन्दर कई जगह समाजवाद की भाषा के जाने बिना ही लोगों के दिमाग में जो आम बात घर कर गई है कि वह यह है कि इन्दिरा जी गरीबों के लिए कुछ करने वाली है और यह सही बात है कि गरीबों के लिए इन्दिरा जी करने वाली हैं और करना चाहती हैं। इन्दिरा जी के हाथ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट है और यकीनन कुछ न कुछ करेंगी लेकिन स्थानीय समस्याओं के बारे में और आम आदमी को उठाने कि बात हैं उसमें जितनी राज्य सरकार की मदद दे सकती हैं जितना राज्य सरकार काम कर सकती है, जितना राज्य सरकार योगदान दे सकती है, उतना केन्द्रीय सरकार नहीं दे सकती है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही कांग्रेस पार्टी की हो वहां तो विशेष कठिनाई नहीं हो सकती है। राज्य सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ करे। अगर नहीं करेगी तो बातें झूठी हो जायंगी झूठी होने के बाद विरोधी दल में राइट पक्ष को सत्ता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि रास्ता चुन लिया है जनता ने। देश के नवयुवकों ने फैसला कर लिया हैं हमारा वाम पक्षी रास्ता है, हमें लेफ्ट की तरफ से जाना है। अगर शान्ति से समाजवाद को लाकर बैठाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिस बह नहीं करते हैं तो कम्यूनिस्ट का रास्ता साफ है। उस रास्ते पर चलिये। तो उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए, देश में लोक-

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)
तन्त्र को बनाये रखने के लिए और अपने आपको जनता में पापुलर रखने के लिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करता हू तो कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ हमको करना चाहिए और करना शुरू कर देना चाहिए और आदर्श उपस्थित कर देना चाहिए। मैं राज्यपाल महोदय के पद को समाप्त करने की बात नहीं कहता, लेकिन जो खर्चा आज के जमाने में हमारे राज्य को उन पर करना पड़ता है तो लोकतन्त्र के हिसाब से और समाजवाद के हिसाब के अनुसार नहीं है। इतना सारा खर्चा साल भर के अन्दर एक राज्यपाल के ऊपर करना पड़ता है जो कि सिवाय दस्तखत करने के और कुछ नहीं कर सकता है। वह काम तो चीफ जस्टिस भी कर सकता है। राज्यपाल महोदय जाते हैं तो वे ही करते हैं।

इसी प्रकार मन्त्री मण्डल का आकार काफी बड़ा है यह सही बात है और काम के हिसाब से भी ज्यादा बड़ा है तो सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों पर ध्यान रखकर कुछ न कुछ करें।

अन्त में जो कुछ भी कांग्रेस की नीति है उसको लेकर और भविष्य के कार्यक्रम को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक अभिभाषण देकर बताया तो उसके लिए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता। कृपा करके समय का खयाल रखें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस की शुरूआत समाजवाद की बातों से हुई। मैं पूछना चाहता हूं आज तक समाजवाद किसने नहीं लाना चाहा। आज तक समाजवाद नहीं लाने की किसकी जिम्मेदारी है? आज तक गरीब और अमीर का फर्क क्यों नहीं मिटा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार राजा और विरोधी दल वाले नहीं हैं, इसके लिये जिम्मेदार वे हैं जिन्होंने 23 साल तक राज्य किया है। जिस संविधान के बनाने में डाक्टर अम्बेडकर जैसे आदमी मौजूद थे, उस संविधान के होते हुए आज किसी जगह पर गरीब के लिये स्थान नहीं है, इसके लिये जिम्मेदार कौन है? आज इन्दिराजी समाजवाद का नारा देकर जीत कर गई, और वह इसलिये जीत कर गई क्योंकि जनता गरीब थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर गरीब पढे लिखे होते तो वे इन्दिराजी का विरोध करते और उनसे पूछते कि यह गलती किसकी है। 19 साल में अगर गरीबी नहीं मिटी, तो यह गलती किसकी है? यह गलती उनकी है जिन्होंने 23 साल तक राज किया है।

सभापति महोदय, शहरों के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा वोट किया है और देहात के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। शहरों के लोग समझते हैं कि इन्दिराजी के खाली नारे हैं···

श्री जयकृष्ण शर्मा : दिल्ली क्या देहात है?

श्री मदन सिंह : दिल्ली में भी गांव के लोग रहते हैं। उदयपुर शहर था, बीकानेर शहर था, जोधपुर शहर था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बाम्बे भी है, दिल्ली भी है।

श्री मदन सिंह : वहां गुंडे ज्यादा होंगे। गुंडाइज्म से वोट ले लिये होंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तो आपका माप दंड हैं।

श्री मदन सिंह : यहां पथराव करके, विरोधी पक्ष वालों की मोटरें रोक करके, गुंडाइज्म करके वोट लिये गये। कलकत्ता में अच्छे से अच्छे फार्वर्ड ब्लाक के नेताओं को मारा गया। यह तो पत्रकारों से सुनते हैं। मैं तो न बोम्बे गया, न कलकत्ता गया और न ही और कहीं गया। जैसे इन्दिरा गांधी ने चैलेंज दिया था कि इस मसले को लेकर···

श्री जयकृष्ण शर्मा : महाराजा भरतपुर जीत गये क्या ?

श्री मदन सिंह : महाराजा भरतपुर तो दल बदलू हैं। मैं तो तब मानता जब जयपुर से राजमाता को हराते, जोधपुर राजमाता को हराते, बीकानेर के महाराजा को हराते, और उदयपुर, जहां से चीफ मिनिस्टर पधारते हैं, वहां पर तीनों की तीनों सीटें हार गये आप। आपके कारनामों से वोट मिला है। लोगों के पास समय नहीं मिला। चार महीने पहले कहा था कि चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जब राज्य सभा में हार गई, सुप्रीम कोर्ट में हार गई, तो चुनाव करा दिया। जनता ने उनको वोट दिया है। इन्दिरा जी ने यह तभी किया है जब कि प्रिवीपर्स के मामले में वह राज्य सभा में हार गई, सुप्रीम कोर्ट में हार गई। तो जनता का आवाहन किया। जनता क्या चाहती है ? जैसा कि अमेरिका में किया। जनता क्या चाहती है ? जनता उस आवाज में फंस गई है। राजस्थान में आपकी जीत हुई है। जहां दो, चार, पांच ईमानदार हैं, अपना सा मुंह लेकर आ गये हैं। आज गरीबों के लिए राज्यपाल के भाषण में क्या हुआ है ? जैसे बच्चे का किस्सा करने के लिए आने वाले होते हैं, उसी तरह से आप को भाषण दे दिया जाएगा। आप कौन सा समाजवाद लायेंगे ? रूसी समाजवाद लायेंगे ? समाजवाद कोई लायेगा नहीं। क्या रोटी, कपड़ा, पानी सब सस्ता हो जायेगा ? सब एक भाव हो जाएगा ? रुपये की इज्जत बढ़ेगी ? काश्तकार के पास पैसा आने लगेगा। जब भाव सस्ते होने लगेंगे तो पैसे की इज्जत होगी। तभी समाजवाद आएगा। आज पैसे की इज्जत घटी है। आज फैक्टरियों की बनी हुई चीज वही खरीद सकता है जो पैसे वाला है, रईस है। आज माचिस की पेटी 3 पैसे में बनती है। लेकिन उसके लिए बाजार में 8 पैसा देना पड़ता है। जयपुर महाराजा एक चीज खरीदते हैं तो उनको भी उतने ही देने होंगे। एक गरीब आदमी खरीदता है तो उसको भी उतना ही देना होता है। एक रिक्शे वाला खरीदे तो उसको भी उतने में ही मिलेगा। एक रिक्शे वाला एक अच्छे होटल में रोटी नहीं खा सकता है। होममिनिस्टर साहब का लड़का खा सकता है। आज वहां जाता है तो दो पैसे की

(श्री मदनसिंह)

जलेबी भी उसको नहीं मिलती है। पहले समाजवाद खुद तो लायें।

सभापति महोदय, बहुत धमकियां चुनाव के अन्दर हुई। आज मुझे दुख हुआ है कि राज्यपाल महोदय कहते हैं कि चुनाव शक्तिपूर्ण हुए। मोदी जी ने पोस्टर छापे वोट नहीं दोगे तो खून खच्चर होगा। सीसराम जी को भार दिया गया है। कौन कहता है कि झुंझुनू में वोटरों को दबाया नहीं गया है। समाजवाद की आज तक किसी ने व्याख्या नहीं की है। इन्दिरा जी ने कम्युनिस्टों से बात की तो कम्युनिस्ट हार गये हैं. तो वह उनसे बात नहीं करते हैं। राजा महाराजा और जागीरदार भी बैठे हैं। वह समाज में खड़े नहीं हो सकते हैं। काश्मीर का राजा हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा गद्दार राजा है। जिस समय काश्मीर पर हमला हुआ उस समय वह हिन्दुस्तान में शामिल हुआ। केवल काश्मीर के राजा के कारण प्राब्लम पैदा हुई है। अगर केण्डीडेट्स की लिस्ट देखी जाये तो पता चलेगा कि आप के यहां राजा महाराजा ज्यादा हैं। सभापति महोदय, मैं अब इन चीजों पर न कह कर राजस्थान के और विधायकों ने जो बातें कहीं हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। आज जैसलमेर के अन्दर जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको वह दूर नहीं कर सके हैं। आज जितनी समस्याएं हैं जैसलमेर से दूर नहीं हुई हैं। जयपुर में जहां 5 हजार लगे हैं, वहां 10 हजार लगाने को सरकार तैयार है। जहां पर कोई सुविधा है वहां पर और भी करने के लिए तैयार है। भरतपुर के विधायक भरतपुर के लिए कह रहे हैं इसी तरह से समाजवाद तभी आ सकेगा जब कि गरीबी को दूर किया जाएगा।

मैं सभापति महोदय, सीकर के बारे में कहना चाहता हूं। इलेक्शन में सीकर में सभी सेठ ही सेठ थे। कोई गरीब था ही नहीं। शिक्षा नहीं है इसीलिए यह कांग्रेसी महल रुका हुआ है। अभी लोग बोल रहे हैं कि हम सारे यंग आदमी कांग्रेस में आगये हैं। मुझे मालूम है इन्द्रिराजी का नारा है। नौजवान कांग्रेस में आये हैं। आखिर नौजवानों को अपने घर की ओर देखना चाहिये। आज स्कूलों और कालेजों में नकसलवादी नारे लिखे हुए हैं। यह डेफीनेशन राजा महाराजाओं के लिए बनाई है या सब के लिए बनाई है? इन्दिरा जी के होते हुए किशनगढ़ महाराजा की हत्या हो जाये। होम मिनिस्टर के होते हुए यह हो गया। उनकी हत्या हुई और ये होम मिनिस्टर बने रहे। हमारे विधायक, पृथ्वीसिंह, दलीपसिंह इसी प्रकार से मारे गये हैं। हम जानते हैं हमारे गवर्नर साहब पंजाब के हैं जहां आये दिन हत्याएं पंजाब में होती है। राजस्थान का भी हाल वैसा ही मालूम देता है। सिवा दांतारामगढ़ के और कौन सी जगह है जहां यह नहीं हुआ है वहां लोगों को ट्रेण्ड किया गया है। झुंझुनू और नागौर तो इनकी बपौती हो गई। नहीं जीते तो कहा कि मारो काटो। जब से विरोधी आने लगे हैं इन्होंने सोचा कि जाट राजपूत आपस में लड़ाई कर रहे हैं।

तो नागौर के अन्दर उस वक्त जोधपुर महाराजा के ऊपर पत्थर वर्षा हुई। दिल्ली

(श्री मदनसिंह)

के होम मिनिस्टर हैं उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी। उन्हीं चव्हाण साहब ने ऐलान किया मीटिंग में, जिसे वोट देने नहीं आना है उसका नाम काटो, यह कर दो। उनके लिए यह आवश्यक नहीं था किन्तु लोगों ने सिखाया कि राजस्थान में जाट राजपूतों में मेल है, कुछ हरकत करो कि जिससे अशांति हो, राजस्थान में शांति नहीं रहे। हम लोग पिट पिट कर मरे हैं, हम लोगों ने गोली खाई है लेकिन राजस्थान के विरोधी दल के हाथ से शांति भंग नहीं हुई है। अन्यथा आपने अपनी करनी में कसर नहीं रखी है। खैर चुनाव हो गया, आप जीत गये, लेकिन जीत कह कर मौजूदा सरकार इस अशांति को बढ़ाये नहीं। यह पक्षपात हैं, यह अनिश्चित पक्षपात है। जहां जहां के मंत्री हैं, जहां जहां उनके स्थान हैं वहां जीते हैं क्योंकि जो सही ढंग से प्रबन्ध करना था, वह किया। दूसरे विधायकों के क्षेत्र को देखें, विधायकों की कान्स्टीट्यूएन्सी में आपके वह वायदे ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हो सकता जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो। आपकी खुद की आदत रईसों से ज्यादा है। आपके घरों की शादियों को देख लें। मुझे बुरा लगता है कि मैं मंत्रियों के घरों की शादी के लिए कहूं लेकिन आपके यहां शादी कौनसे रईस से कम होती हैं। आपके लड़के बदमाश होते हैं जिस प्रकार कि रईसों के लड़के बदमाश होते हैं. हर काम में उनका मुकाबला करते हैं। दिल्ली में इन्दिराजी के राजकुमारों को देख लें और यहां पर मंत्रियों के राजकुमारों को देख लें। कौन से राजा-महाराजा ऐसा ऐश-ओ-आराम करते थे। आपको समाजवाद लाना है तो आप गरीब को टिकट दीजिये गरीबों को जहां दिया है, वहां हमने सपोर्ट किया है, वहां उसका प्रचार किया है और वहां बिल्कुल लाठी, पत्थर नहीं चले। आप शुरुआत कर देंगे तो मैं सच कहता हूं, इससे समाजवाद आयेगा। जो भैरोंसिंह जी ने कहा है, उसका आपने जवाब दिया है-लेकिन घोड़े की लात से घोड़ा मरता नहीं है। आप राजस्थान में जायं तो ऐसी स्थिति में कोई खड़ा होने वाला तैयार नहीं हो सकता कि कहीं लड़ाई न हो जाय। इसलिए जीवन में आदमी को उठाने के लिए काम करें।

इन बातों को छोड़ कर मैं अपने एरिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा राज्यपाल महोदय ने फौजियों के सम्बन्ध में, हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ कहा है। जहां तक हरिजनों और फौजियों को जमीन देने का सम्बन्ध है, उनको नहरी इलाके में जमीन मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था, इतने एकड़ जमीन हरिजन और फौजियों के लिए कैनाल एरिया में रखी है। गांव गांव के अन्दर, पंचायतों में आपस में लड़ मिट जायं लेकिन हरिजनों के लिए जमीन नहीं है कोई गोचर बताते हैं, कोई नाले बताते हैं। कोई गन्दी जमीन कहीं बाकी है वह कहीं कहीं बताते हैं। लेकिन उस पर भी कब्जा दर्ज करते नहीं। राजस्थान में हजारों मिसालें, हजारों केस ऐसे हैं जहां हरिजनों और फौजियों को जमीन एलाट हुई है लेकिन उसका कब्जा उनको नहीं मिला है। अगर कब्जा भी मिल गया है तो खड़ी फसल के खेत को लोगों ने छीन लिया है। अफसोस की बात है कि सीकर जिले में फौजियों, हरिजनों को जो जमीन मिली, उस पर

(श्री मदनसिंह)

उनका कब्जा हो जाने के बाद कलेक्टर ने रिश्तेदारी करके उस जमीन को गोचर भूमि घोषित कर दिया। इसका क्या इलाज हो सकता है? क्या हरिजन अदालतों में जायं? अगर अदालतों में जाएं तो क्या वह वकील रख सकते है इसी प्रकार फौजियों के लिए व्यवस्था की थी कि उनके लिए वकील रखेंगे, लेकिन क्या आज उनके लिए वकील हैं। केवल आंकड़े पूरे किये जाते हैं। हरिजन और फौजियों के लिये आपको व्यवस्था करनी है तो जैसा जागीरदारी के लिए बिल बनाया था वैसा बनाओ। जो हरिजन हैं जिनके पास में जमीन नहीं है उनकी आप लिस्ट बनायें और जो कैनाल एरिया में एक्स्ट्रा जमीन है, वहां उनको बसायें। हरिजन लोग कहते हैं कि जब हम दिल्ली में पार्लियामेन्ट में जा सकते हैं तो हम कैनाल एरिया में क्यों जायं, हम आजाद राजस्थान में पैदा हुए हैं, हम वहां अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आप चाहते हैं कि गरीब रहे, भूख रहे ताकि आप चुनाव में जीतते रहे। हर साल यह सरकार चाहती है कि गरीबी बनी रहे, अकाल बना रहे और सड़के वह गरीब लोग कूटते रहें, और आपके आफिसर उनका कान पकड़ कर चुनाव में वोट लेते रहें। यह चाहते हैं वो आप गरीबी को मिटा नहीं सकते हैं। आपको चाहिये कि जो नीचे हैं उनके समाज को आप इतना ऊपर उठायें कि वह लोग समान दर्जे तक आ सकें। इससे समाजवाद आ सकता है। लेकिन आपको तो कुर्सी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तो गवर्नर होकर मरूं, मैं तो प्राइमिनिस्टर होकर मरूं। इसमें नीचे रह कर कोई मरना नहीं चाहता। आपको चाहिए कि छोटे आदमियों की ओर आप देखें। मैं पिछले दिनों में चार सौ गांवों में घूमा हूं। मैंने वहां कहा कि आपने राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्जा मिलने का ऐलान पढ़ा है? आपमें से जिनको कर्जा मिला हो। वह हाथ उठाकर बतायें तो एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको कर्जा मिल हो। चार सौ गांवों में से बैंक से कर्ज मिलने का एक भी आदमी ने नहीं कहा। नाथूराम जी मेरी कानस्टीट्यूएन्सी में आये, वहां पर बैंक मौजूद हैं, हमने चला कर मीटिंग बैंक के नीचे रख ली। नाथूरामजी ने यह सुन कर कहा-यह अन्याय की बात है, रामगढ़ में बैंक है और वहां लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यह मोदी जी को अब मालूम हुआ है। मोदी जी, आपको मंत्री महोदय ने अंधेरे में रखा था। आप दांता रामगढ़ की तरफ गये तब आपको मालूम हुआ कि यहां अन्याय हो रहा है। तब मोदी जी मर्द की तरह खड़े हो गये। आप दांता रामगढ़ के गांव गांव में घूमे तो आप में ताकत आ गई और आप तेजी के साथ भाषण दे रहे हैं। एक बार दांता रामगढ़ में और घूम लें, आपकी शक्ति और बढ़ेगी। दांता रामगढ़ में चुनाव में एक पत्थर भी नहीं फिका। पुलिस की वहां जरूरत नहीं रही। लेकिन मैं पुलिस मंत्री को कहना चाहता हूं कि दांता रामगढ़ के थानेदार को दस दिन पहले आपने बदल दिया। मैंने कहा था कि यह नेक थानेदार है, चोरियों को पकड़ता है, चोरों को पकड़ता है। लेकिन आपने वोट प्राप्त करने के लिए उसको चेंज कर दिया। मोदी जी इस बात को मानते हैं कि वोट थानेदार के नाम से नहीं मिले तो वहां बड़ी मुश्किल हो गई। आपके पास वोट लेने का केवल नारा

(श्री मदनसिंह)
गरीब आदमियों को ऊंचा उठाना था जिसमें किसान, जाट, हरिजन, मीणा सब आ गये। लेकिन दांता रामगढ़ में कुछ हुआ नहीं है। मोदीजी चाहते हैं कि गरीबी मिटे, इसलिए हो वोट आपको मिले हैं।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : कितने हजार वोटों से हार गये थे आप अपनी कान्स्टी ट्यूएन्सी में ?

श्री मदनसिंह : पन्द्रह हजार मिलते हैं वह मैंने दिला दिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मोदी जी को दिला दिये।

श्री मदन सिंह : मेरे केन्डीडेट को।

श्री **जयकृष्ण** शर्मा : आप हरे होंगे पन्द्रह हजार से ?

श्री मदन सिंह : आप कह रहे हैं, 1 लाख 30 हजार की। वह मेरी जिम्मेदारी है नहीं। बहुत हारे हैं। उदयपुर में हारे हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप वहां की तारीफ कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : हर बार इतने वोट आये हैं। जो बात है उसकी तारीफ कर रहा हूं अलवर की तरह नहीं हैं कि जब कि कोई जीत गया, पहले कोई जीत गया

श्री जयकृष्ण शर्मा : 1962 में हारे थे।

श्री मदनसिंह : कहां कौन हारा था। सीट देकर हारा हूं। जगतसिंह को कहा, मंत्री बनोगे तो हट जाऊंगा। मैं दांता रामगढ़ एक दिन नहीं गया, लेकिन वह के वह सब वोट मिले। हम उनमें से नहीं है। हम हारे हैं तो और ताकतवर हुए हैं। लेकिन आपकी तरफ के जो आज तक नहीं हारे हैं वह हार गये।

आपको समाजवाद लाना है, तो आप निश्चित रूप से समाजवाद लायें। लेकिन यह खाली गाड़ियों से, बंगलों से और रईसी से कोई काम नहीं होने वाला है। इससे समाजवाद नहीं आने वाला है। इससे तो हुडदंगबाजी आ रही है। इससे देश में अशांति पैदा होगी। लोग कहते हैं कि देश में कम्यूनिज्म आयेगा। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि देश में अगर कम्यूनिज्म आयेगा तो जागीरदार साथ देंगे और कन्धे से कन्धा मिलाकर चलेंगे। लेकिन कौन लायेगा कम्यूनिज्म ? कम्यूनिज्म लाने का दम है। समाजवाद या कम्यूनिज्म इनसे नहीं आयेगा और नये पढ़े-लिखे लोगों के तबके से आये तो उस समय हम कन्धे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि कम्यूनिज्म आयेगा तो बड़े-बड़े महलों के दरवाजे टूटेंगे, दांता रामगढ़ का क्या लेगा कोई। कम्यूनिज्म रामानन्द जी से भी नहीं आयेगा क्योंकि उनके पेट्रोल पम्प है। कम्यूनिज्म से वह भी नष्ट होगा। तो जो इस सिद्धान्त को मानने वाले होंगे उनसे ही यह आयेगा और वे ही सेक्रिफाइस कर सकेंगे।

इसलिए निवेदन करना है कि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो समाजवाद नहीं आयेगा क्योंकि समाजवाद से आप खुद घबराते हैं। आपकी जीवन सोशलिस्ट नहीं है। आप सिर्फ भाषा कहते हैं सोशलिज्म। इसलिए वह तो सेक्रीफाइस से आयेगी। जैसे

(श्री मदनसिंह)

हमारी कान्सटीट्यूएन्सी है वहां सच्चे लोग भी पुलिस के हैं वह रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे मुख्य मन्त्री ने खुद ने हिदायतें दी हैं। प्रधान का चेक पकड़ा गया है। लेकिन वह केस आज भी एन्टीकरप्शन विभाग के पास दो साल से झुल रहा है। वहां के सरपंच जो कि आपके यहां से रुपया मिलता है तकावी का, वह 60-60 हजार रुपये खा गये। मय सबूतों से पकड़वाया है। न मालूम एन्टी-करप्शन को किसका फोन जाता है। लोग कहते हैं कि डी. आई. जी. चरित्रवान हैं, मैं भी कहता हूं कि वह चरित्रवान् हैं लेकिन सनकी हैं। नित प्रतिदिन लोग मर गये हैं। हम कैसे पकड़ रहे हैं। जिस गांव में वे लोग हैं नहीं। सरपंच रुपया उगाही करके दस्तखत करके खा गया। डी. आई. जी पकड़ता है। 1965 में पहले कर दिया और 1962 बाद में कर दिया यहां तक रेकार्ड हैं। एन्टी-करप्शन में पक्षपात है जब गृह मंत्री का इतना हाथ है। खुद डिप्टी होम मिनिस्टर ने 50 जगह लिखा। सरपंच दांता रामगढ़ के प्रधान हैं, चेक पकड़ा गया है, हां भर ली है। एन्टीकरप्शन ने कहा, हां करली इसलिए चोर नहीं होगा। जहां से रुपया उठाया गया वहां पकड़ा गया। सरपंच के दस्तखत हैं। वह आदमी ही नहीं है। फिर भी दो दो साल तक केस चल रहा है। उधर मदेरणा साहब नहीं बिराज रहे हैं। वहां कम से कम कहते हैं कि हम दिल में ईश्वर को रखते हैं। उनको हमने शिकायत की। प्रधान की पूरी गाड़ी चारों पहियों पर खड़ी हैं। स्टेरिंग है प्रधान का। चार हजार का सामान है। हमने आफिसर्स को बताया। सब ने कहा कि ऊपर से इशारा हुआ है, चुनाव में नहीं पकड़ेंगे। यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह जो आप चर्चा कर रहे हैं जब मांगें आएं तो कटौती प्रस्ताव के जरिये करें। इन्डिवीज्यूअल शिकायतों का जवाब नहीं मिल सकेगा।

श्री जुझारसिंह : सुन कौन रहा है।

श्री मदनसिंह : मैं चेलेन्ज करता हूं यदि यह बात सत्य न निकले।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मदनसिंह : इनको समाप्त करें तो अच्छा है। हम तो विरोधी दल में चलते रहेंगे। आज तक यदि कोई नेक अधिकारी आया है जिसके लिए गृह मंत्री से कहते हैं कि वह आ गया है, तो चुनाव के समय सबको हटा दिया। चोरों के साथ लगे हुए हैं। थानेदार कोई मोदीजी नहीं है। मीटिंग हुई है दांतारामगढ़ में, एडीशनल एस. पी. आए हैं। मीणों को बुलाकर कहा सारे केसेज हटा देंगे, वोट इधर मत दो चाहे ठाकुर साहब भी कहें। शर्म नहीं आई। मीणों को काबू करेंगे ? वे लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ऐसा पावर नहीं है कि चोरी करायेंगे। चोरी करेंगे तो शिकायत होगी, उसको ठीक करेंगे। सीकर जिले में सारे आफीसर्स रात रात को घूमे हैं। मजिस्ट्रेट घूमे हैं, एस. पी. घूमे हैं, फिर भी वोट दातारामगढ़ में नहीं मिले हैं न मिलेंगे। आज कम से कम पानी के लिए मेरे गांव में 18 हजार रुपए पानी के लिए जमा हैं। कोई योजना वहां पूरी नहीं करा रहे हैं। अभी वहां से मोदीजी जीते। वोट मिले। कहा दांता रामगढ़ से दिल्ली तक रेल गाड़ी निकालेंगे ? दांता रामगढ़ ऐसी

(श्री मदनसिंह)
जगह है कि वहां मंडी बने इसलिए कोई रेलगाड़ी निकलवाता है तो कोई पोल के लिए कहता है। बाहर की जनता ने 14 आने वोट दिए। जो वहां वाटर वर्क्स का आदमी है निष्पक्ष आफिसर है उस पर दबाव डाला जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है।

पिछले सत्र में मैंने शिकायत की थी कि मोदी मिल्स के खिलाफ 50 हजार के बिल्स आज तक पेंडिंग हैं। दांता रामगढ़ के आफिसर्स को चेंज कराया। उन्होंने कहा मोदी तबादला कराता था। इसके साथ रामदेव भी चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर के पास। दांता रामगढ़ जो चाहेगा वह करेगा। इसलिए आज तक वहां इतने बिल्स पेंडिंग हैं। अगर 10) रु. गरीब काश्तकार जमा नहीं कराता है तो उसकी बिजली बन्द हो जाती है, चक्की के 10) रु. पेंडिंग हैं तो बिजली बन्द हो जाती है लेकिन आज जो संसद के जो विधान सभा के सदस्य हैं, उनका रेकार्ड देखा जाए तो 50 हजार रुपए के बिल पेंडिंग हैं जिनको खाए बैठे हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं बिजली बन्द होती है। इसलिए समय आएगा सच्चे और गरीब उठ खड़े होंगे। उस समय सिफारिश नहीं चलेगी, जल्दी होगा। भारत की बाहर की जनता पोलिटिकली कान्शस है। इन्दिराजी के चुनाव को हम समझ रहे थे। गरीब नहीं समझ रहे थे। इसके रेडियो और हवाई जहाज चलते थे। उन्होंने कहा अमीर और गरीब की लड़ाई है। अब एक साल है, एक साल के अन्दर...

श्री जूझारसिंह : दो महीने।

श्री मदनसिंह : एक साल। इन्दिराजी के वोट पर आप जीत जायेंगे। आपने जहां जहां विश्वास दिलाया है, वहां कार्य शुरू होना चाहिए। चाहे शिक्षा का चाहे दवाखाने का। हमारे मोदीजी दूअर में गए तो तीन गांव ऐसे थे जहां विश्वास दिलाया कि आपके यहां औषधालय खोले जायेंगे...

श्री सभापति : राज्यपाल के अभिभाषण में मोदी का क्या जिक्र था ?

श्री मदनसिंह : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चिकित्सा का कहा है।

श्री सभापति : मोदी करता था ?

श्री मदनसिंह : मंत्रीजी (श्री जय-कृष्ण शर्मा): जो सुन रहे हैं वहां जाकर दूसरे वैद्य भेजे थे जो परमानेन्ट थे ·

श्री जय कृष्ण शर्मा (आयुर्वेद राज्य मंत्री): कहां जाकर भेज दिया ?

श्री मदनसिंह : सुनो तो। अभी तीन गांव ऐसे थे जहां आपने आर्डर किया था कि परमानेन्ट वैद्य जायेंगे। तीनों के आर्डर हुए कि वोट नहीं दिए तो...

श्री जय कृष्ण शर्मा : कहां ?

श्री मदनसिंह : एक तो नीनथा गांव है।

श्री जय कृष्ण शर्मा : आपको झूंठ बोलने की आदत पड़ गई है। आप झूठ बोलते रहते हैं, आपको आदत है ना ? तथ्य पर आधारित नहीं है। केवल सदन में दिखावे के लिए कि अच्छा बोलने वाले हो जो मर्जी आए बोलते हो। अपना अधिकार मानकर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
बैठे हो। ऐसा अधिकार नहीं है कि जो चाहे बोलो दूसरे लोगों के लिए। आपने जो कहा है वह असत्य पर आधारित है। यह नहीं कहना चाहिए।

श्री मदनसिंह : अगर यह बात सही न हो कि आपने नए कैंप खोले हैं तो स्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने कहा औषधालय खोले हैं, मंत्री के आर्डर्स हैं। मैंने न औषधालय खोले हैं न चिकित्सालय के आदेश दिये हैं। आपने पहले भी स्तीफा दिया था और फिर ...

श्री मदनसिंह : आप लोगों ने पैर पकड़े।

श्री जयकृष्ण शर्मा : तुम्हारे पैर और लोग पकड़ते होंगे। हमने तो न पकड़े हैं न पकड़ेंगे।

श्री मदनसिंह : आपके ब्राह्मण होने की वजह से हमारी बीवियों ने पैर पकड़े होंगे। बीवियों का नाम लेंगे तो पर्दा भी खोल दूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप कहते हैं कि हमने पैर पकड़े हैं हमने जिंदगी में न पकड़े हैं, न पकड़ेंगे।

श्री मदनसिंह : मैं चेलेंज स्वीकार करता हूं। चुनावों के बीच में इन्होंने वैद्य भेजे हैं और इसलिए भेजे हैं कि वहां के वोटर्स को मनाया जाए। कैंप खोले हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मदनसिंह : अब मैं बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। छोटे छोटे उद्योग जहां बिजली खुद पैदा करना चाहते हैं आज काश्तकार या अन्य लोग खुद पैदा करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यदि छोटे तबके के पास हो तो वह कोई चीज घोल कर पीयेगा नहीं। वह तो छोटी मोटी चीज ही खरीदेगा। ट्रान्जीस्टर खरीदेगा और कुछ खरीदेगा। बड़े पूंजीपति फैक्ट्रियों में लगायेंगे। उद्योग धन्धे वहां होने चाहिये जिससे कि गरीब तबका काम कर सके और बीच की श्रेणी के व्योपारी खरीद सकें। विधायक की हैसियत यहां बोलने की है। झूठे की उपाधि दी तो वह तो समय आने पर ही पता चलेगा कि कौन क्या है। मेरी सच्चाई मेरे साथ रहेगी और आपकी आपके साथ। झूठ और सत्य का फैसला समय कर देगा।

यही मंत्री यह कहते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब जब तक नहीं दें तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। मंत्री लेवल पर भी उनको बताना चाहिये। फिर किस लिये बैठे हैं ? राजस्थान सरकार सुविधा देती है कानून के अन्तर्गत तो रेवेन्यू सैक्रेटरी के लेबल पर यह स्थिति नहीं होनी चाहिये फौजी आगया तो क्या खुदा आगया यह कहते हो। लेकिन फौजी को खुदा तक मानते हो जब उनके काम पड़ता है। आपने ही यहां जाकर कहा था। फौजी आपके पास मांगने नहीं गया था। आपके प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोग गये थे। उनको कहा कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फौजी लोग तो लड़ने और मारने के लिये हैं। प्रधान मंत्री का

(श्री मदनसिंह)

तो हक है। फौजियों और नीचे के तबके के लोगों के लिए ऐसी वैसी बातें न करें।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में समाजवाद की कोई रूपरेखा नहीं बताई न गवर्नमेन्ट ने ही कोई समाजवाद की बात रखी। इससे तो प्रेसिडेन्ट फार्म आफ गवर्नमेन्ट अच्छी है। अपने ढंग की व्यवस्था और मिनिस्टर। किसी को ओलंभा तो दे सकते हैं। न जाने कहां से वह लाये। प्रेसिडेण्ट को पावर दुनिया से ज्यादा बढ़ा दी लेकिन एग्जीक्यूशन प्रधान मंत्री की मर्जीपर। प्रेसिडेन्ट को कुछ करने धरने के अधिकार नहीं। प्रेसिडेन्ट की मिट्टी पलीत हुई जब राजाओं का प्रिवीपर्स खत्म किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। प्रधान मंत्री को यह पता ही नहीं कि प्रिवीपर्स को बन्द कर सकते हैं या नहीं।

होम मिनिस्टर साहब के साहिबजादे खुद समाजवाद की बातें कर रहे थे। होम मिनिस्टर के बंगले के पास गरीब पड़े हुए हैं. उनको रोटी तो मिलती नहीं, न मकान मिलता और उनके राजकुमार साहब नारा लगा कर सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गरीबों का काम कर रहे हैं। वकालत की फीस ही छोड़ दो, करना चाहते हो तो। गरीब आता है तो 5 कदमों की उनसे फीस लेते हैं और यहां समाजवाद का नारा लगाते हैं और वहां कहते हैं कि पैसा नहीं दोगे नहीं लडूंगा। नेहरू जी और इन्दिरा जी का यह त्याग था इसलिए अब के जीते। 72 के चुनाव में नहीं आ सकते।

श्री सभापति : श्री राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय....

श्री जगन्नाथ पटेल : सभापति महोदय, सदन का अब अधिक समय नहीं बढ़ाया जाय। सदस्यों को सदन में आकर राष्ट्रीय ड्यूटी देनी चाहिए थी।

श्री देवेन्द्र कुमार : सभापति महोदय,

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा था।

श्री देवेन्द्र कुमार (गोगुन्दा सु.) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना। आज देश में गरीब के प्रति जो भावना जागृत हुई हम सब उनको जानते हैं।

सभापति महोदय, हमारी प्रधान मन्त्री ने इस देश के अन्दर समाजवाद का नारा लगा कर देश के अन्दर गरीबों में एक जागृति पैदा की। इस ओर गरीबों का ध्यान गया है। जो नारा लगाया है उसको सच्चे रूप में पूर्ण करना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं आपके मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे उदयपुर में ऐसे क्षेत्र हैं कि चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में हजारों आदिवासी पड़े हुए हैं। कांग्रेस के शासन में उनके अन्दर शिक्षा की थोड़ी जागृति हुई। उनकी आर्थिक हालत तो आज भी बहुत कमजोर है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि उन गरीब आदिवासियों की आर्थिक हालत को सुधारना है तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में छोटे 2 एनीकट बनाने पड़ेंगे, उनमें पानी रहे और उससे जमीन की

(श्री देवेन्द्रकुमार)
सिंचाई हो। साथ ही सरकार को कुए खुदवाने पड़ेंगे। वे कई सदियों से पिछड़े हुए हैं। राजस्थान के इन आदिवासियों की हालत देश के दूसरे स्थानों से बहुत पीछे है।

शिक्षा के माने में उनमें जागृति पैदा हुई है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों की सर्विस के बारे में साढ़े अट्ठाईस प्रतिशत नौकरी देने का नियम बनाया है।

सभापति महोदय, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। मैं आज यह देखता हूं कई आदिवासियों के लड़के नौकरी के लिए ठोकरें खाते हैं। उनको नौकरी नही मिलती है। आपके कानून इन कागजों में पड़े हुए हैं और गरीब तबका रोटी के लिए महरूम है।

श्री देवेन्द्र कुमार : मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आदिवासियों की हालत सुधारी नहीं गई तो हमारे ये आदिवासी लोग बहुत पीछे रह जावेंगे।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय दस मिनिट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा रायसिंह) : यह क्या बात हुई। आज त्योहार का दिन हैं, हम जल्दी जाना चाहते हैं। आप समय बढ़ाते जा रहे हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवेन्द्र कुमार : तो सभापति महोदय।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापतिजी, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर उनको सन्तोष तो कराइये।

श्री सभापति : मुझे क्या आपत्ति है। सदन की इच्छा हो तो।

श्री किशनलाल वर्मा : अगर इनको समय दिया गया तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। समय आपको और बढ़ाना होगा।

श्री देवेन्द्रकुमार : आदिवासी एरिया के लोगों को जागृत करने के लिए प्रधान मन्त्री ने जो आवाज उठाई है उसको पूरा करना होगा। आज इनकी हालत सुधारनी होगी, नहीं तो बहुत पिछड़ जावेंगे।

सरकार को किस बात का डर है। सीलिंग का कानून बनाया। जमीन उनसे लेकर गरीबों को देनी होगी। गरीब लोगों को टूटी फूटी झोंपड़ियों को सम्भालना होगा। नहीं तो आने वाले जमाने की हवा को आप रोक नहीं सकेंगे।

हमने समाजवाद का नारा लगाया।

(गणपूरक घंटी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि समाजवाद का नारा लगाया गया। गरीब लोगों की यह भावना रहती है कि हमारी आर्थिक हालत सुधरे। उसे ठीक करने की कोशिश की जाय।

मैं सभापति महोदय, आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में अभी बहुत कुछ करना है। सरकार इस

(श्री किशनलाल वर्मा)
बारे में जो कुछ करती है, पक्षपात से करती है। गांवों में अगर स्कूल कालेज हाई स्कूल कुछ भी खोलने की बात आवेगी तो कहेंगे कि गांव वाले चन्दा करें और उसके लिए भवन बनावें, श्रमदान करें जबकि शहरों में एक पैसा स्कूल, हाई स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी खोलने के लिए नहीं मांगती। गांव और शहर में इस तरह का भेदभाव क्यों ?

यह भेदभाव सरकार को मिटाना पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में इतना पैसा कहां है। फर्नीचर भी आप हमें लगाने के लिए कहते हैं। समान अधिकार होना चाहिये। दुख की बात है कि मेरे एरिया में किसी तरह चालीस हजार रुपया लगाकर स्कूल बनाई लोगों ने और उदयपुर में स्कूल खोलते हैं तो एक पैसा नहीं मांगते। यह ऊंच-नीच की भावना उचित नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र कुमार: तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से भेद-भाव नहीं बरता जावे।

गरीब सिपाहियों की तनख्वाह आप नहीं बढ़ावेंगे। जमीन अलाटमेंट करने में आप गरीबों का खयाल नहीं करते, प्लाट अलाट करते हैं तो गरीबों को नहीं मिलते। तो यह निवेदन करना चाहता कि देश की रक्षा करने वाले हैं उनको हर बात की सुविधा दीजिए। छोटे कर्मचारियों को सुविधा दीजिए जिनकी तनखा थोड़ी है उनको सुविधा दीजिए। आप क्या करते हो, उनकी तनखा बढ़ाने का मामला आता है तो आप उनकी बढ़ाते हैं पांच रुपया दो रुपया एक रुपया और जिनको पांच सौ मिलता है या हजार मिलता है उनको बढ़ाते हैं सौ रुपया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह भेद-भाव न करें। छोटों का वेतन बढ़ावें ताकि वे अपने बाल बच्चों का पालन आसानी से कर सकें। अपने बच्चों को लिखा पढ़ा सकें और अच्छा खिला पिला सकें। रहने के लिये आवास का प्रबन्ध कर सकें।

मैं इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय सु.): सभापति महोदय, ····

श्री सभापति: पांच मिनिट में आप अपना भाषण दे दें।

श्री किशनलाल वर्मा: राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसका मैं स्वागत करता हूं।

चुनाव शांति पूर्ण हुए। वैसे मैंने देखा कि स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से पैसे पाने वाले सेठ साहूकार खड़े हुए तो काफी पैसा नाजायज तौर पर रिश्वत के रूप में लोगों में लुटाया गया। जगह जगह शराब पिलाई गई। ऐसे आयोजन किये गये। ठीक नहीं है आज के दिन कि पैसे वाले इस प्रकार लोगों से वोट हासिल करें। इसलिए जरूरी है कि इस तरह जिनके पास ज्यादा पूंजी है, उसको खत्म किया जावे किसी तरह से।

इसके लिए पूंजीपतियों को पूंजीवाद को खत्म करना आवश्यक है। समाजवाद के लिए यह जरूरी है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो करीब 428 लाख रुपये का ऋण दिया गया है

(श्री किशनलाल वर्मा)

काश्तकारों को और दूसरे मजदूर वर्ग और छोटे व्यापारी वर्ग को, उस का स्वागत करता हूं पर फिर भी लोन मिलने में काफी कठिनाई होती है। परेशानी होती है। नया व्यापार करने वाले को पैसा नहीं मिल पाता आसानी से। और जो पैसा मिलता है वह बहुत थोड़ा होता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अधिक से अधिक इस बैंक के ऋण का लाभ छोटे लोगों को मिले।

अभी तक समाजवाद के नाम से जो काम किया गया वह थोड़ा किया गया। नहीं के बराबर हुआ है। इन्दिराजी ने नया नारा लगाया है। वे नई चेतना और नई जागृति लाना चाहती हैं। तो राजस्थान में भी बताना चाहता हूं कि हमें समाजवाद के लिए ठोस काम करना होगा। कोरे थोथे नारों से समाजवाद नहीं आ सकेगा, अगर नारों से आता होता तो अब तक आ गया होता। समाजवाद के लिए देश के लोगों को पूरी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से काम करना होगा। सच्चे दिल और दिमाग से काम करना होगा, नहीं तो काम अब नहीं चलेगा। केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए वोट हासिल करने के लिए समाजवाद का नारा हम लगाते रहे और ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं किया तो अब जनता हमें माफ नहीं करेगी और ये कुर्सी, ओहदे और बंगले कारें भी नहीं रहेंगी।

आज हमें भ्रष्टाचार को भी हर स्तर पर समाप्त करना होगा। भ्रष्टाचार के शिकार जो होते हैं वे गरीब होते हैं। छोटे काश्तकार और मजदूर लोग होते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही दिनांक 22 मार्च, 71 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 10 मिनट पर दिनांक 22 मार्च, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची)

LIST OF THE TUBE-WELLS CONSTRUCTED IN BARMER DISTRICT DURING 1968-69 to 1970-71

S. N.	Name of the party	Discharge	Utilisation
1968 69			
1.	M. E. S. at Gadraroad	2500	
2.	Exe. Eng. Project at Satho		
3.	Famine work at Dharvi	1000	PHED for water supply.
4.	Famine work at Kotra	5000	PHED for water supply.
5.	Famine work at Ratri	11500	Irrigation.
6.	Famine work at Sajeetra	5000	PHED for water supply
7.	Famine work at Doli	1500	PHED for water supply.
8.	Famine work at Padru-I	18000	Irrigation.
9.	Famine work at Dhori-mana	5000	PHED for water supply.
10.	Famine work at Lahrwa	10000	Irrigation
11.	Padru-II (G.S.I.)	27200	Irrigation
12.	Bhimda (E.T.O.)	10750	PHED for water supply.
1969-79			
13.	Famine Relief works at Bithuja		PHED for water supply.
14.	D. S. N. Rly. at Samdari		
1970-71			
15.	Exe. Engineer PHED T/W Division Jodhpur village Bhimda No.-II	16000	PHED for water supply.
16.	Exe. Eng. PHED Jodhpur worked at Undu	8000	PHED for water supply.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 46 की सूची)

उद्योगपतियों का नाम जिन्हें कर्ज दिया गया	कुल कर्ज जो दिया गया	कुल रुपया जो उद्योगपतियों में बाकी है अथवा ड्यू है		वसूली योग्य राशि अथवा ड्यू कितने सालों से बाकी है
1	2	3		4
		मूल	ब्याज	
1. जयपुर उद्योग लिमिटेड	60,00,000.00	10,00,000.01	12,000.00	नवीं किश्त एक वर्ष पुरानी है मूल 3,33,333–33 व ब्याज बाकी है किश्त की अवधि 2-1-70 से 1-1-71 है।
2. जयपुर उद्योग लिमिटेड	12,00,000.00	6,50,000.00	87,750.00	आठवीं किश्त रु. 2,00,000/– की अवधि 2–7–67 से 1–7–68 नवीं किश्त रु. 2,00,000/– की अवधि 2–7–68 से 1–7–69 दसवीं किश्त रु. 2,50,000/– की अवधि 2–7–69 से 1–7–70 व ब्याज अर्थात तीन से एक वर्ष पुरानी किश्तें बाकी हैं।
3. विजय नगर शुगर मि. लिमिटेड	3,84,546.48	3,84,546.48	2,64,375.00	यह रुपया 11 वर्ष से बाकी है अवधि 21-11-59 से 21-11-70

1	2	3		4
4. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	50,51,712.32	15,15,513.71	—	समय पर किश्त का ब्याज प्राप्त हो रहा है।
5. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	60,00,000.00	36,10,347.25	—	,,
6. कमानी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	4,61,174.65	4,61,174.65	—	पूरी भूमि अवाप्त न होने के कारण अभी मूल रुपयों की किश्त नहीं बांधी गई है।
7. जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड	50,00,000.50	30,00,000.00	—	समय पर किश्त व ब्याज प्राप्त हो रही है।
8. जयपुर उद्योग लिमिटेड	25,00,000.00	25,00,000.00	—	पहली किश्त 12,50,000/– की दिनांक 31–3–71 तक जमा होनी है अतः इस समय यह बाकी नहीं है।
9. महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड	4,50,000.00	4,50,000.00	—	ब्याज कम्पनी ने दे दिया है मूल रकम एक लाख रुपये की अभी प्राप्त होनी है।
10. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	50,00,000.00	39,92,368.80	—	समय पर किश्त व ब्याज प्राप्त हो रहा है।
11. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	25,00,000.00	22,50,000.00	—	,,
12. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	,,	25,00,000.00	—	अभी कोई किश्त ड्यू नहीं हुई है।
कुल योग	3,70,47,433.45	2,23,13,951.00	3.64,125.00	

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक आवंटित किये गये विभिन्न प्रकार के ट्रेक्टरों की जिलेवार सूची।

जिला	जीटर (2011)	बेलारस	डी. टी. -14	जर्मन आर. एस.-09	रूमानियन
अजमेर	4	2	1	1	1
अलवर	9	6	–	12	14
बांसवाड़ा	4	1	–	–	1
बाड़मेर	4	2	–	–	1
भरतपुर	9	5	–	28	29
भीलवाड़ा	7	3	1	–	8
बीकानेर	3	1	2	1	9
बूंदी	1	2	–	1	3
चित्तौड़गढ़	6	4	4	6	5
चूरू	3	2	1	–	15
डूंगरपुर	2	–	–	–	–
गंगानगर	11	10	2	4	104
जयपुर	13	12	9	23	52
जैसलमेर	5	1	–	–	3
जालोर	5	1	–	–	7
झालावाड़	3	2	–	–	–
झुन्झुनूं	3	1	–	3	3
जोधपुर	5	1	1	3	12
कोटा	6	3	1	5	1
नागौर	6	3	1	3	16
पाली	3	3	–	2	14
सवाई माधोपुर	8	4	1	4	9
सीकर	7	3	–	3	7
सिरोही	1	1	–	–	1
टोंक	5	1	–	2	1
उदयपुर	9	4	–	2	1
	142	78	24	103	317

कुल योग—664

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1971)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	9	विरास्तन	विरासतन
6	10	बिमारियां	बीमारियां
7	अन्तिम से 11	इन्डीज्युअल	इन्डवीज्युअल
,,	,, 3	करातेहूं	करतो हूं
13	,, 3	श्री वृद्धिचन्द्र जैन: (बाड़मेर)	श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :
14	,, 4	इन कुओं से पानी लेकर काश्त करना चाहें तो हम	
16	,, 10	लिलो	लिखो
17	,, 10	(2) जो हैं	(2) जो हां
20	14	मिलना	मिलनी
,,	अन्तिम से 6	दवाइय	दवाइयां
,,	,, 5	अजमें	अजवाइन
23	,, 14	श्री उद्योग मंत्री	उद्योग मंत्री
26	1	प्लान	प्लान्ट
27	10	श्री लादूराम सुलानिया (फाग) :	श्री लादूराम सुलानिया (फागी) :
39	अन्तिम से 9	तल	तेल
42	,, 5	नहीं	नहीं
45	,, 10	मह	यह
60	9	नहीं नहीं	नहीं
71	शीर्षक	क	के
78	अन्तिम	इसे	से
85	,, 7	नहा	नहीं
93	9	शान्तिर्ण	शान्ति पूर्ण
94	अन्तिम से 5	नहा	नहीं
96	15	इनकार	इन्कार
,,	16	में	ने
,,	20	कम्पनी	कम्पनियों
125	18	एक्मुलेट	एक्यूमुलेट
129	अन्तिम से 16	तरह	तरफ
,,	,, 13	केदंगे फसाद	दंगे फसाद
130	3	के	की
132	13	वह	यह
149	अन्तिम से 9	दरखवात	दरख्वास्त
165	4	सदाय	सदस्य
178	15	श्री नुरेन्द्र कमार व्यास	श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास

1	2	3	4
179	6	भा	भो
182	अन्तिम	अ	और
188	अन्तिम से 11	मोलत	मोहलत
193	शोर्ष	श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)	(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)
196	अन्तिम से 11	झुटो	झंटी
199	,, 6	ग	गये
201	9	सीतराम जी को भार	शोशराम जी को मार
203	अन्तिम से 6	कते	करते
204	10	लडई	लडाई
206	9	मिल	मिला
207	2	रीब	गरीब
,,	15	हुरे	हारे
210	शोर्षक	वद विवाद	वाद विवाद
,,	1	श्री सभा ा ति	श्री सभापति
212	5	टूअर	टूर
219	शोर्ष	(श्री किशनलाल वर्मा)	(श्री देवेन्द्र कुमार)

———